

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

15 मार्च, 1994

खण्ड 1, अंक 9

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार, 15 मार्च, 1994

	पृष्ठ संख्या
भाोक प्रस्ताव	(9)1
स्थगित तारांकित प्र न उत्तर	(9)2
तरांककित प्र न एवं उत्तर	(9)6
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखा गया	(9)22

तारांकित प्रश्न का लिखित उत्तर	
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(9)23
कथित विशेषाधिकार भंग का प्रश्न	(9)24
ध्यानकर्षण सूचनाएं	(9)29
ध्यानकर्षण प्रस्ताव	—
भिवानी भाहर में पीलिया का रोग फैलने संबंधी	(9)34
वक्तव्य—	
स्वास्थ्य एस आयुर्वेदा मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी	(9)35
वर्ष 1994—95 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(9)39
बैठक का समय बढ़ाना	(9)88
वर्ष 1994—95 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान बैठक का समय बढ़ाना (पुनरारम्भ)	(9)89
बैठक का समय बढ़ाना	(9)92
वर्ष 1994—95 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(9)92

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—	
श्री धर्मपाल द्वारा	(9)97
वर्ष 1994—95 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(9)98
बैठक का समय बढ़ाना	(9)99
वर्ष 1994—95 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(9)99
बैठक का समय बढ़ाना	(9)105
वर्ष 1994—95 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(9)106

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 15 सितम्बर, 1994

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1 चण्डीगढ़ में प्रातः 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ई वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

भाोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब मुख्य मंत्री जी अबुचरी रेफरेन्स करेगे।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, यह सदन महात्मा गांधी जी की पौत्री श्रीमती मनुबैन सुरेन्द्र भाई मधुबाला जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, के 13 मार्च 1994 को हुए दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है। उनकी समाज सेवा व धार्मिक कार्यों में गहरी रूची थी। उनके निधन से दे । एक सामाजिक कार्यकर्ता की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

प्रो० सम्पत सिंह (भट्टकला): स्पीकर सर, हाउस के नोत व विपक्ष के नेता ने जो भाोक प्रस्ताव यहां हाउस में रखा है, मैं भी अपने आप को उसमें शामिल करता हूं और भाोक प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। स्पीकर सर, मेरी हाउस के नेता से यह भी

प्रार्थना है कि श्री रतीराम भार्मा, जो पब्लिक सर्विस कमिशन के मैम्बर रहे हैं, वे भी स्वर्गवास हो गए हैं और अगर उनका नाम भी इस भाग के प्रस्ताव के साथ जोड़ दिया जाए तो अच्छी बात है।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I associate myself with the feeling expressed by the leaders of the different parties. Smt. Manubai Surender 'Bai', महात्मा गांधी जी की पौत्री थी और महात्मा गांधी राष्ट्र के पिता थे। उन्होंने अपनी पूरी भाक्ति लगाकर देश को आजाद करवाया। अंग्रेजी प्राईम मिनिस्टर चर्चिल ने एक दफा कहा था कि मैं महात्मा गांधी के घुटने दिका दूंगा तो उस वक्त पास में बैठे हुए दसेर स्टेट्समैन ने कहा कि नहीं, आप उनके घुटने नहीं टिका सकते, वे आपके घुटने टिका सकते हैं। इसके बाद जब चर्चिल ने कहा था I have not become the Prime Minister of England to liquidate the British Empire. वह ब्रिटिश एम्पायर महात्मा गांधी जी ने ही लिक्वीटडेट कराया। भारत आजाद हुआ और उसके साथ सभी देश, जो अंग्रेज के गुलाम थे, सभी आजाद हुए वन बाई वन। तो मैं भी, हाउस के नोता ने जो भाग के प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करते हुए आप सभ्यता के साथ एसोसिएट करता हूँ और जो हाउस की फीलिंगज होगी, उनको ब्रीवड फैमिली तक पहुंचा दूंगा।

अब मैं सब से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा के प्रति दो मिनट खड़े होकर मौन धारण करें।

(इस समय सदन ने दिवंगत के सम्मान में दो मिनट खड़े होकर मौन धारण किया)

स्थागित तारांकित प्र न एव उत्तर

Mr. Speaker: Hon'ble Members, before we start question enlisted for today, the postponed starred question NO. 663 enlisted in the name of Prof. Chhattar Singh Chauhan, M.L.A will be first taken up.

Plantation of Trees

663. Prof. Chhattar Singh Chauhan: will the Minister for Forests be pleased to state the district wise number of trees planted during the period from July, 1992 to date in the state?

Forest Minister (Rao Inderjit Singh): Sir, statement is placed on the table of the House.

Statement

Sr No.	Name of District	Total tress planted from July, 1992 up to 31-01-94
1.	Ambala	21286468
2.	Yamuna Nagar	13962515
3.	Kurukshetra	6146878

4.	kaithal	5045872
5.	Karnal	7668472
6.	Panipat	4142731
7.	Sonipat	6731632
8.	Gurgaon	13477548
9.	Faridabad	7195494
10.	Mohindergarh	10417127
11.	Rewari	6954880
12.	Rohtak	10195207
13.	Bhiwani	12299879
14.	Hisar	14929925
15.	Jind	5633975
16.	Sirsa	11050112
		157138715

प्रो० छतर सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बतलाने का कष्ट करेगे कि जो लिस्ट जुलाई 92 से 31.01.1994 तक की इन्होंने दी है, उनमें से कितने वृक्ष जिलावाइज सरवाइव कर रहे हैं और कितने खत्मक हो गये हैं? इसके साथ साथ में मंत्री महोदय से यह भी कहूंगा कि जितने वृक्ष वे आगे लगवा रहे हैं उनमें कम से कम कीकर के वृक्ष न लगवाएं। राव

साहब खुदतो भायद किसान नही हैं लेकिन वे किसान परिवार से सम्बन्धित जरूर है। मैं उनको यह बतलाना चाहता हूँ कि कीकर के वृक्ष लगवान से आधा-आधा एकड़ जमीन बिल्कुल नष्ट हो जाती है। ओर उस जमीन में कोई फसल नहीं होती तथा उसका मुआवजा भी किसानों को नहीं मिलता।

इसके अलावा मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ कि जो दरख्त गिराये जा रहे हैं, क्या सरकार पिछली सरकार की नीति के अनुसरण करते हुए, उन दरख्तों को आमदनी का आधा हिस्सा किसानों को देने का इरादा रखती है?

राव इन्द्रजीत सिंह: स्पीकर साहब, नवम्बर, 1991 में गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से हमारे यहां एक टीम आई थी। उस समय हमारी स्टेट प्लांटे इन करचुकी थी। उन्होंने अपनी तरफ से जो उसकस ब्यौरा दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हरियाणा का सक्सैस रेट 80 प्रति एअर से ऊपर है। वैसे हमारा जो निजी मीनिट्रिंग सैल है। जो सो एल फारैस्टरी में करनाल ओर अरावली में रखा हुआ है, उसके हिसाब से इनका सक्सैस रेट 60-70 प्रति एअर है। दूसरी बात उन्होंने कही कि कीकर के पेड़ ने लगाए जाए। स्पीकर साहब, कई किस्म के पेड़ लगाए जाते हैं। एक बात तो मैं भी मानता हूँ कि कीकर के पेड़ के नीचे फसल ठीक ढंग से नहीं होती। लेकिन माननीय सदस्य यह बातभी मानंगे कि गांव वाले फयूल के तौर पर कीकर की लड़की को इस्तेमाल करते हैं। अगर कीकर का पेड़ ने हो तो वे अपना कुलहाड़ा दूसरे

पेड़ों पर चलाएंगे। हमारी फयूल की जरूरत को वही पूरी कर सकता है। इसलिए उसका लगाना जरूरी है। जो अब तक पेड़ का हिस्सा किसान को देने की बात है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि पिछली सरकार की नीति में यह था कि कुछ परसेंट हिस्सा किसानों को दिया जाएगा। उसका फायदा उठाते हुए किसानों ने अपने खेत के साथ लगते पेड़ों के अलावा सड़क के साथ लगते हुए पेड़ भी काट लिए। तो इनकी नीति के हिसाब से खेत के साथ लगने वाले पेड़ों का हिस्सा उनको जाना चाहिए था लेकिन उन्होंने सारे पेड़ ही काट लिए। इसलिए हमने उस नीति को लागू नहीं किया।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, क्या मंत्री जी बताएंगे कि जिस तरह से कीकर का पेड़ नुकसानदायक है, इसी तरह से सफेदे का पेड़ भी खेती के लिए और सब सायल पानी के लिए लाभदायक नहीं है। दूसरे आपने जो पेड़ों का सरवाइवल रेट बताया है, क्या इसका हर साल सर्वे करवाते हैं, अगर हाँ तो इससे कितनी सच्चाई है?

राव इन्द्रजीत सिंह: स्पीकर साहब, सफेदे के पेड़ के बारे में काफी डिबेट हुई है। कि बेहतर किस्म को पेड़ है या नहीं, क्या यह वाहे पर लग सकता है जहाँ पानी की कमी है? स्पीकरसाहब, सफेदे के पेड़ की जड़ दस फुट तक सब-सायल पानी होता है, इसलिए सब-सायल पानी को यह खराब नहीं करता। उन्होंने जो कहा कि सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कहां तक

सच्चाई है या नहीं, उसके लिए हमारी हरियाणा सरकार ने मौनिट्रिंग सैन बना रखे है। एक करनाल के अन्दर है ओर एक गुडगांव जिले में है। इनके अनुसार 60-70 प्रति अत सक्सैस रेट हैं हम बाकायदा 60-70 परसेंट मंथ टू मंथ, ईयर टू ईयर सक्सैस रेट का सर्वे करते रहते है। स्पीकर साहब, हमारे प्रदेश में भारत सरकार की ओर से सर्वेक्षण टीम आई थी, उन्होंने सर्वे के बाद यह बताया कि हरियाणा के अन्दर 80परसेंट सक्सेट रेट है

श्री सतबीर सिंह कादयान: स्पीकर साहब, चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने किसान के खेत से 10 फुट तक दुरी के पेड़ों में किसानों को आधा हिस्सा देने का प्रावधान कियाथा। इसलिए मैं मौजूदा सरकार से यज जाननाचाहता हूं कि पिछले दो साल में किसानों को पेड़ों में कितना हिस्सा दिया गया है? इसके साथ साथ मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि असंध ग्राम पंचायत ने जो एक हजार एकड़ जमीन ट्री प्लांटे इन के लिए सरकार को दी है, उसमें कब तक ट्री प्लांटे इन करवा दी जाएगी। क्या वह जमीन पंचायत को वापिस कर दी जाएगी। अरग वापिस की जाएगी तो कब तक की जाएगी?

राव इन्द्रजीत सिंह: स्पीकरसाहब, किसानों को पेड़ों में हिस्सा देने के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि वह नीति अब लागू नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पिछली सरकार ने क्या यह नीति लागू की थी?

राव इन्द्रजीत सिंह: स्पीकर साहब, पिछली सरकार ने सारे पेड़ कटवा दिए थे।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, आज सारी दुनिया इस बात से चिन्तित है कि वायुमंडल को कैसे भुद्ध रखा जा सकता है, दूषित वातावरण से मानव को कैसे बचाया जा सकता है? मानव को दूषित वातावरण से बचाने की बात पेड़ों से ही हो सकती है। पेड़ ही मानव को दूषित वातावरण से बचा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने बैठे विरोधी पक्ष के भाईयों ने तो रास्ता रोकने के नाम से पेड़ों को काट-काट कर सकड़कों पर डाल दिया था और लोगों को कह दिया था कि हमारी पार्टी की सरकार आते ही आप सारे पेड़ काट लेना, जो सरकारी पेड़े उनमें भी आपको आधा हिस्सा मिलेगा। ये लोग इस तरह की बात करते हैं। लोगों को कर्जा माफी की बात कह करके उनको गुमराह करते हैं और लोगों से वोट ले कर गद्दी पर बैठे, क्या लोगों को कर्जा माफ हुआ? उनका कर्जा माफ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने कर्जा माफी को जो पालिसी बनाई, क्या वहा लागू हुई? ऐसी पालिसी लागू नहीं हो सकती। एक पेड़ की रक्षा करना एक इन्सान की रखा करना है। पेड़ में भी जीव है। अध्यक्ष महोदय, ये पेड़ की जीवनी के बारे में पढ़ें तो हम इनको बताएं, इन्होंने पेड़ कटवा का प्रदेा के वातावरण को बहुत खराब किया।

हम पेड़ों की रखा कर रहे हैं। हम प्रदेश के अन्दर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगवाएंगे और ज्यादासे ज्यादा पेड़ लगवाने की कोशिश भी की है।

श्री जय प्रकाश: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि जुलाई, 1992 से 31.01.1994 तक करनाल जिले में 7668472 पेड़ लगाए हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इनमें से कितने परसैट कीकर लगाईं और कितने परसैट सफेदे के पेड़ लगाए गए?

राव इन्द्रजीत सिंह: स्पीकर साहब, नीति के अनुसार करनाल जिले में पेड़ लगाए गए हैं। इमें से 31 परसैट पेड़ ऐसे लगाए गए हैं जो छाया के तौर पर काम में आएंगे। 37 परसेंट पेड़ टिम्बर के इस्तेमाल के लिए, 17 परसेंट फीडर के इस्तेमाल के लिए और 6 परसेंट फ्रूट आदि के इस्तेमाल के लिए लगाए जाते हैं।

श्री जय प्रकाश: स्पीकर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि ये पेड़ कहां-कहां पर लगाए गए?

राव इन्द्रजीत सिंह: आमतौर पर पेड़ कम्युनिटी लैंड पर लगाए गए हैं।

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि हमने पेड़ काट कर सड़कों पर डाल दिए थे। इस संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि जब स्टेट

वाटर का ओर टरोटोरियल का इ पू चल रहा थातो उसकी रक्षा करने के लिए प्रांत के हितों की खातर लोगों ने पेड़ काटर कर भी रास्ता रोका, ट्रैक्टर-ट्रालियों से भी रास्ता रोका। उन्होंने प्रोटैस्ट के तौर पर रास्ता रोका था। स्पीकर साहब, जो स्कीम थी, वह यह थी कि सड़कों या नहरों के किनारे पर जो पेड़ लगे हुए है, उनकी जो लास्ट लाईन होती है, वह किसान की फसल को नुकसान पहुंचाती थी, इसलिए उस समय यह फैसला किया गयाथा क जब ऐसे पेड़ जो 15-20 साल बाद मैच्योर होंगे, ऐसे पेड़कों को फोरैस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा काटने के बाद औकान के जरिए आधा पैसा किसानों को दिया जाएगा। यह पैसा उनको बतौर मुआवजे के तौर पर देना था। लीडर तो चेंज होते रहते हैं लेकिन पालिसी सरकार की वही रहती है मैं जानना चाहता हूँ कि किसानों की फसल को हुए नुकसान का मुआवजा देने के लिए क्या उस नीति को दोबारा से लागू करने का सरकार का कोई विचार है?

राव इन्द्रजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, इनहोंने एक बात यह कही है सरकार तो बदलती रहती है लेकिन नीतिया वही रहती है मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि इनके समय के दौरान जो नीति लागू की गई थी, वह यह थी कि जो पेड़ किसानों के खेत के साथ-साथ सड़कों पर या नहरों के किनारों पर लगाए जाएंगे उनको काटने पर आधा हिस्सा उन पेड़ लगाते हैं तो तो वह 15-16 साल में जा कर मैच्योर होता है। इसलिए उससे पहले उसको काटने की हम अनुमति नहीं देते।

(विधन) कीकर के पेड़ की छाया से खेत को नुकसान हो सकता है लेकिन अभी हमारी सरकार को आए हुए केवल अढ़ाई वर्ष हुए हैं और वे इतनी छोटे पेड़ हैं कि उनमें किसान की फसल को नुकसान नहीं हो सकता। किसानों को मुआवजा देने व पेड़ काटने के बारे में हमारी नीति यह है कि जब तक हम यह नहीं देख लेंगे कि फलां वृक्ष से किसान की फसल को नुकसान हो रहा है, तक तक उसको काटने की अनुमति नहीं देंगे। साथ ही मैं यह बताना चाहता हूँ कि जब हमारी सरकार बनी तो उस समय भुरू— गुरू में मने इनकी नीति के मुताबिक 1000—2000 हैक्टेयर जमीन में जो पेड़ लगे हुए थे, उनका मुआवजा किसानों को दिया था लेकिन अब हमारी नीति इनकी नीति से अलग है।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

तारांकित प्र न संख्या 786

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य प्रो० राम बिलास भार्मा सदन में उपस्थित नहीं थे।

Raid Conducted on Veravali Hospital, Gurgaon

809. Sh. Dhirpal Singh: Will the Minister for Health be pleased to state whether any raid on the Veravali Hospital, Gurgaon was conducted by the Police during the year 1992; if so, the result thereof?

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती भान्ति देवी राठी): अतिरिक्त उपायुक्त, गुडगांवा द्वारा जनवरी/फरवरी, 1992 के समय के दौरान एक जांच की गई थी। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस स्टेशन सिटी, गुडगांव में केस दर्ज किया गया था, जिसकी जांच अभी चल रही है।

श्री धीरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री होदया ने जो जवाब दिया है, वह हमें जो रिटन रिप्लाइ किला है, उससे अलग है।

श्रीमती भान्ति देवी राठी: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न मैं यह पूछा है कि क्या वर्ष 1992 के दौरान पुलिस द्वारा वेरावाली अस्पताल, गुडगांव में कोई छापा मारा गया है, यदि ऐसा है, तो उसका क्या परिणाम निकला है? इसका मैंने जवाब दिया है, नहीं। इसक बावजूद भी अगर माननीय साथी कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो वे पूछ सकते हैं।

श्री धीरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुझे जो लिखित उत्तर किला है उसमें कहा गया है कि जनवरी/फरवरी, 1992 में ए0 डी0 सी0, गुडगांव ने इन्क्वायरी की थी। मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि वह जांच रिपोर्ट पुलिस को किस तारीख को रैफर हुई थी? (विधन)

श्रीमती भान्ति देवी राठी: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि रेड तो नहीं हुई

थी। डी० सी० गुडगांव को रिटन िाकायत मिली थी और वह िाकायत सिटिजन राईट्स, हरियाणा द्वारा डी० सी० को दी गई थी और वह िाकायत दिनांक 07.12.1991 को ए०डी०सी० को सौंप दी। ए० डी० सी० ने कुछ अधिकारीयों को साथ लेकर मौके पर जा कर जांच की। उस में कौन-कौन से अधिकारी थे, यह भी मै बता देती हूं। एक डी० एस० पी०, एक डाक्टर और एक आई० ए० एस० अधिकारी मौके पर गए थे और उन्होंने वहां पर जो कर छानबीन की।

श्री धीरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मै माननीय मंत्री महोदया से जानकारी चाहता हूं कि सिटी गुडगांव में यह केस किस तारीख को दर्ज हुआ ओर उस पर क्या कार्यवाही हुई?

मुख्य मंत्री (चोधरी लाल): अध्यक्ष महोदय, 08.03.1994 केस दर्ज हुआ था। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही उस पर आगे की कार्यवाही हो सकेगी।

श्री धीर पाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या बी० ए० एम० एस० डाक्टर अंग्रेजी दवाईया रिक्मेंड कर सकता है?

श्री अध्यक्ष: धीरपाल सिंह जी, यह सवाल तो रेड से संबंधित है, इसमें बी० ए० एम० एस० की कोई बात नहीं है।

श्रीमती भान्ति देवी राठी: अध्यक्ष महोदय, कहां-कहां पर केस रजिस्टर्ड हुए हैं या इस बारे में कोई जानकारी अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो अलग से नोटिस दें। (विधन)

श्री धीरपाल सिंह: स्पीकर साहब, माननीय मंत्री साहिबा काफी इन्टैलीजेंट हैं और वे इस सवाल का जवाब दे सकती हैं, इसलिए मैं इनसे जानकारी चाहूंगा कि जहां पर रेड डाली गई है।(विधन) स्पीकर साहब, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और मेरी पर्सनल जानकारी में भी है। मेरे पास बी० ए० एम० एस० डाक्टर का लैटर पैड है जिस पर आयुर्वेदिक डिग्री लिखी होने के बावजूद अंग्रेजी दवाईया प्रैस्क्राइब की गई है, क्या एक बी०ए०एम०एस० डाक्टर ऐसी दवाईया प्रैस्क्राइब कर सकता है?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, फिनायल पर जो जांच की गई है, उसमें पाया गया है कि उनके पास सही डिग्री नहीं पाई गई थी। इसलिए तो उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है और कानून के मुताबिक जो कार्यवाही हो सकती है, वह जरूर की जाएगी।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जिन अस्पतालों में दवाईयों नहीं मिलती और सरकारी अस्पतालों में डाक्टर नहीं मिलते हैं.....(विधन)

Mr. Speaker: It is no question. Next question please.

Dadupur-Nalvi and Dadupur-Ladwa Canal

798. Sathi Lehri Singh: Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether the construction work of Dadupur Nalvi Canal has been started; if so, the time by which it is likely to be completed?

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra): No. Sir. The scheme is under consideration.

साथी लहरी सिंह: अध्यक्ष महोदय, इस स्कीम में आपका हल्का भी आता है और मेरा हल्का भी आता है। इससे चार जिे इफैक्ट होते है। मै सरकार का धन्यवाद करता हूं क्योंकि इन्होने कहा है कि यह अन्डर कंसीड्रे 1न हैं पिछली बार सरकार ने कहा था कि यह कैनाल स्कीम में नही है। मै सरकारका आभारी हूं कि इन्होने इस बार स्कीम में इसे भामिल कर लिया है। अध्यक्ष महादेय यह किसान को लाईफ लाईन हैं ऐसा करने से सरकार की 10 करोड़ रुपये की बिजली बच सकती है। मै मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये दादूपुर नलवी पर कब तक काम भुरु कर देगे?

चौधरी जगदी 1 नेहरा: अध्यक्ष महोदय, यह सी0 डब्ल्यू0 सी0 के साथ अन्डर कंसीड्रे 1न है और हरियाणा सरकार इस बारे में जागरुक है। जब सी0 डब्ल्यू0 सी0 इजाजत देगी तो इस पर सरकार कार्यवाही करेगी।

साथी लहरी सिंह: अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि जो नहर हमारे एरिया से निकलती है, उससे हमें पानी नहीं मिलता और यह मारे साथ ज्यादाती होती है हमें ने तो डब्ल्यू० जे० सी० का पानी मिलता है और न ही आगमैंटे इन का पानी मिलता है। हमारी जीरी और गेहूं की फसले सूख जाती है। क्या इन फसलों को बचाने के लिए सरकार हमें पानी देगी?

(इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

चौधरी ओम प्रकाश बेरी: अध्यक्ष महोदय, दादूपुर-नलवी नहर जब सैक इन की गई थी, तब से लेकर आज तक इस पर कतने करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है? इसके साथ ही क्या मंत्री जी आवासन देंगे कि जो वर्ल्ड बैंक से आठ सौ करोड़ रुपए मिल रहे हैं उसमें से कुछ पैसा इस कैनल पर खर्च करने का प्रावधान करेंगे?

चौधरी जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, यह स्कीम 1985 में सैक इन हुई थी। उस समय यह स्कीम 13 करोड़ रुपए की थी और आज 65 करोड़ रुपए की है। पहले जब डिजाइन किया था उस समय इसकी कैपेसिटी 590 क्यूसिक की थी और इससे जो एरिया कामन्ड हो रहा है, वह 186114 एकड़ है। लाडवा वगैरह को मिलाकर इसकी टोटल लैन्थ 381.40 किलोमीटर है।

दूसरे इन्होंने वर्ल्ड बैंक की बात कही है। यह वर्ल्ड बैंक की स्कीम के तहत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इसके साथ

जमुना का पानी के बंटवारे की बात जुड़ी हुई हैं जमुना का पानी पांच सूबों में बंटना है ओर जब बंटवारा हो जाएगा, तक यह रूकीम आएगी। दादूपुर नलवी, हथनी कुण्ड बैराज, डब्ल्यू० जे० सी० में पानी की कैपेसिटी बढ़ाना, जे० एल० एन० की सप्लाई ठीक करना, दिल्ली कैनल को पैरेनियल बनाना, गुड़गांव कैनल की कैपेसिटी बढ़ाना, किसान डैम, रेणुका डैम, गिरी बाटा डैम और जमुना हाईडल पावर स्टे इन की स्कीमें है जो पानी के बंटवारे के बाद ही पूरी होगी। इसी तरह से और भी बहुत सी चीजे जमुना के पानी से जुड़ी हुई है। अध्यक्ष महोदय, जब पानी का बंटवारा हो जाएगा तो केन्द्रीय सरकार से भी सहायता मिलेगी। इसमें किसी स्कीम पर 40 करोड़ किसी पर 80 करोड़ किसी पर 100 करोड़ और किसी पर 400 करोड़ रूपये खर्च होने है। सर, इसका संबंध केन्द्रीय सरकार से है।

श्री के० एल० भार्मा: स्पीकर साहब, मैंने भी इसी क्वै चन को हाउस में मार्च 1992 के सै इन में उठाया था और उस समय मंत्री महोदय ने यह कहा था कि ये दादूपर-नलवी की जो स्कीम है, यह अंडर कंसीड्रे इन है लेकिन बाद में कहा कि यह स्कीम छोड़ दी गई हैं परन्तु अब फिर मंत्री जी ने लहरी सिंह के सवाल के जवाब में बताया है कि यह स्कीम को भुरु करने जा रहे है। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह जो इन्होंने कहा कि यह स्कीम अंडर कंसीड्रे इन है, यह किन प्वायंट्स के आधार पर कहा गया है? क्या कोई पैसा

इसके लिए मंजूर हुआ है और इसके बारे में कोई ऐकान लिया गया है, अगर लिया है तो इस को कब तक चालू कर देगे?

चौधरी जगदीश नेहरा: स्पीकर साहब, इस स्कीम को अंडर कंसीड्रेटर इस लिए कहा गया है क्योंकि कई मुद्दे और कई चीजे इससे जुड़ी हुई हैं। (विधन) स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अंडर कंसीड्रेटर इन का मतलब है कि अभी हमारे हाथ में पूरी तरह से यह बात नहीं है जैसा मैंने पहले भी कहा कि यह स्कीम पांच सूबों से जुड़ी हुई है, जिसमें हिमाचल, यू० पी०, हरियाणा दिल्ली और राजस्थान शामिल है। इन सूबों के बीच में जो भी समझौता होगा, उसके बाद ही यह केस केन्द्रीय सरकार के सी० डब्ल्यू० सी० के सामने रखा जायेगा तथा इसके बाद पलनिंग कमीशन में जाएगा और उसके बाद ही इसके लिए बजट में प्रावान किया जायेगा। स्पीकर सर, इस तरह से यह सारा सिस्टम कम्पलीट करना है इसलिए य स्कीम अंडर कंसीड्रेटर इन है। यह काम इनकी सरकार की औकात से बाहर का है।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, अभी नेहरा जी ने कहा कि यह काम हमारी औकात का नहीं है। (विधन) स्पीकर सर, सवाल दादूपुर नलवी का था। अभी नेहरा साहब ने बड़ी सीरियल बात कही है जिसके बारे में हमने भी बार-बार सवाल उठाया है। और मुख्य मंत्री जी ने भी अपना ब्यान दिया है। स्पीकर सर, इन्होंने बड़े धड़ल्ले से गवर्न ऐड्रेस में भी बोल दिया कि जमुना के वाटर

में केवल दो स्टेट्स का भोयर है, और वह यू० पी० और हरियाणा। लेकिन अभी नेहरा जी कह रहे हैं कि जमुना के वाटर में पांच स्टेट्स डिसप्यूट है। ओर इनके बीच में जल्दी ही कोई फैसला होने वाला है। ये इस फैसले के बाद ही दादूपुर नलवी स्कीम को टेकअप करेगे। इन्होंने कहा कि यह स्कीम अभी अंडर कंसीड्रे टान है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि ये दोगली बाते क्यों करते हैं? मुख्यमंत्री जी स्पष्ट करें कि क्या उस जमुना के वाटर में उन तीनों स्टेट्स का भी हिस्सा है? स्पीकर सर, मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा क मंत्री जी ने तो ब्यानबाजी की है, उसको स्पष्ट करें। हमें मंत्री जी की बात में भांक हो रही है। स्पीकर सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दादूपुर नलवी की स्कीम जमुना के पानी से जुड़ी हुई हैं जितना जमुना का पानी फालतू होगा, वह इस स्कीम के माध्यम से दादूपुर-नलवी कैनल में आएगा। (विधन) स्पीकर सर, इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, गलत बात कहने से कोई फायदा नहीं है। (ओर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बरसात में तो आपके पास काफी पानी हो जाता है। क्या आप उस नहर को बनाकर बरसात के मौसम में उसमें पानी नहीं छोड़ सकते?

चौधरी जगदी ा नेहरा: अध्यक्ष महोदय, यही कई बातें अंडर कंसीड्रे टान है। जो सवाल आपने किया है, वह बड़ा रेलैवेन्ट है और इसलिए जो समझौते होने हैं, उनके तहत इस नहर को तैयार करना है जो फलड का वाटर भी ले जाए, चाहे वह

इंरीगे ान के लिए हो, चाहे री-चाजिग के लिए हो। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सम्पत सिंह जी, आप बैठ जाइए। (ाोर एवं व्यवधान)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, इसमें सिवाये हरियाणा और यू० पी० के इंरीगे ान के लिए बाकी और किसी स्टेट का हिस्सा नहीं है। पीने के पानी के लिए मानवता के आधार पर सारे दे ा की पौलिसी बनने जा रही है कि जहां पीने के पानी का संकट है, वहां पीने का पानी दिया जाए। दिल्ली दे ा की एस०वाई०एल० के रास्ते से दिल्ली को पीने का पानी का पानी दें। इसी बात को दृष्टि में रखते हुए दिल्ली में 3-4 बार मीटिंग हुई है कि दिल्ली को पीने का पानी देना है। दिल्ली वाले भी बदले में हमको पानी देगे। दिल्ली का जो गन्दा पानी है उसको बाकायदा साफ करके हमें सप्लाई करेंगे।

प्रो० सम्पत सिंह: इसमें और कौन-कौन सी स्टेट्स शामिल हैं?

चौधरी भजन लाल: इनमें यू० पी०, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पांचवा हिमाचल प्रदेश है।

श्री अध्यक्ष: हिमाचल से तो सारी नदियां होकर आती हैं?

चौधरी भजल लाल: हिमाचल का पानी नहीं, बिजली की बात है रणुका और किसानों के पानी में हिमाचल का भोयर नहीं है मैंने चार स्टेट्स है। जैसे भोयर तो छिल्ली का भी नहीं है। पानी अगर सिंचाई के लिए दिया जाए तो पानी के बंटवारे का सवाल हाता है माननीय आधार पर उनको पीने का पानी दिया है क्योंकि दिल्ली में आबादी बढ़ रही है। हरियाणा के लोग भी वहां रहते हैं, यू० पी०के लोग भी रहते हैं। दे० की मानमर्यादा का सवाल है। अगर हम पीने का पानी दिल्ली को नहीं दे सकेंगे तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे? माननीय आधार पर सिर्फ आर्जी तौर पर कुछ समय के लिए पीने के लिए पानी दिया है। इसमें भोयर की कोई बात नहीं है बार-बार जैसे ही ये बात कह रहे हैं, अब बात खत्म हो गयी है। (व्यवधान व भाोर)

प्र० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, इन्होंने यह कहा है कि 5 स्टेट्स की टाक्स हो रही है ओर मामला अंडर कंसीड्रे टन है। (व्यवधान व भाोर).....

Declaration of Farukh Nagar as Sub-Tehsil

753. Sh. Mohan Lal Pippal: will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to declare Farukh Nagar as sub-Tehsil; and

(b) If so, the time by which the afore-said proposal is likely to be materialized?

राजस्व मंत्री (श्री निर्मल सिंह):

(क) हां जी।

(ख) निर्दिष्ट समय नहीं दिया जा सकता।

श्री मोहन लाल पिपल: स्पीकर महोदय मंत्री जी ने मेरे सवाल के भाग 'क' के जवाब में हां जी कह दिया है लेकिन 'ख' का जवाब देते समय यह कह दिया है कि इस बारे में निर्दिष्ट समय नहीं दिया जा सकता। सर, यह तो हमारे इलाके की मांग है इसको कब तक पूरा कर देंगे?

श्री निर्मल सिंह: अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

Construction of Metalled Roads

853. Sh. Chander Mohan: Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Govt. to launch a crash programme to connect all the village in Shivalik Region with metalled roads; and

(b) If so, the time by which the Villages as referred to in part (a) above are likely to be connected?

लोक निर्माण मंत्री (चौधरी आनन्द सिंह डांगी):

(क) और (ख) िवालिक क्षेत्र के भोश काबिल डायरैक्ट्री गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव है परन्तु इनका पूरा करना भारत सरकार द्वारा डिफोरैस्टे ान की अनुमति जहां तक आव यक हो तथा धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

श्री चन्द्र मोहन: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने यह बताया है कि भारत सरकार जब मंजूरी देगी, तब इस क्षेत्र के बाकी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। भारत सरकार से मंजूरी लेना तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है, किसी आदमी वि ेश का काम नहीं है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार की यह नीति है कि हरेक गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। मैदानी इलाके में तो सरकार ने इस बारे में काफी सराहनीय कार्य किया है लेकिन मेरे क्षेत्र मोरनी के पहाड़ी क्षेत्र में कई गांव ऐसे हैं जहां पर अभी तक यह सुविधा प्राप्त नहीं है। उन गांवों को पक्की सड़कों से नहीं जोड़ा गया है। भारत सरकार से आप कब तक मंजूरी प्राप्त कर लेंगे और कब तक वहां पर काम शुरू करा देंगे? अब तक क्या ऐव ान हुआ है, क्या मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेंगे?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी: अध्यक्ष महोदय, इस पहाड़ी क्षेत्र के लगभग हरेक गांव को, जिनकी आबादी मैदान में 250 की है और पहाड़ी क्षेत्र में 150 की है पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है। अब केवल 7 गांव ऐसे हैं जिनको जोड़ना भोश रहता है।

राज्य सरकार इसके लिए पहले ही स्वीकृति दे चुकी है। यह सड़के तभी बनी सकेंगी जब उन पर डी-फारैस्टे इन का काम करने के लिए भारत सरकार से अनुमति मिल जायेगी। इस बारे में हम कई पत्र भारत सरकार को लिख चुके हैं और हर लैवल पर मीटिंग भी हो चुकी है। अब आगा की जाती है कि डी-फारैस्टे इन के कार्य के लिए जल्दी ही हमें अनुमति मिल जायेगी। लेकिन इन सड़कों को जोड़ने के लिए अवधि या कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि जब तक फारैस्ट डिपार्टमेंट को सैट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्लीयरेंस न मिल जाए, तब तक हम इनकी बना नहीं सकेंगे।

744. Ch. Om Parkash Beri: Will the Minister Education be please to state—

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Govt. to upgrade the following schools—

(i) Govt. Girls Hight Schools, Beri to Senior Secoundary School;

(ii) Govt. Girls Middle School, Majra to Hight School;

(iii) Govt. Girls Primary School, chimmi to Senior Secounary School;

(iv) Govt. Primary School, Bakra to Middle School;
and

(b) If so, the time by which the schools referred to in part (a) above are likely to be upgraded?

Education Minister (Sh. Phool Chand Mulana):

(a) No, Sir.

(b) Upgradation cases can be considered as per need of the area and subject to the availability of funds.

चौधरी ओम प्रकाश बेरी: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह बताया है कि अपग्रेडे इन के लिए फंडज होने चाहिए। जहां तक अवेलेबिलिटी आफ फंडज का ताल्लुक है, वह तो ये खुद ही करेगे, हमारे बस की बात नहीं हैं जिन स्कूलों को जिक्र मैंने अपग्रेडे इन के लिए आपने सवाल से किया है, मैं इस बारे में इनको यह बता दूँ और इस बारे में चाहे वये अपने डिपार्टमेंट से पूछभी ले क 21.06.1992 को, जब मुख्य मंत्री बेरी में गयेथे, तो वहां पर इन स्कूलों की अपग्रेडे इन के लिए एलान करके आये थे। जहां तक बेरी का ताल्लुक है, वहां पर 20 हजार के करीब आबादी है। इसमें दो हजार के करीब लड़कियां/बच्चियां पढ़ती है। इसी तरह से एक माजरा गांव है उसकी आबादी भी करीब 13000 है। इसी तरह से चिमनी की आबादी 7-8 हजार के करीब है। वहां पर बिल्डिंग एक कालेज जसी बना रखी है। इसी तरह से बाकरा में भी यही हालत है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्यो वे इन स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए आवासन देगे?

श्री फूल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, बेरी साहब ने कहा है कि मुख्य मंत्री जी बेरी गए थे ओर इनस्कूलों को अपग्रेड करने की घोशणा करके आए हैं। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने केवल बेरी के स्कूल के लिए घोशणा की थी। मैं बेरी साहब को बताना चाहता हूँ कि बेरी में पहले से 10+2 का स्कूल चल रहा है, इसलिए परमावयक ने समझ कर उस पर अगले वर्ष विचार कर लिया जाएगा। जहां तक दूसरे स्कूलों के अपग्रेडेशन कासवाल है, अध्यक्ष महोदय, प्रांत में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर 2.33 किलोमीटर की परिधी से कोई स्कूल दूर पड़ता हो। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि जब हम ओर आप पढ़ा करते थे तो दस बारह किलोमीटर हमें स्कूल के लिए जाना पड़ता था। आज तो शिक्षा विभाग ने शिक्षा के केन्द्र जगह-जगह खोल दिए हैं। आज शिक्षा विभाग ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी चेतना पैदा कर दी है। आप लोग अध्यापकों को कहें कि वे अपनी जिम्मेदारी समझे ओर बच्चों को पढ़ाए।

चौधरी अजमत खां: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने कहा कि हरियाणा में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां 2.33 किलोमीटर से ज्यादा फसले पर 10+2 का कोई स्कूल नहीं है, मलाई से बहीन ग्यारह किलोमीटर है, और वहां कोई स्कूल नहीं है। मलाई से हथीन ग्यारह किलोमीटर का फासला है लेकिन वहां पर बीच में कोई 10+2 का स्कूल नहीं है हथीन से औरंगाबाद का फासला तेरह किलोमीटर है लेकिन वहां भी 10+2 का कोई स्कूल

बीच में नहीं है। क्या मंत्री महोदय बताने का कृपा करेंगे कि ये अम्बाला के आंकड़े दे रहे हैं या भिवानी, हिसार और सिरसा के आंकड़े दे रहे हैं?

श्री फूल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, मेरे दोस्त अजमत ख स्वयं अध्यापक रह हैं ये जो मैंने फिगरज दी है, वे ऐवरेज फिगरज हैं ये जो पन्द्रह-पन्द्रह किलोमीटर का फासला बता रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पन्द्रह किलोमीटर तक कोई स्कूल न हो। जो मैंने फिगरज बताई है, उसका मतलब यह है कि फासला ऐवरेज इतना बनता है।

श्री अमीर चन्द्र मक्कड़: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, कौन से इलाके की ऐवरेज बता रहे हैं? हरियाणा की ऐवरेज बता रहे हैं या किसी और इलाके की ऐवरेज बता रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कहीं परभी ऐवरेज दो तीन किलोमीटर नहीं बनती। हर जगह दस पन्द्रह किलोमीटर से कम फासले पर कोई भी 10+2 का स्कूल नहीं है।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, 10+2 की बात नहीं है। जो फासला बताया गया है वह स्कूल का बताया गया है। हर किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल है, दो किलोमीटर पर मिडिल स्कूल है और पांच किलोमीटर पर हाई स्कूल है। ऐसा नहीं कहा कि 10+2 का स्कूल 2.33 किलोमीटर पर है।

श्री रमे 1 चन्द्र: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि हर 2.33 किलोमीटर पर 10+2 का स्कूल है। स्पीकर साहब, इतने फासले परकही कोई स्कूल नहीं है। मेरे बड़ौदा हल्के में सिवानका गांव है, वहां के बच्चों को आठ-आठ किलोमीटर पर स्कूल जाना पड़ता है। न वहां पर कोई हाई स्कूल है और न कोई 10+2 का स्कूल है। क्या मंत्री महोदय बताने का कृपा करेगे कि मेरे हल्के के सिवानका गांव में कोई 10+2 का स्कूल खोलने की स्कीम विचारधीन है?

श्री फूल चन्द मुलाना: अभी कोई विचार नहीं है।

श्री अमर सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि वर्ष 1994-95 में कितने प्राईमरी स्कूलों को मिडल स्कूल अपग्रेड किया जायेगा, कितने मिडल से हाई और कितने हाई से 10+2 बनाए जाएंगे?

श्री फूल चन्द्र मुलाना: अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी मैंने एक सवाल के जवाब में बताया था कि यह सब कुछ बजट पर निर्भर करता है। इस बार माननीय सदस्य ने वित्त मंत्री श्री मांग राम गुप्ता जी को एड्रेस भी सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि 50 स्कूल प्राईमरी से मिडल ओर 25 स्कूल मिडल से हाई अपग्रेड किये जाएंगे।

तारांकित प्र न संख्या 759

(यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री दरियाओं सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Jaundice Disease in Pehowa City

818. Sh. Jaswinder Singh: Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) Whether any cases of Jaundice disease have been reported from Pehowa city during the month of November, December, 1993 and January, 1994, if so, the reasons therefor; and

(b) The steps, if any taken to prevent the occurrence of such type of disease in future?

स्वास्थ्य एवं आयुर्वेदा मंत्री (श्रीमती भान्ति देवी राठी):

(क) हां, मास नवम्बर, दिसम्बर, 1993 तक जनवरी, 1994 के दौरान पेहवा भाहर में पीलिया रोग के 4 मामले प्रकाश में आए हैं। पीलिया एक जल दूषित रोग है जो मल दूषित जल के पीने से होता है।

(ख) (1) पीने के पानी को क्लोरीनेशन।

(2) लीकिंग पाईपों की मरम्मत करना।

(3) रैजिड्वल क्लोरीन तथा जीवाणु परीक्षण के लिए पानी के नमूनों की नियमित चैकिंग।

(4) स्वास्थ्य शिक्षा।

(5) ऐपीडैमिक डीजीजिज एक्ट, 1897 का लागू करना।

(6) जिला स्तर पर दूषित जल से फैलने वाले रोगों के नियंत्रण हेतु जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है जिसमें सिविल सर्जन, अधीक्षक अभियन्ता/कार्यकारी अभियन्ता (जन स्वास्थ्य) जिला किवास एवं पंचायत अधिकारी तथा प्रधान नगरपालिका सदस्य होते हैं।

श्री जसविन्द्र सिंह: स्पीकर सर, मंत्री महोदया ने मेरे सवाल के जवाब में यह माना है कि मास नवम्बर, दिसम्बर, 1993 तथा जनवरी, 1994 के दौरान पेहवा भाहर में पीलिया रोग के केवल 4 मामले प्रकाश में आये हैं। अध्यक्ष महोदय, पेहवा एक यात्री स्थान है, वहां पर यात्री आते जाते रहते हैं। और लगभग 50 के करीब वहां प्राइवेट हस्पताल भी है। वहां पर 7 केसिज गवर्नमेंट हस्पताल में काफी सीरियस है और लगभग 600-700 केसिज हमारे नोटिस में आ चुके हैं जिनमें से दो व्यक्तियों की तो मौत भी हो चुकी है। इस रोग के फैलने का कारण यह है कि वहां का जो सीवरेज सिस्टम है, वह बहुत ही खराब हो चुका है और सीवरेज का गन्दा पानी पीने के पानी के साथ मिल जाता है। 12 नवम्बर वार्ड में तो यह शिकायत सब से ज्यादा है। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूँ कि इन सारे हालात को देखते हुए वे कब तक पीने के स्वच्छ पानी का प्रबन्ध लोगों के लिए करवा पाएंगी ताकि लोगों को इस रोग से बचाया जा सके जो सीवरेज की गन्दगी के कारण फैलता है?

श्रीमती भान्ति देवी: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है और आज एक बहुत जटिल समस्या सीवरेज के गन्दे पानी की और स्वच्छ पानी की हमारे समक्ष खड़ी है। वैसे तो सीवरेज की पाईप्स ओर स्वच्छ पानी की पाईप एक दूसरे से काफी दूरी पर होनी चाहिए लेकिन वहां पर दोनों ही पाईप्स साथ साथ चल रही है जिससे सीवरेज का जो दूषित पानी है, वह स्वच्छ पानी में मिल रहा है क्योंकि वे दोनों पाईप्स बिल्कुल साथ साथ जा रही है। पाईप्स की लीकेज के कारण पानी आपस में मिल जाता है और लोगों को वह गन्दा पानी पीने से पीलिया का रोग हो जाता है और इससे बच्चे बूढ़े व जवान सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बात इनकी सही है कि पीलिया एक जल दूषित रोग है जो मल दूषित जल के पीने से होता है। इसकी रोकथा के एि सरकार पूरी तरह से सजग है। इसके लिए जन स्वास्थ्य विभाग से भी मैंने निजी तौर पर अनुरोध किया है और लिखा है क वह कम सक कम किसी भी विस्तार से पहले, जो खस्ता हालत की सीवरेज की या दूसरी पाईप्स है, जो 14-14 व 15-15 साल पुरानी चली आ रही है, कम सके कम उनको पहले रिप्लेस करें। इस बारे में काफी काम हुआ भी हुआ है और भविश्य में हम और सतर्कता बरत रहे हैं। हमारा भविश्य में यह प्रयास होगा कि सीवरेज के पानी से जो दूषित जल होता है, उसकी लीकेज के कारण भविश्य में ऐसा कोई वाक्या न होने पाए। जैसा इन्होंने कहा है कि पीलिया के ज्यादा केसिज हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है, मैं इस बारे में इन्हें बता देना चाहती

हूं कि अब तक हमारे रिकार्ड के अनुसार केवल चार मामले प्रकाश में आये हैं, मुत्यु काकोई केस अभी तक हमारे सामने नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष: बहन जी, पेहवा एक तीर्थ स्थान है। बहुत सारे यात्री रोजाना आते जाते हैं। पेहवा के बारे में बताए कि स्थिति कब तक ठीक हो जाएगी?

श्री जसविन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का सही जवाब नहीं आया है जैसाकि मैंने पहले ही कहा है कि सात केसिज हमारी जानकारी के अनुसार काफी सीरियस है। वहां के जो तहसीलदार हैं, वे भोर सिंह जी के रिपेयर्स हैं, वे बीमार हुए, सिविल हस्पताल के डॉक्टर श्री कोहली श्री बीमार हुए। म्यूनिसिपल कमिटी के जो पेजीडेंट हैं, उनका बेटा बहुत सीरियस है। इस तरह से ओर बहुत से केसिज हमारी नालिज में हैं। मंत्री महोदय ने तो केवल वे रिपोर्ट बताई हैं जो सिविल हस्पताल की हैं। पेहवा के लगभग 50 के करीब प्राइवेट हस्पताल हैं जहां पर लोग इस रोग का इलाज करवा रहे हैं। मेरी स्पीकर साहब, आपके माध्यम से यह कहना है कि कब तक वे पेहवा के दूषित जल को पीने के लायक बनाव देंगे ओर कब तक सीवरेज की जो टूटी फूटी पाइप्स हैं, जिनका पानी रिस कर पीने की पाइप्स द्वारा लोगों के घरों तक जाते हैं, उसको रिपेयर करवा देंगे ताकि लोगों को स्वच्छ पीने का पानी मिल सके ओर इस तरह पीलिया जैसी भयानक बीमारियां आगे से न हो सकें, कब तक यह कार्य करवा देंगी?

श्रीमती भान्ति देवी: स्पीकर साहब, जैसे कि मैंने बताया कि पीलिया से पीड़ित काफी केस हो सकते हैं लेकिन विभाग ने जो रिपोर्ट मुझे दी है, वह मैंने यहा पर बता दी है। अगर माननीय सदस्य के नोटिस में और केसिज है तो वे हमें लिख कर भेज दें, उनकी पूरी तरह से जांच की जाएगी। हमने जन स्वास्थ्य विभाग से पहले अनुरोध कर रखा है ताक जो पाइप लीक कर रहे है, उनको रिप्लेस करवाया जाए।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, जिस जगह पर पाइप ठीक नहीं है यानी पाइप से लीकेज हो कर पीने वाले पानी के पास सीवरेज का पानी मिल जाता है तो उस गन्दे पानी की वजह से पीलिए की बीमारी फैल सकती है मैं माननीय सदस्यों को वि वास दिलाना चाहता हूं कि जहां जाहं पर ऐसी समस्या है, जहां सीवरेज के पाईप लीक करते है, उनको सबसे पहले बदला जाएगा ताकि लोगों को पीने के लिए स्वच्छा पानी देकर पीलिए की बीमारी से बचाया जा सके।

Chhainsa Power Sub-Station

824. Sh. Rajinder Singh Bisla: Will the Minister for Power be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to upgrade the capacity of power sub station of Chhainsa in District Faridabad?

Power Minister (Sh. A.C. Chaudhary): Yes, Sir.

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने पावर पोर्टफोलियो संभालने के बाद इसमें बहुत सुधार किया है मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा है कि 'जी हाँ'। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि केवल मात्र 'जी हाँ' कहने से मेरे क्षेत्र के लोगों को तसल्ली नहीं होगी। कृपया आप सदन में आवासन दें कि छांसया के पावर सबस्टेशन की अपग्रेडेशन का काम आने वाले अप्रैल के महीने में शुरू कर दिया जाएगा?

श्री ए० सी० चौधरी: स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर ने जो अपने इलाके का दुख जाहिर किया है, मैं उसके साथ सहमत हूँ। इस समय चूंकि छांसया को हम बदरोला से सप्लाई दे रहे हैं, फिर भी छांसया में एक को बजाए दो ट्रांसफार्मर लगाए हुए हैं। सरकार को इस बात का एहसास है और यह कमी तो आज के दिन हम पूरी कर लेंगे लेकिन हमें पता नहीं कि आने वाले दिनों में बजली की कमी होगी, इसलिए हमने उसके लिए एक रिपोर्ट पहले ही मांग ली है। हमने उसी टैक्नीकल फिजिबिल्टी मांग ली है और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि ऐसा वक्त नहीं आएगा कि आपको गिला रहे। हम पैसे के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए इस करन्ट ईयर में सारा काम क्लीयर करके काम शुरू करवाने की कोशिश करेंगे।

श्री मनी राम केहरवाला: अध्यक्ष महोदय, पावर सबस्टेशन की कैपेसिटी बढ़ाने की कई जगह जरूरती है। जैसे

एलनाबाद में ओर करीवाला में जो ट्रांसफार्मर्ज लगे हुए है, वे जरूरत के मुताबिक छोटे है। वहां की जरूरत कब तक पूरी कर दी जाएगी?

श्री ए०सी० चौधरी: स्पीकर साहब, यह सवाल तो बल्लभगढ़ के छांयसा का था लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि मैंने पिछले दो तीन सवालों के जवाब में हर जिले के बारे में डिटेल में बताया है। जहां ये समझते है कि ओवर लोडिंग की वजह से ट्रांसफार्मर की एडी इनल रिकवायरमेंट है, वे कृपया मुझे बता दे ताकि मैं उन पर हाउस में फारमैलिटी के तौर पर जवाब ही न दूं बल्कि उस काम को करवाभी सकूं।

**Cases /Registered under the violation of Essential
Commodities Act**

836. Sh. Jai Singh Rana: Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state—

(a) Whether any cases have been registered under the violation for Essential Commodities Act with the Police in the State during the year 1993-94, if so, the number thereof; and

(b) the Number of licencess of depot. holders, if any cancelled under the detection of mal practice and irregularities in Public Distribution Systme in the state during the perod mentioned in Part(a) above?

खाद्य एवं पूर्ति मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह):

(क) हां, वर्ष 1993-94 में (28 फरवरी, 94 तक) आव यक वस्तुएं अधिनियम की उल्लंघना करने पर पुलिस के पास 100 मामले दर्ज करवाये, और

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान जन वितरण प्रणाली के तहत अवैध कार्य करने तथा अनियमितताये करने के कारण 180 डिपों धारकों की अथोरिटी (जिसे आमतौर पर डिपों का लाईसेन्स भी कहा जाता है), रद्द किये गये।

श्री जय सिंह राणा: स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो 100 मामले दर्ज किए गए है, उनका जिलावार ब्यौरा क्या है तथा किस किस जिले में कितने कितने केस दर्ज हुए है?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, फरवरी, 1993-94 तक जिन डिपों होल्डर्ज या लाईसेंसीज की अनियमिताएं पाई गई, उनके खिलाफ 100 केस दर्ज करवाए गए। उनका जिलावार ब्यौरा इस प्रकार है अम्बाला जिले में पांच, जमुनागर जिले में 13, भिवानी जिले में तीन, सोनीपत जिले में चार, रिवाड़ी जिले में 6, कैथल जिले में पांच, हिसार जिले में 8, सिरसा जिले में 10, कुरुक्षेत्र जिले में एक, फरीदाबाद जिले में 10, गुडगांव जिले में 10, रोहतक जिले में दो, पानीपत जिले में 15, करनाल जिले में तीन, और नारनौल जिले में पांच। इस तरह से लगभग 100 केस दर्ज हुए।

Harijan Chaupals

841. Sh. Ram Rattan: Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state—

(a) The number of Harijan Chaupals, if any, lying incomplete in Hassanpur Block, Distt. Faridabad; and

(b) The time by which construction work of the aforesaid Chaupals is likely to be completed?

विकास मंत्री (राव बंसी सिंह):

(क) फरीदाबाद जिले में ऐसा कोई ब्लाक नहीं है।

(ख) प्र न ही नहीं उठता।

स्पीकर साहब, भाई राम रतन ने यह सवाल पूछा है कि जिला फरीदाबाद के हसनपुर ब्लाक में कितनी हरिजन चौपाले अधूरी पडती है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हसनपुर कोई ब्लाक नहीं है इसलिए वहां पर कोई हरिजन चौपाल अधूरी रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दरअसल मैं इनकी तसल्ली के लिए बताना चाहूंगा कि इनकी कांस्टीच्यूसी में दो ब्लाक पडते हैं— एक होडल और दूसरा पलवल। अब तक माननीय सदस्य की कांस्टीच्यूसी में 59 हरिजन चौपाले कम्पलीट की जा चुकी है। अब 25 चौपाले रहती है जिनको कम्पलीट करना है। ज्यो ही एफ0 डी0 से पैसा रीलीज होगा, उनको कम्पलीट करने की कोशिश करेंगे।

श्री राम रतन: अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में प्रहलादपुर, हुसंगाबाद, डकोरा, कु गलीपुर, भामसाबाद, बाता, गुन्दवास, करबन, सतवागढ़, गुलावाद, लिखी और रूंधी यानि कम सक कम 25 चौपालें ऐसी है जो अधूरी पडत्री है, उनको कब तक पूरा करवा दिया जाएगा?

राव बंसी सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने आपे माध्यम से भाई राम रत जी को अभी बताय था कि 25 चौपालें इनक्पलीट हैं चौपालों के लिए 25 लाख रूपया मंजूर किया गया था, जिसमें से 15 लाख रूपया रिलीज हो चुका है और वह पैसा हमने जिलवाइज डी0 सीज0 को भेज दिया है। अब 10 लाख रूपया रिलीज होना बाकी रहता है। ज्यो ही पैसा हमारे पास आएगा, हम डी0 सीज0 को भेज देगे ओर उस पैसे से जितनी चौपालें कम्पलीट की जा सकेगी, उनको कम्पलीट करने की कोशिश करेगे।

श्री अध्यक्ष: अनरेबल मैम्बर्ज, अब क्वै चेज आवर समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर खा गया तारांकित प्रश्न का लिखित उत्तर

Cases of Embezzlement

773. Ch. Azmat Khan: Will the Minister for Power be pleased to state—

(a) Whether any cases of embezzlement in Hodel, Nuh and Ferozpur Jhrika sub division of H.S.E.B. has been detected during the period from 1986 to 1992; and

(b) If so, the total amount involved in each case of embezzlement togetherwitht he names of the officials held responsible therefor and the action taken against them?

Power Minister (Sh. A.C. Chaudhary):

(a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the table of the House

STATEMENT

Followiing cases of embezzlement were detected during the period 1986 to 1992 in respect of the operation sub divisions of hodel and Nuh. There was no case of embezzlement at operatio sub Divisions,Ferozpur Jhirka during the perid.

Name of Sub Division	Amount involoved	Name of Officer/Official	Action taken
Operation sub Division, Nuth	Rs. 1053405.92	Sh. Ajit Kumar Jain, L.D.C. (Cash	Official arrested and released on bail. Presentaly under suspension. Case under

			investigation by police.
Operation Sub Division Hodal	Rs. 1178174.80	Sh. Siri Chand, Chashier. Sh. Giaisi Ram, U.D.C. (R) Sh. Ulshan Nagpal, S.D.O., Sh. Girraj Singh, S.DO. Sh. I.M. Jain, S.D.O. Sh. R.D. Dhiman, J.E.-I	Sh. Siri Chand Cashier, arrested and released on bail. The exten of responsibility of other officials is sbeing determined for punitivie action.

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Construction of Roads

175. Sh. Mani Ram Rupwas: Will the Minister for PWD (B&R) be pleased to state—

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct the following roads of Distt. Sirsa—

(i) From village Rupawas to Jorka;

(ii) From village Kumhariya to Rajasthan border:

(iii) From village Sahuwala-II to sherpura;

(iv) From village Rupana Khurd to Nirwan; and

(v) From village Bakriyawali to Moriakhera; and

(b) If so, the time by which the afore-said roads are likely to be constructed?

लोक निर्माण मंत्री (चौधरी आनन्द सिंह डांगी):

(क) और (ख) क्रमांक 1 तथा 3 पर वर्णित सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव नहीं है। क्रमांक 1 तथा 3 पर वर्णित सड़कों के निर्माण के समय निर्धारण का प्र न ही नहीं उठता।

Veterinary Hospital/Dispensary

176. Sh. Mani Ram Rupawas: Will the Minister of state for Animal Husbandary be pleased to state—

(a) Whether it is a fact that the most of the Veterinary Hospital/Dispensaries of Darba-Kalan of Block Nathusari Chopta District Sirsa are without Doctors; if so, the time by which the doctors are likely to be posted therein; and

(b) Whether it is also fact that the mot of the buildings of Veterinary Hospitals/Dispensaries of above said Block are in dilapidated condition; if so, the time by which the afroesaid buildings are likely to be repaired?

प ़ुपालन राज्य मंत्री (राव धर्मपाल):

(क) जी नहीं, केवल मात्र 1 प ़ु हस्पताल एवं प्रजनन केन्द्र तथा 12 प ़ु औशधालय, बिना प ़ु चिकित्सक/प ़ुधन

विकास सहायक (वी० एल० डी० ए०) के हैं। इन पदों को भरने
बारे पग उठाए जा रहे हैं।

(बी) जी हां, उनकी हालत अच्छी नहीं है। पंजु
हस्पतालों/औशधालयों के भवनों की मुरम्मत हेतु धनराशि
उपलब्ध होते ही कार्यवाही की जाएगी।

**Construction of Water works all Village Rupawas and
Arnianwali**

177. Sh. Mani Ram Rupawas: Will the Minister for
Public Health be pleased to state—

(a) Whether the construction work of water works of
village Rupawas an Arnianwali of Distt. Sirsa are lying
incomplete; and

(b) If so, the time by which the work on the
aforesaid water works is likely to be completed?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री रामपाल सिंह कंवर):

(क) जी हां।

(ख) रूपावास का जलघर दिनांक 22.12.94 तक तथा
अरनियावाली का जलघर 9/94 तक पूर्ण हो जायेगा।

कथित विशेषाधिकार भंग का प्रश्न

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैंने आपकी सेवा में आज ही हमारे सदन के नेता चौधरी भजन लाल के खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन दिया है।

श्री अध्यक्ष: आपने यह प्रिविलेज मोशन कितने बजे दिया है?

श्री कर्ण सिंह दलाल: मैंने 11.45 बजे दिया है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपने 12.45 बजे दिया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, हाउस में पिछले दिनों मनोज कुमार मण्डल के बारे में चर्चा हुई थी, उस समय चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि धनिक लाल मंडल का कोई मामला नहीं है। लेकिन स्पीकर साहब, मैंने काफी भागदौड़ करके हमारे महकमें के कागज इकट्ठे किए हैं और मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुख्य मंत्री महोदय ने राज्यपाल महोदय की नजरों में अपनी छवि बनाने के लिए सदन के समक्ष जो स्टेटमेंट दी, वह गलत थी। यह मनोज कुमार मण्डल, जिनके पिता का नाम हरिकिशन मण्डल है, उनका एफिडेविट स्पीकर साहब, एक जगह नहीं, 3 जगह हरियाणा प्रदेश के कार्यालयों में पड़ा हुआ है। यही नहीं, इससे भी बड़ा 3 जगह हरियाणा प्रदेश के कार्यालयों में पड़ा हुआ है यही नहीं, इससे भी बड़ा धमाका यह है कि जो मनोज कुमार मण्डल है, वह बैकवर्ड क्लास से संबंध रखता है स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री महोदय की कृपा से 500 रुपये

स्टाईपेंड लेने के लिए फार्म में बी० सी० को काट कर एस० सी० लिखा गया है। और 500 रुपये का स्टार्पेंड वह एक दो महीने का ले चुका है। जिसके चैक नं० व ड्राफ्ट नं० मेरे पास लिखे हुए है। स्पीकर साहब, यही नहीं, गवर्नमेंट कालेज के उन दिनों वहां पर हरिसिंह प्रिंसिपल हुआ करते थे जिन्होंने इस मनोज कुमार मण्डल के लिए सारे गलत रीके से काम किए। जब उस हरिसिंह का वहांसे तबादला हुआ तो मनोज कुमार मण्डल ने फरीदाबाद कालेज के दफ्तर से गवर्नर साहब के निवास स्थान पर टेलिफोन बुक करवाया जिसका नंबर बाकायदा वहां के रजिस्टर में दर्ज है ओर अक्सर, वहां के जो लैक्चरर है, उनको डराने धमकान का काम किया करत है, स्पीकर साहब, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जानबूझ कर हमारे जो प्रैस के भाई, उनमें अपनी छवि बनाने के लिए, इस दे 1 में ओर प्रदे ज्ञ में छवि बनान के लिए, इससदन को गुमराह किया है। स्पीकर साहब, यही हारे मुख्यमंत्री महोदय की आदत है। (विधन)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अभी आप सुनों कि मैं क्या कहने वाला हूं? (विधन) पहले आप सुनिए।

श्री अध्यक्ष: कर्ण सिंह, आपकी बात हो चुकी है। (विधन)

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर सहाब, जब मनोज कुमार मण्डल को 500 रुपये स्टार्पेंड ि 1 ड्यूल्ड कास्टस के नाम से दिए गए तो हरियाणा के अधिकारियों ने आडिट ओब्जेक्टिव इन लगाया

और उस आडिट ओब्जेक्टिव को नकारा करके उससे 500 रुपये का स्टार्टपैड दिया गया। स्पीकर साहब, जब रिजर्व बैंक का स्टार्टपैड लेना होता है, तो एस0 सी0 का सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है। वह व्यक्ति हरियाणा की जिस तहसील का रहने वाला है, वहां के उप-मण्डल अधिकारी (ना0) से सर्टिफिकेट लेना होता है, जिसे जाति प्रमाणपत्र कहते हैं। (विधन) स्पीकर साहब वह फार्म मैंने आपकी सेवा में दिया है। (विधन) इसमें एस0 डी0 एम0 का कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया गया है। (गोर)

चौधरी भजन लाल: आप सुनेगे तो पता लगेगा। (गोर) अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे पहला निवेदन यह है कि अगर कोई आदमी हाउस में गलत प्रिविलेज मोशन दे तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही होनी चाहिए? (विधन) एक तो इस बारे में मैं आपको रूलिंग चाहूंगा कि कोई गलत स्टेटमेंट दे तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही होनी चाहिए? दूसरे, जो इन्होंने कहा है, उसके लिए मेरा चैलेंज है या तो ये सदन से इस्तीफा दे देगे या मैं दे दूंगा अगर मनोज कुमार गवर्नर साहब हापोता है और उसके बाप का नाम हरिकिशन है। गवर्नर साहब के किसी बेटे का नाम हरिकिशन नहीं है। गवर्नर साहब के दो बेटे हैं और इन दोनों बेटों का नाम हरिकिशन नहीं है। आज कोई आदमी लिख से सन आफ भजन लाल। भजन लाल एक ही है दे। मैं क्यात्र कोई लिख दे जवाहरलाल नेहरू। गलती से नहीं लिखा, वह गलती कर बैठा, उसको जवाहर लाल नेहरू लिखना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय,

इस तरह से गलतब्यानी की है, गलत बात की है, हाउस को गुमराह किया है, इसलि ऐसे मेंबर के खिलाफ फौरन कार्यवाही होनी चाहिए। मेरा इस बात के लिए इनको चैलेंज है। (विधन)

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, क्या आपने वैरीफाई कर लिया? (विधन)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हाउस की कमेटी बनाइए। (गोर) वे गलत बात करते हैं, हाउस को गुमराह करते हैं। (गोर)

श्री मनी राम केहरवाला: यह हाउस में गलत ब्यानी कर रहे हैं, इनके खिलाफ प्रिवेलेज मो आना चाहिए। (गोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, यह मामला अखबारों में छपा था ओर अखबारों की हैड लाईन में जिस तरीके से छपा था, वह आपके सामने रखा गया है। (विधन)

चौधरी भजन लाल: स्पीकर सहाब, आप हाउस की कमेटी बनाइये। (गोर) पेपर की क्या बात है? (गोर)

श्री कर्णसिंह दलाल: स्पीकर साहब, आप इस मामले को प्रिवेलज कमेटी में एडमिट करिए। (गोर)

चौधरी भजन लाल: मनोज कुमार पोते का नाम नहीं, हरिकि उन बाप का नाम नहीं। (विधन) गवर्नर साहब के दो बेटे हैं, हरिकि उन नाम का उनका कोई बेटा नहीं है। (गोर)

चौधरी जगदी । नेहरा: ऑन ए प्वायंट ऑफ आर्डर।
स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय सदस्य ने यह कहा है कि मैंने पेपर देख कर यह मोशन दिया, जबकि आज यह कह रहे हैं कि मैंने बड़ी भागदौड़ करके सारे कागज इकट्ठे किए हैं। फरीदबाद एन० आई० टी० का एड्रेस लिया है और मनोज कुमार की फोटो भी इन्होंने ली है जिसको ये यहां पर दिखा रहे हैं, टेलीफोन किया है, उनका स्टार्डपैण्ड कन्सैशन जो हाता है, उसके कागल इन्होंने भागदौड़ कर हर चीज इकट्ठी की है। स्पीकर सर, यह सब किसके खिलाफ किया है? मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि और आपको तो पता ही है कि गवर्नर साहब के कण्डक्ट के बारे में यह असेम्बली किसी चीज को डिस्कस नहीं कर सकती। पालियामेंट प्रैजिडेंट के कण्डक्ट के बारे में और असेम्बली गवर्नर साहब के कण्डक्ट के बारे में कुछ नहीं कर सकती। उस भाक्स के बारे में इन्होंने बड़ी भागदौड़ की। अध्यक्ष महोदय माननीय मुख्य मंत्री जी के खिलाफ ये प्रिविलेज मोशन लाए है कि इन्होंने झूठी स्टेटमेंट दी है। स्पीकर साहब, इस तरह से जो आदमी गैर-जिम्मेदारी वाली बात करे, गलत ब्यानी करे, सारी बात गलत करे, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। स्पीकर साहब, आपसे मेरी दरखास्त है कि आप हाउस की एक कमेटी बना दीजिए। असेम्बली पार्टी वार्डज रेगुलेशन के मुताबिक 5 मैम्बर्स की एक कमेटी बना दीजिए और अगर उस कमेटी में ये बात गलत साबिल हो जाए तो कमेटी जो रिक्मेंड करें, उसके हिसाब से आगे कार्यवाही की जानी चाहिए। (विधन एवं भाोर)

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, आप यह बताइये कि क्या आप ऐफिडैविट देने के लिए तैयार हैं? (गोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर सर, ऐसा है कि ऐफिडैविट देने के लिए भी मैं तैयार हूँ। (गोर) स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो सुनिये। (विधन और भाोर) यह मामला जिस दिन उठा था, मैंने उस दिन भी कहा था। (विधन एवं भाोर) ऐफिडैविट देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। (विधन एवं भाोर)

श्री अध्यक्ष: मैंने सवाल किय है कि क्या आप ऐफिडैविट देने के लिए तैयार हैं? (गोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर सर, ये जो कागज है इनमें ऐफिडैविट पहले से ही लगा हुआ है यह ऐफिडैविट मेरा नहीं है, मनोज कुमार मण्डल के बा का है। (गोर) स्पीकर सर, यह जो मामला मनोज कुमार मण्डल के बारे में था आप इसको प्रिविसलैज कमेटी में डाल दीजिए। (गोर) प्रिविलेज कमेटी होती किस लिए है? (विधन एवं भाोर)

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, आप बैठिए। (विधन एवं भाोर) राम पाल सिंह जी आप क्या कहना चाहते हैं? (गोर)

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री राम पाल सिंह कंवर): स्पीकर साहब, प्रिविलेज मो उन लाने के लिए उसका बेस क्या होना चाहिए, इस पर मैं आपकी रूनिग चाहता हूँ? अध्यक्ष महोदय, कर्ण सिंह दलाल जी ने जब खुद प्रिविलेज मो उन मूव करने का प्रयास

किया है तो इन्होंने यह कहा कि प्रिविलेज मोशन लाने का हमारा बेस यह है कि हाउस को मिसलीड किया गया है अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा जैसे कि आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि कमेटी बना दी जाए और उसकी रिपोर्ट मंगवा ली जाए। यदि रिपोर्ट आने के बाद यह साबित हो जाए कि मैम्बर साहेबान ने प्रिविलेज मोशन मूव करते समय हाउस को मिसलीड किया है तो क्या यह प्रिविलेज मोशन मूव करने वाले के खिलाफ प्रिविलेज मोशन आ सकता है? (गोर) अध्यक्ष महोदय, हम चाहेगे कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन हाउस के अन्दर आए और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। (विधन)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिये। (गोर)

श्री अध्यक्ष: मैंने आपसे जो सवाल किया है, आप उसके बारे में कहिए। आपने उनके ऐफिडेविट का जिकर तो किया है। लेकिन आप अपना ऐफिडेविट देने के बारे में बताइए? (गोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैंने तो रूलज ऑफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट ऑफ बिजनैस के रूल 265 के तहत आपको दरखास्त दी है सदन की प्रिविलेज कमेटी बनी हुई है। (गोर)

चौधरी बंसी लाल: स्पीकर सर, श्री कर्ण सिंह दलाल प्रिविलेज मोशन लाए है मुख्य मंत्री जी ने चैलेन्ज किया है और साथ ही यह भी कहा है कि सदन के मैम्बरज की एक कमेटी बना दी जाए। इनकी बात ठीक है। सदन के पांच मैम्बरज की कमेटी बना दीजिए, उसको इन्क्वायरी कर लेने दीजिए ओर उसके बाद आगे की जो भी प्रोसीडिगज होगी, वह आप कर लें। (विधन एवं भाोर)

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, इनका ऐफिडैविट तो आना चाहिए। (गोर)

श्री धीर पाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, जब हाउस के मैम्बरों की कमेटी बनाई जा रही है तो फिर उसमें ऐफिडैविट की क्या बात रह जाती है? (गोर)

चौधरी बंसी लाल: स्पीकर सर, सदन में आज तक किसी भी मैम्बर का ऐफिडैविट नहीं लिया गया और प ऐफिडैविट लेने का कोई सवाल ही पैदा हाता है क्या आज तक सदन के किसी मैम्बर ने ऐफिडैविट दिया है? (गोर)

श्री सतबीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मुख्यमंत्री जीने ऐफिडैविट लेने की बात कही है कि ऐफिडैविट लिया जाए। क्या आज से पहले किसी ऐ ऐफिडैविट लिया गया है या किसी ने दिया हे? मै इनसे यह पूछना चाहता हूं कि अब यह क्यों मांगा जा रहा है, क्या सदन को गुमराह किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: कादयान जी, यह मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा, यह मैंने कहा है। This matter is under consideration and I will tell you tomorrow. Please take your seat. That matter is finished now.

ध्यानकर्षण सूचनाएं

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह मैटर तो आपने एक्सटैन्ट कर दिया है, लेकिन मुझे इस पर दो भाब्दकहने है।

श्री अध्यक्ष: अब आप इस पर नहीं कह सकते हैं, अगर आपको और कुछ कहना है तो कहें।

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हमारी प्रधानमंत्री जी के साथ एस० वाई० एल० के बारे में 19 तारीख को मीटिंग हो रही है परन्तु पंजाब के मुख्य मंत्री जी ने अखबार के मुताबिक कहा है कि 19 तारीख को कोई मीटिंग नहीं हो रही है। अब हरियाणा के मुख्य मंत्री ने कह दिया कि इस बारे में पंजाब के मुख्य मंत्री ने कहा है बल्कि यह 25 तारीख को होने जा रही है उन्होंने कहा है—

“Talking to reporters here, Mr. Beant Singh said that no meeting has been fixed for March 19 at Delhi for Discussion on the construction of the SYL Canal.

Further, it is written—

“Mr. Beant Singh said that he would go to Jalandhar on March, 19, to attend function and was not aware of any meeting to be held in Delhi on that day.”

तो स्पीकर साहब, यह जो एक अहम खबर अखबार में निकली है, इससे यह साबित होता है कि यह सरकार सीरियस नहीं है और लोगों को गुमराह कर रही है।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, यह मीटिंग पहले 19 तारीख को ही तय हुई थी लेकिन हमारे पास टैलेक्स आया कि अब मीटिंग 19 तारीख की बजाय 25 तारीख को होगी। यह रिकार्ड की बात है और टैलेक्स हमारे पास है। अगर आप चाहे तो पढ़ लेना।

चौधरी बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, हमने आत एक कालिंग अटैन्डान्स दी है। अध्यक्ष महोदय, कल के 14 मार्च, 1994 के इण्डियन एक्सप्रेस में एक खबर निकली है। यह खबर है कि ढूँढाहेड़ा गांव जो गुड़गांव जिले में है, वहां की 80 एकड़ से ज्यादा जमीन को हरियाणा के फाईनैन्सियल कमिशनर ने इन्तकाल को नामन्जूरी दे दी है। तो मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि नामन्जूरी किस हिसाब से दी गई है? यह खबर अखबार में बहुत ही डिटेल् में लिखी गई है कि इनफ्लूएन्सियल आदमियों के हाथ में आज हकूमत है, वे उस जमीन को हडपना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक जमावन्दी की जिरोकसकापी है। इसमें एक हवाला दिया गया है कि तबदील मजलकयीत रैजुले

नं० 3, 05.05.79 चिट्ठी नं० एस० आई० 590/707-10 डेटिड 30-01-90 हैं इसमें एम० के० मिगलानी, कमी इनर एंड सैक्रेटरी आफ हरियाणा सरकार डिप्लोमैट एंड पंचायत हैं अध्यक्ष महोदय, जब यह इन्तकाल दर्ज हुआ ओर जब यह जमीन पंचायत से लेकर टूरिज्म डिपार्टमेंट के नाम पर की गई तो पंचायत ने रेजुले इन पास किया होगा क्योंकि इसमें भी रेजुले इन का हवाला है, एम० के० मिगलानी के हुक्म का हवाला है और यह दर्ज किया गया है। खैर, यह बडत्रे ही ताज्जुब की बात है कि यहजो इन्तकाल तसदीक होने की तारीख है, यह एक जगह तो पहले मन्जूर की गई है ओर बाद में नामंजूर कहा गया है। उसमें स्याही भी दो तरह की प्रयोग हुई है, यह बतात है यह मुझे सही नहीं मालूम लेकिन एक बात का मुझे सही मालूम है कि इस इन्तकाल की तारीख एक जगह 10 तथा दूसरी जगह 11 लिखी हुई है और तीसरी जगह 25.03.92 लिखी हुई है तो मरी समझ में यही बात नहीं आयी कि तहसीलदार तो एक ही दस्तखत करवो वाला है, फिर उसके एक दिन में तीन तारीखों में दस्तखत कैसे हो गये? दस्तखत एक जगह है, तारीख तीन जगह है तथा तारीखे भी तीन अलग अलग है तो यह जमीन हड़पने की कोशिश क्यों की जा रही है? इस इंडियन ऐक्सप्रेस अखबार की रूह से ऐसा लगता है कि पंचायत ने अन्डर प्रोटेस्ट रूपया लिया था और अगर पंचायत ने अन्डर प्रोटेस्ट रूपया लिया ही था तो सवाल सिर्फ इतना ही था कि कीमत उतनी हो या कीमत उससे ज्यादा। अगर ज्यादा हो तो कीमत बढ़ायी जा सकती थी। सरकार कीमत बढ़ाकर पंचायत को

दे सकती थी। अध्यक्ष महोदय, इस जमाबंदी से साफ जाहिर हो गया है कि इन्तकाल दर्ज हुआ। उसमें बाकायदा कमि नर डिवैल्पमेंट की चिट्ठी का हवाला है, फिर यह इन्तकाल नामंजूर करने की नौबत कैसे आयी? श्री एम० के० मिगलानी ने अपनी मर्जी से ही बगैर पंचायत के प्रस्ताव के हुक्म भेज दिया क इस जमीन का इन्तकाल टूरिज्म डिपार्टमेंट के नाम कर दे। अध्यक्ष महोदय, यह कैसे हो गया? श्री मिगलानी के खिलाफ क्या ऐक्शन लिया गया। अध्यक्ष महोदय, यह कागजों की मैनुपलेक्चर है, फ़ैब्रीकेक्चर है या सच्चाई है तो इस विषय पर सरकार एक खुलासा ब्यान दें।

प्र० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, जो इ. पू. चौधरी बंसी लाल जी ने उठाया है, इसमें दो तीन कंट्राडिक्शन भी हैं। पहली तो यह है कि जो पंचायत ने रैजोल्यूशन पास किया कि हमें जमीन नहीं बेचनी है और उनको मंजूरी भी मिल गयी बेचने की, और उसके बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी वह जमीन दस हजार रूपए एकड़ के हिसाब से ले ली। पंचायत ने मुआवजा अन्डर प्रोटेस्ट लिया। बाद में लोग कोर्ट में भी चले जाते हैं और अनकों फालतू मुआवजा मिल भी जाता है लेकिन बाद में जब इस जमीन का इन्तकाल हो गया तो उसके बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट के एक ज्वाइंट सैक्रेटरी ने डी० सी० को चिट्ठी लिखी कि हमें खदशा है कि इस जमीन का इन्तकाल खारिज करवाय जा रहा है और इस को खुर्दबुर्द करने का लोग प्रोग्राम बना रहे हैं डी० सी० ने लिखा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि इन्तकाल नहीं हुआ

है। स्पीकर साहब, यह तो डी० सी० का ब्यान हो गया लेकिन इसके बाद में कमि 1नर साहब ने एफ० सी० आर० के लिए लिखा दिया और उन्होंने कहा है कि यह आपके अधिकार क्षेत्र में है। स्पीकर साहब, जब यह फैसला हो गया कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में है, फिर पता नहीं उनको रात में सोकर सुबह जाग आ गयी और पता लगा कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है बल्कि स्वयं मेरे अधिकार क्षेत्र में है। इसके बाद उन्होंने वापस कागज मंगवा लिए ओर स्वयं ही इन्तकाल खारिज करने के आर्डर कर दिए। स्पीकर सर, एक तकफर तो डी० सी० ने कहा है कि इन्ताकल नहीं हुआ और दूसरी तरफ खारिज करने के आर्डर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ न कुछ स्मैल जरूर आ रही है। इसलिए सरकार को ऐक 1न लेना चाहिए ताथा इसकी इंकवायरी करवानी चाहिए कि कौन लोग हैं, ताकि पता लग सके कि क्या मामला है? क्योकि टूरिज्म डिपार्टमेंट को 80 एकड़ लैण्ड देने का फैसला कर दिया और उसने वह जमीन ले ली थी तथा वहां पर उन्होंने हटस वगैरह बना लिए थ, कुछ काम कर लिया था तथा बाढद्य वगैरह भी लगा दी थी। स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी भी उस रास्ते से आते जाते रहते हैं। दिल्ली और गुड़गावं के बौर्डर पर बकायदा टूरिज्म विभाग का बोर्ड लगा रहता है, हम यहां पर कोई क्वे 1नल सैन्टर या पर्यटन स्थल बनाने जा रहे हैं। स्पीकर साहब, इसमें कोई दो दाय नहीं है कि वह दिल्ली के पास है और टूरिज्म के लिए वह स्पौट अच्छी है। इससे तो हमारे टूरिज्म को ही प्रोत्साहन मिलता, लकिन इस तरह से ऐसा लगता है कि

सरकार टूरिज्म को एनकरेज न करके डिसकरेज करना चाहती हैं इसलिए जो लोग इस मामले के पीछे हैं, उनको पकड़ने के लिए सरकार को इस मामले की इंक्वायरी करवानी चाहिए ओर उन लोगों को पब्लिक के सामने लाना चाहिए जिन्होंने गड़बड़ की है। इसके साथ ही मुख्य मंत्री जी को टूरिज्म विभाग को यह लैण्ड देने के लिए अपनी कमिटेमैन्ट भी करनी चाहिए कि टूरिज्म विभाग के पास ही यह लैण्ड रहेगी।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं असलियत बताना चाहता हूँ ताकि आपको और हाउस को भी पता लग सके। अध्यक्ष महोदय, जब सम्पत सिंह ओर ओम प्राक 1 चौटाला का राज था, जब की इस जमीन की बात है। वह डूंडाहेड़ा की जमीन मु 1 तरका मालकान की जमीन थी और यह मु 1 तरका मालकान की जमीन पंचायत में वैस्ट हो गयी। इन्होंने य जमीन पंचायत से दस हजार रूपये एकड़ के हिसाब से धक्के से टूरिज्म विभाग के नाम करवा दी। जबकि पंचायत यह जमीन नहीं देना चाहती थी। उन्होंने इसके लिए प्रोटेस्ट भी किया। मालकान ने कहा कि जमीन हमारी है, हम पंचायत को नहीं देगे। झगड़ा चलता रहा, इन्होंने क्या किया कि 18 एकड़ जमीन प्रका 1 सिंह बादल को कौड़ियों के भाव में दे दी। यह रिकार्ड की बात है इन्होंने चौधरी देवी लाल के धर्म भाई को वह जमीन दे दी। उस जमीनका भाव 10 से 15 लाख रूपये प्रति एकड़ से कम का नहीं था। (ओर एवं व्यवधान)

चौधरी बंसी लाल: आपने जमीन का दाम क्या बताया है?

चौधरी भजन लाल: 10 से 15 लाख रुपये एकड़ कम से कम है।

चौधरी बंसी लाल: इससे भी कहीं ज्यादा है।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, भजन लाल ने जिन्दगी में किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। मिनिस्टर बने हुए इतने साल हो गए हैं, किसी एग्रीकल्चर इन्स्पैक्टर ने मेरे खेत को जाकर नहीं दिखा। नहर भी खेत से निकलती है, कोई यह भी नहीं कह सकता कि भजनलाल न बगली कर ली या पाईप डाल दिया। भजन लाल के कभी कोई गलत काम नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि मालिकान ने अपील दायर कर दी कि हमारा हक है, जमीन हमारी है अब जुडि़ियल केस है, कमिशनर ने जो कुछ फैसला किया है, जुडि़ियल नेचर के हिसाब से क्या है, मैंने फाईल परआड किए हैं कि फौरन अपील दायर करो। जहां तक जमीन छोड़ने का सवाल है, कम से कम वो बात कहनी चाहिए जिसके पीछे कुछ सच्चाई हो य हेरफेर की बात हो। हमने न तो हेराफेरी कभी की है, न करने की सोच भी सकते हैं।

चौधरी बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने बड़े संक्षेप में जवाब दे दिया जिससे ऐसा लगा जैसे कोई झगड़ा ही न

हो। अध्यक्षमहोदय, इसमें एक बात यह है कि इन्तकाल दर्ज हो गया और यहां से कमि रन ने कहा कि इसको ट्रांसफर कर दो टूरिज्म डिपार्टमेंट के नाम। क्या कमि रनर को इस बात का अधिकार है कि जमीन का मालिक कौन है, इस बात का फैसला करेगा इस बात का फैसला तो दीवानी अदालत करेगी या हाईकोर्ट करेगा कि जमीन का मालिक कौन है? टूरिज्म डिपार्टमेंट बराबर दर्खास्त देता रहा है क हमको इसमें पार्टी बनाओं, हमारा नाम इसमें से हटाया जा रहा है। (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल: बंसी लाल जी, आप ऐसी बात करते हो जैसे वाय भटिडा वकील बनकर आए हो। जमीन केकेस एस0 डी0 एम0 से लेकर एफ0 सी0 आर0 तक जुडी रिगल नेचर के होते हैं।

चौधरी बंसी लाल: मुख्यमंत्री जी, आप तो भैरों सिंह भोखावत से पी0 एच0 डी0 की डिग्री लिए बैठे थे और जब ये जयपुर गए तो भैरा सिंह जी ने इनसे यह डिग्री छीन ली। (गोर)

चौधरी भजन लाल: किसी अनपढ़ आदमी से भी पूछोगे तो बताएगा कि जमीन के केसिज, रैवेन्यू केसिज चाहे तहसीलदार के पास हो, चाहे डी0 सी0 के पास हो, जुडी रिगल नेचर के होते हैं। इसी तरह नम्बरदार के पास के केसिज हो तो वे भी जुडी रिगल नेचर के होते हैं। आपकी पार्टी में भी एक दो वकील हैं। (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। मैं भी यह बात जानता हूँ कि जमीन के केस एफ0 सी0 आर0 तक जुड़ि गयल नेचर के होते हैं मगर ट्राइबल का फैसला सिविल कोर्ट करेगी, रैवेन्यू कोर्ट नहीं कर सकती।

चौधरी भजन लाल: जब इन्तकाल का कोई झगड़ा हो तो रैवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा और ये केसिज एफ0 सी0 आर0 तक जाते हैं। एफ0 सी0 आर0 के बाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। कोर्ट ने जो फैसला किया है वह जुडी गयल नेचर के हिसाब से किया है हम उसके खिलाफ अपील में जा रहे हैं। सरकार इसके खिलाफ टूरिज्म डिपार्टमेंट की तफ से अपील में जा रही है। जो हम कर सकते हैं, वह अवश्य करेंगे।

श्री धरीपाल सिंह: जमीन खुर्द-बुर्द तो नहीं होगी?

चौधरी भजन लाल: जमीन खुर्द बुर्द होने का तो कोई सवाल ही नहीं है।

प्रो० छतर सिंह चौहान: स्पीकर सर, अभी आरणीय मुख्य मंत्री महोदय ने बताया है कि कमिशनर फैसला करसकता है। मुख्य मंत्री जी के पड़ोस में नेहरा साहब बैठे हैं, वह भी वकील है। उनसे बेतक वह पूछले, इनको पता चल जायेगा। उस समय जुलाई, 1993 में कमिशनर श्री पी0 पी0 छाबड़ा थे।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, यह जुडी टायल नेचर का केस है, क्या इसको यह पर डिस्कस किया जा सकता है?

श्री अध्यक्ष: नहीं।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से बोल रहा हूँ। मैं एक बात जानना चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय को भायद यह पता नहीं होगा कि जो कमि नर है, उन्होंने अपना एक आर्डर जुलाई, 1993 में फाईनै टायल कमि नर रैवेन्यू को भेज दिया। मुख्यमंत्री महोदय यह बताये कि अगर कोई कमि नर फैसला खुर कर दे तो क्या उसको वह खुद ही रिव्यू कर सकता है? रिव्यू के मामले में रैवेन्यू की कोई किताब यह पढ़ लें तो बेहतर होगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह तसल्ली करके और किताब पढ़ कर जवाद दें। मैं दावे के साथ यह कह सकता हूँ कि कमि नर ने जो फैसला करके फाईनै टायल कमि नर को भेज दिया, वह उसको अपने आप रिव्यू नहीं कर सकता।

चौधरी बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से पोजी न थोड़ी सी क्लीयर कर दूँ। इस अखबार में ये क्लीयर कट लिखा हुआ है कि कमि नर ने फैसल करके फाईनै टायल कमि नर को भेज दिया। फाईनै टायल कमि नर रैवेन्यू के पास यह फैसला जाने के बाद, क्या कमि नर उस फैसले को दोबारा

खुद मंगा सकता है और रिट्यू करसकता है य फाइनें ियल कमि ानर उसको वापिस भेजेगा?

चौधरी भजन लाल: जो भी बात कानून के मुताबिक ठीक होगी, वही होगी। मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि हम किसी को उस जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखने देगे।

Mr. Speaker: It is a sub-judice matter and interpretation of law is involved. Therefore, no further discussion will be allowed on this matter.

साथी लहरी सिंह: सर, मेरा एक काल अटै ान मो ान था।

श्री अध्यक्ष: किस बारे में?

साथी लहरी सिंह: पोटेटों क्राप के बारे में था।

श्री अध्यक्ष: यह अभी अंडर कंसीड्रे ान है, कमैट्स के लिए सरकार के पास भेजा हुआ है।

साथी लहरी सिंह: सर, यह कब तक अंडर कंसीड्रे ान रहेगा?

श्री अमरी चन्द मक्कड़: सर, मेरा भी एक काल अटै ान मो ान था।

श्री अध्यक्ष: आपका काल आटै न मो न तो आज सवा एक बजे आया है। यह भी अंडर कंसीड्रे न है

ध्यानकर्षण प्रस्ताव—

भिवानी भाहर में पीलिया का रोग फैलने सम्बन्धी

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of calling attention motion No. 11, given notice of by Sarvshri Ram Bhajan Aggarwal and Chhattar Singh Chauha, M.L.As. regarding breadking out of jaundice in Bhiwani City. I have admitted it. Sh. Ram Bhajan Aggarwal may read his notice and thereafter the Health Minister may make a statement thereon.

श्री राम भजन अग्रवाल/प्रो० छत्तर सिंह चौहान: मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्याव यक लोक महत्व के विशय की ओर दिलाना चाहता हूं कि भिवानी भाहर में पीलिया फैला हुआ है तथा सैकड़ों व्यक्ति इस बीमारी के ितकार है तथा इस बात का डर है कि यह एक महामारी का रूप धारण कर सकती है। यह नागरिकों को सिवरेज खराब होने के कारण दूशित पीने का पानी सप्लाई करने के कारण से है।

अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस संबंध में सदस्य में एक वक्तव्य दें।

वक्तव्य—

**स्वास्थ्य एवं आयुर्वेदा मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानकर्षण प्रस्ताव
संबंधी**

स्वास्थ्य एवं आयुर्वेदा मंत्री (श्रीमती भान्दि देवी राठी):
अध्यक्ष महोदय, भिवानी में पीलिया के 144 मामले प्रकाश में आए हैं। जिनमें से 11 मामले दिसम्बर, 1993 के अन्तिम सप्ताह में, 75 मामले जनवरी, 1994 तक 58 मामले फरवरी, 1994 में प्रकाश में आए हैं। कोई मृत्यु का मामला प्रकाश में नहीं आया है।

इस बीमारी की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं—

1. पीने के पानी का उचित क्लोरीनेशन सुनिश्चित किया जा रहा है।

2. भिवानी भाहर में घर-घर में पीलिया के मामलों का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण करने, स्वास्थ्य शिक्षा देने, ड्रिंकवैल गोलियों को वितरित करने एवं पीने का पानी में क्लोरीन अंश की उपस्थिति की जांच करने के लिए आठ पैरा मैडीकल टीमों का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त बिड़ला टैक्सटाईल मिल तथा टैक्नोलोजिकल इन्स्टीच्यूट आफ टैक्सटाईल की कालोनियों के लिए चार अन्य टीमों भी लगाई गई हैं।

3. मास जनवरी, 1994 में सर्वेक्षण के दौरान पाया गया है कि पीलिया के अधिकतर मामले बिड़ला टैक्सटाईल मिल तथा टैक्नोलोजिकल इन्स्टीच्यूट आफ टैक्सटाईल की कालोनियों एवं

आसपास के क्षेत्रों में पाये गए है। रिपोर्ट के अनुसार इन कालोनियों की जल आपूर्ति बिड़ला टैक्सटाईल मिल एवं टैक्नोलोजिकल इन्स्टीच्यूट आफ टैक्सटाईल में स्थित पानी के टैंकों से होती है। इन स्टोरेज टैंकों में पानी की आपूर्ति जन स्वास्थ्य स्त्रोतों एवं टयूबवैलों से मिल अथोरिटिज के टैकरों द्वारा की जाती है।

4. जनवरी, 1994 में पानी में रेजिडुअल क्लोरीन की जांच के लिए पानी के 25 नमूने लिए गए तो सभी नेगेटिव पाये गये। जनवरी तथा फरवरी 1994 में जन स्वास्थ्य विभाग बिड़ला टैक्सटाईल मिल तथा टैक्नोलोजिकल इन्स्टीच्यूट आफ टैक्सटाईल के अधिकारी से निवेदन किया गया था कि पानी की सुपर क्लोरीनेशन की जाए। तत्पश्चात् पीने के पानी के रेजिडुअल क्लोरीन टैस्ट करने हेतु फरवरी, 1994 में 32 नमून लिए गए जो सभी पोजिटिव पाये गए।

5. पानी को उबाला कर पीने की आवश्यकता पर बल दिये जाने हेतु सभी को स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है। पानी से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए जन चेतना हेतु जगह जगह पर पोस्टर्ज लगाये गए हैं इस सम्बन्ध में हिदायतों सहित हैण्ड बिल्ज भी वितरित किये गए।

6. सभी पीने के पानी के स्रोतों की क्लोरीनेशन के अतिरिक्त 7000 ड्रिंकवेल गोलिया पानी की क्लोरीनेशन के लिए घर-घर में बांटी गई हैं

7. जन स्वास्थ्य विभाग के प्राधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार भिवानी भाहर में उन द्वारा मास दिसम्बर, 1993, जनवरी तथा फरवरी, 1994 के दौरान 165 पानी के कनेक्शनों को ठीक किया गया।

8. जन स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जन स्वास्थ्य विभाग के प्राधिकारियों द्वारा दिसम्बर, 1993 तथा जनवरी, 1994 में एक सर्वेक्षण किया गया, जिसके अनुसार म्यूनिसिपल मेन से घरों तक जाने वाली जी० आई० पाईपे जो 10-15 साल या इससे अधिक पुरानी हो गई है तथा गल चुकी है, उन्हें बदलने की आवश्यकता है यह कहार्य उन द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

श्री राम भजन अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, सब से पहले जो मैं जौन्डेस के लिए इनसे यह पूछना चाहता हूँ कि जो आंकड़े इन्होंने दिये हैं, वे सत्य नहीं हैं। सी० एम० ओ० ने 86 कंसेजस्वॉय एडमिट किए हैं लेकिन मंत्री महोदय जब अपना जवाब पढ़ रही थी तो उनके आंकड़ों से सी० एम० ओ० के आंकड़ों से डिफर करते थे। क्या मंत्री महोदय इसबारे में दोबारा सर्वे करवाएंगी ताकि उनकी सही पोजीशन का पता चल सके? लोगों के घरों

तक जाने वाले पानी का पाईप जो 10-15 साल सा इससे अधिक पुरानी हो गई है तथा गल चुकी है उनके बारे में सरकार ने कहा है कि उन्हें बदलने की आवश्यकता है और साथ ही जवाब के अन्त में यह भी कहा है कि यह कार्ग प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि लोगों को इस भयंकर रोग से बचाने के लिए क्या सरकार इस काम के लिए कोई समय निर्धारित करेगी ताकि निश्चित समय के अन्दर अन्दर यह सारा काम हो सके? दो महीने, चार महीने, या छः महीने, कत तक सरकार इसकाम को करवा देगी ताकि लोगों को भिवानी भाहर के अन्दर पीने का शुद्ध पानी मिल सके? मेरा आपके द्वारा सरकार से निवेदन है कि सरकार कब तक गली सड़ी सवीरेज की पाईपों को निकलोगी जो कम से कम 14-14, 15-15 सालों से खराब पड़ी हुई है, जिनकी वजह से गन्दा सीवरेज का पानी पीने के पानी में मिलकर दूषित हो जाता है। लोग उस पानी को पीते हैं और बीमार हो जाते हैं, कब तक उन गली सड़ी पाईपों को सरकार बदल देगी?

श्रीमती भान्ति देवी राठी: स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने तो पूरा भाषण ही दे डाला। मैंने पहले ही यह स्वीकार किया है कि भिवानी में पीलिया के 144 मामले प्रकाश में आए हैं। इस बारे में शिकायतें मिलीं हैं और इन सब बातों का हमने पहले ही विस्तार से जवाब दे दिया है, किसी प्रकार से हाउस को गुमराह करने वाली बात नहीं है। मैं आपने माननीय सदस्य को

बताना चाहती हूं कि पानी के मामले में चाहे हमारे विभाग की कोई भी अनियमितता हो, जन-स्वास्थ्य विभाग से जो भी अनियमितताएं हुई हो, उन का हम फौरन नोटिस लेते हैं और तुरन्तु आवश्यक कार्यवाही की जाती है ताकि पीलिया जैसे भयंकर रोग से लोगों को बचाया जा सकते। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, इनहोने बोलते हुए सरकारी आंकड़ों को भी गलत बताया। मैं इनको बता देना चाहती हूं कि कोई भी आंकड़ा जो हमने बताया है, असत्य नहीं है। सभी सत्य हैं यदि माननीय सदस्य महोदय चाहें तो सारी डिटेल्स में उनको बता सकती हूं। अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं बतानी चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय, जिला भिवानी में पीलिया के केसों का क्षेत्रवार ब्यौरा इस प्रकार है— 17 कालोनियों में पीलिया के 137 केस हुए तथा 7 केस आस पास के गांवों में हुए। इस तरह कुल 144 केस जिला भिवानी से रिपोर्ट हुए। क्षेत्रवाइज स्थिति निम्नलिखित है:—

क्षेत्र का नाम	केसों की कुल संख्या
बिडला कालोनी	37
लबर कालोनी	20
डी0 सी0 कालोनी	11

टी० आई० टी० कालोनी	32
कच्ची कालोनी	6
चरणजी कालोनी	5
सेवानगर	7
ब्रिजवासी कालोनी	4
बैक कोठी	2
कृष्णा कालोनी	7
रूरा कालोनी	2
जगत कालोनी	1
हनुमान घनी	2
जैन चौक	1
चिडियामार मुहल्ला	1
नीयर मुरारी सिनेमा	1
दुर्गा कालोनी	2
ग्रामीण क्षेत्र	

हलुवास (हलुवास)	5
नथुवास	1
पालुवास	1

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, यह सब क्यो हुआ इस बारे में बहन जी ने बताया नहीं। यह जो सीवरेज है, यह आज का लगा हुआ नहीं है। यह चौधरी बंसी लाल जी के वक्त का लगा हुआ है और इन्होंने ऐसा घटिया माल वहां लगा दिया जिसकी वजह से जगह जगह लीकेज हो गईं ओर पीने के पानी में यह गन्दा पानी भामिल हो गया। इसी वजह से वहां पीलिया की गम्भीर बीमारी फैल गई। इसको अब हम जल्दी ही ठीक कर रहे हैं, सरकार इसके लिए पूरी तरह से प्रयत्न गील है। यह सब कुछ चौधरी बंसी लाल जी की मेहरबानी से ही हुआ है। (हंसी)

चौधरी बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय भायद किसी स्कूल या कालेज में पढ़े हैं या नहीं लेकिन ये अपने आपको राजनीति के पी० एच० डी० कहते हैं। जब ये राजस्थान में गये तो भैरो सिंह भोखावत ने इनकी पी० एच० डी० की डिग्री छीन ली (हंसी) अध्यक्ष महोदय, जो सीवरेज स्कीम हमारे वक्त में बनी थी, उस में कोई ऐसी बात नहीं थी। सीवरेज का फायदा होता है कि हर साल में दो बार उसको साफ किया जाए लेकिन 6-6 महीने साल से ऊपर का समय बीत चुका है ओर इस सरकार ने

सीवरेज कोसाफ तक नहीं करवाया स्वाभाविक है सीवरेज रूकेगा ही। अब जमीन का पानी ऊपर आ गया है, पहले वह साठ—सत्तर फुट पर था और अब पांच फुट पर आ गया है। जब यह उसकी सफाई नहीं करवायेगे तो यह ठीक काम कैसे करेगी? आजकल वैसे भी प्लास्टिक के लिफावे आ गये हैं, गर किसी ने सब्जी भी लानी है तो प्लास्टिक के लिफाफे में डालकर दी जाती है। ये लिफाफे गिरने से भी सीवरेज बन्द हो जाता है। इसके बावजूद भी इनहोने सीवरेज की सफाई की जरूरत नहीं समझी। स्पीकर साहब, सफाई कैसे हो क्योंकि जो मैन्टीनेंस का पैसा है, वह तो जेबों में चला जाता है।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इनको हमें आ इस बात का फोबिया रहता है। चौधरी बंसी लाल जी, आप इतने पुराने मैम्बर है, कोई बात तो ठीक करों। हमने इसकी वाकायदा सफाई करवाई लेकिन मैटीरियल इतना घटिया लगा हुआ है कि वह ठीक होने की नहीं आ रहा है।

वर्ष 1994—95 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now discussion and voting on the demand for grants on budget for the year 1994-45 will take place. As per past practice and to save the time of the House, all the demands on the order paper will be deemed to have been ready and moved. The Hon. Members can discuss

any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise the discussion.

That a sum not exceeding Rs. 27907000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No. 1-vidhan Sabha.**

That a sum not exceeding Rs. 555298000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No. 2-General Administration.**

That a sum not exceeding Rs. 1397909000 revenue expenditure and Rs. 45000000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No 3-Home.**

That a sum not exceeding Rs. 348568000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No 4-Revenue.**

That a sum not exceeding Rs. 145786000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No. 5-Excise & Taxation.**

That a sum not exceeding Rs. 1397909000 revenue expenditure and Rs. 45000000 for capital expenditure be

granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No. 6-Finance.**

That a sum not exceeding Rs. 13612546000 revenue expenditure and Rs. 1050000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No. 7-Other Administrative Services.**

That a sum not exceeding Rs. 861452000 revenue expenditure and Rs. 817760000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No. 8-Buildings & Roads.**

That a sum not exceeding Rs. 5059358000 or revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No. 9-Education**

That a sum not exceeding Rs. 3289457000 revenue expenditure and Rs. 463800000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No. 10-Medical & Public Health.**

That a sum not exceeding Rs. 138618000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No. 11-Urban Development.**

That a sum not exceeding Rs. 299694000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No. 12-Labour & Employment.**

That a sum not exceeding Rs. 1397909000 revenue expenditure and Rs. 45000000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No. 13-Social Welfare & Rehabilitation.**

That a sum not exceeding Rs. 7.933600 revenue expenditure and Rs. 3444725000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No. 14-Food and Supplies.**

That a sum not exceeding Rs. 9961550000 revenue expenditure and Rs. 1340700000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No. 15-Irrigation.**

That a sum not exceeding Rs. 301028000 revenue expenditure and Rs. 109711000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No. 16-Industries.**

That a sum not exceeding Rs. 1216747000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year

1994-95 in respect of charges under **Demand No. 17-Agriculture.**

That a sum not exceeding Rs. 374000000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No. 18-Animal Husbandry.**

That a sum not exceeding Rs. 44911000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No. 19-Fisheries.**

That a sum not exceeding Rs. 48.80.70.000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No. 20-Forest.**

That a sum not exceeding Rs. 173290000 revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No. 21-Community Development.**

That a sum not exceeding Rs. 139454000 revenue expenditure and Rs. 86109000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No. 22-Cooperation.**

That a sum not exceeding Rs. 2548392000 revenue expenditure and Rs. 379300000 for capital expenditure be

granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No. 23-Transport.**

That a sum not exceeding Rs. 8502000 revenue expenditure and Rs. 26000000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No. 24- Tourism.**

That a sum not exceeding Rs. 3233897000 revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No. 25-Lowans & Advances by State Govt.**

I have also received notices of cut motions to the various demands from some M.L.As. These will also be deemed to have been read and moved. However, I will put the various cut motions to the vote of the House when the respective demands are put to the vote of the House. Such members may, however, participate in the discussion.

Demand No. 2

1. Sh. Bansi Lal,
2. Sh. Karan Singh Dalal,
3. Sh. Chhattar Singh Chauhan; and
4. Smt. Janki Devi, M.L.As.

That demands No. 2 of Rs. 568399000 on account of General Administration be reduced by Re. 1/-,

Demand NO. 3

1. Sh. Bansi Lal,
2. Sh. Ram Bhajan,
3. Sh. Karan Singh Dalal and
4. Sh. Attar Singh, M.L.As

That demands No. 3 of rs. 2039319000 on account of Home be reduced by Re. 1/-

Demand No. 5

1. Sh. Ram Bhajan, M.L.A;

That Demand No. 5 of Rs. 145796000 on account of Excise & Taxtion be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 6

1. Sh. Chhattar Singh Chauhan, M.L.A.;

The Demend No. 6 of Rs. 6748389000 on account of Finance be reduced by Re. 1/-.

Demand NO. 7

Sh. Chhattar Singh Chauhan, M.L.A.:

That Demand NO. 7 of rs. 10615476000 on account of other administrative Servgices be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 8

1. Sh. Chhattar Singh Chauhan,
2. Smt. Janki Devi and
3. Sh. Karna Singh Dalal, M.L.As.

That Demand No. 8 of Rs. 1679812000 on account of Building & Roads be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 9

1. Sh. Ram Bhajan,
2. Shrimati Janki Devi
3. Sh. Chhattar Singh Chauhan and
4. Sh. Attar Singh, M.L.As

That Demand No. 9 of Rs. 5059663000 on account of Education be reduced br Re. 1/-.

Demand No. 10

Sh. Om Parkash Beri, M.L.A.

That Demand No. 10 of Rs. 3754769000 on account of Medical & Public Health be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 11

Sh. Ram Bhajan, M.L.A.:

That Demand No. 11 of Rs. 138618000 on account of Under Development be reduced by Re. 1/-

Demand No. 15

Sh. Om Parkash Beri, M.L.A.:

That Demand No. 15 of Rs. 9961550000 on account of Irrigation Department be reduced by Re. 1/-.

1. Sh. Bansi Lal,
2. Sh. Karan Singh Dalal, and
3. Sh. Chhattar Singh Chauhan, M.L.As.

That Demand NO. 15 of Rs. 11305805000 on account of Irrigation be reduced by Re. 1/-

Demand No. 16

1. Sh. Bhajan, M.L.A:

That Demand No. 16 of Rs. 410779000 on account of Industries be reduced by Rs. 1/-.

Demand No. 17

1. Sh. Bansi Lal,
2. Sh. Karan Singh Dalal, and
3. Sh. Om Parkash Beri, M.L.As.

That Demand No. 17 of Rs. 1217897000 on account of Agriculture be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 22

1. Sh. Chhattar Singh Chauhan,

2. Sh. Karan Singh Dalal, M.L.As.

That Demand No. 22 of Rs. 225573000 on account of Cooperation Department be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 24

Sh. Bansi Lal, M.L.A.:

That Demand No. 24 of Rs. 8136686000 on account of Tourism be reduced by Rs. 1/-.

Now discussion will take place. Sh. Lehri Singh will speak on these demands first.

श्री सतबीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का समय दें।

श्री अध्यक्ष: अब तक जो बोल चुके हैं उनका पार्टीवाइज टाइम इस प्रकार है—

इंडियन नेशनल कांग्रेस 333 मिनट, एस0 जे0 पी0 210 मिनट, हरियाणा विकास पार्टी 125 मिनट, बी0 जे0 पी0 61 मिनट और बी0एस0 पी0 3 मिनट। अपोजीशन पार्टीज के सदस्य टोटल 399 मिनट बोले हैं और कांग्रेस के 323 मिनट।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन): अध्यक्ष महोदय, हम इंडिपैटस समेत 65 सदस्य हैं, इसलिए हमें दो तिहाई के लगभग समय मिलना चाहिए।

साथी लहरी सिंह (रादौरा, अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं डिमांड नं० 1, 3, 17, 18 और 22 पर बोलना चाहता हूँ। सब से पहले मैं विधान सभा के बारें में थोड़ा सा सुझाव दूंगा। स्पीकर साहब, मैं टेलीफोन के बारे में कहना चाहता था। टेलीफोन का सिस्टम बहुत खराब है।

श्री अध्यक्ष: यह आप अलग से पूछ ले।

साथी लहरी सिंह: ठीक है जम्। स्पीकर साहब, हमारे जमनानगर जिले में पुलिस पूरी इफैक्टिव है और अच्छा काम कर रही है लेकिन अगर साथ के इलाके में कोई घटना हो जाए तो पुलिस इफैक्टिव नहीं होती। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, जमनानगर जिले के साथ यू० पी० का इलाका लगता है। वहां पर बहुत बुरा हाल है जमनानगर का इलाका जो यू० पी० के डाकू हमला करके चले जाते हैं, किसी को मार कर चले जाते हैं और किसी को घायनलकरके चले जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐडमिनिस्ट्रेटिव की बात है इसलिए मेरा निवेदन है कि जमनानगर इलाके को अच्छा ऐडमिनिस्ट्रेटिव मिलना चाहिए। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है। उसको मुकाबला करने के लिए अच्छे साधन नहीं है। जमनानगर जिले के एस० पी० और डी० सी० साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पुलिस भी बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन पुलिस के पास अच्छे साधन नहीं है, जिसके कारण यू० पी० के डाकू हमारे लोगों पर हमला करके चले जाते हैं। मेरा

सरकार से निवेदन है कि पुलिस को अच्छे साधनों को इन्तजमा करवाएं ताकि पुलिस उन गुण्डों का मुकाबला कर सके। उन गुण्डों को यू0 पी0 की एडमिनिस्ट्रेटिव भाह देती है, प्रोटैक्टिव भाह देती है, जिसके कारण हरियाणा के इलाके के लोगों को मनोबल डाउन होता है। इसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, जमना नही पर जो ठोकरे लगाई हुई है, वे हमारी तरह 65 फुट की है लेकिन यू0 पी0 वालों ने अपनी तरह 125 फुट की ठोकरे लगाई हुई है जिसका सीधा असर हमारे इलाके पर पड़ता है। यू0 पी0 वाले जमना नही को हमारी तरफ काटने पर लगे हुए है। उनहोने 125 फुट लम्बी ठोकरे लगाई हुई है। जिसके कारण हमारे इलाके की उपजाऊ जमीन पानी के बहाव के कारण कट जाती हैं ऐसे हालत है कि हमारे उस इलाके के कई गांव बहने के कगार पर है। यू0 पी0 वालों ने 125 फुट लम्बी ठोकरें लगाई हुई है, परिणामस्वरूप हमारी काफी जमनी कट कट कर यू0 पी0 की तरफ चली गई हैं सरकार से मेरा निवेदन है कि हरियाणा सरकार सैट्रल गवर्नमेंट से बात करें और अनुरोध करे कि 65 फुट लम्बी ठोकरे लगाने का जा स्पैसिफिके भाह है, उसके हिसाब से ही ठोकरें लगानी चाहिए। हमारी सरकार को यह केस केन्द्रीय सरकार में प्लीड करना चाहिए ताकि हमारे इलाके की जमीन, हमारे इलाके के गांव बचाए जा सके। कई गांव तो इस समय बहने के कगार पर हैं उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह मुद्दा पहले भी उठाया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का बड़ा आभारी हूं कि सरकार ने वहां पर स्टेट हाईव, एक्सप्रेस हाईवे मंजूर किया है। वह सड़क जमनानगर से दिल्ली

जाएगी। मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां पर यू0 पी0 के जो गुण्डे हमारे इलाके के लोगों पर हमला करके चले जाते हैं, किसी को मार जाते हैं और किसी को घायल करके चला जाते हैं, उनके बारे में कोई न कोई इन्तजमा किया जाए वरना न सड़क रहेगी और न आबादी रहेगी। जमीन तो कट कट कर पहले ही जा चुकी हैं उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला ऐसा है जिसके बारे में सरकार को जरूर विचार करना चाहिए। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि कोई जुगाड़ नाम का व्हीकल आज सड़कों पर बहुत ज्यादा मात्रा में चल रहा है। न उसके ऊपर कोई नम्बर लिखा हुआ है और न ही कोई और बात है। अगर उनसे पूछते तो कहते हैं कि यह धक्का ट्रांसपोर्ट है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मेरी इस बात पर हंस रहे हैं। सबसे ज्यादा इन्हीं के इलाके में वह व्हीकल चल रहा है अगर वह व्हीकल किसी को एक्सीडेंट करके चला जाए तो किसी को मार कर चला जाए तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती क्योंकि उसके ऊपर कोई नम्बर नहीं लिखा है। यदि उसके पीछे कोई नम्बर वाली व्हीकल आ रही होती है तो एक्सीडेंट के मामले में उसका नम्बर नोट कर लिया जाता है और उसका खिलाफ कार्यवाही की जाती है लेकिन अगर किसी आदमी को जुगाड़ व्हीकल एक्सीडेंट करके मार जाता है और जो नम्बर वाली गाड़ी उसके पीछे आ रही होती है, उसका नम्बर नोट कर लिया जाता है तो यह बड़ी भारी त्रुटि है चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लैवल की बात हो, चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात हो, उनको तुरन्त बन्द किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं एग्रीकल्चर के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, जिसकी नीयत अच्छी होती है, उसको परमात्मा भी देखता है। हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने और एग्रीकल्चर मंत्री महोदय ने जो अपनी साफ नीयत से काम किया है, उसकी बदौलत हमारे यहां अनाज की रिकार्ड तोड़ पैदावार हुई है। पहले पजाब में सबसे ज्यादा पैदावार होती थी। मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हमारे एग्रीकल्चर विभाग की, सरकार की नीयत साफ होने की वजह से यहां पर फसल का रिकार्ड तोड़ उत्पादन हुआ और कुरुक्षेत्र जिला सारे देा में गेहूँ की पैदावार में सबसे प्रथम रहा। इनकी नीयत अच्छी थी इसलिए भगवान भी मेहरबान रहे ओर समय पर बारिा हुई। इस समय था जब इनकी सरकार आई तो उस समय एक बार तो सूखा पड़ गया और दूसरी बार बाढ़ से सारी फसल तबाह हो गई। इसलिए यह नीयत की बात होती है एग्रीकल्चर विभाग का कामकाज का तरीका बहुत अच्छा है इसलिए मेरा निवेदन है कि यह महकमा बागवानी और फ्रूट की पैदावार की तरफ भी ज्यादा ध्यान दे ताकि किसानों को अपनी फसल का अधिक से अधिक रेट मिल सके। हरियाणा सरकार ने हर फसल का सारे देा से अच्छा भाव अपने किसानों को दिया है। गन्ने के आगाजी सीजन के लिए अभी से हमारी सरकार ने 5 रूपए रेट बढ़ा दिया है ओर जब सीजन आयेगा तो और बढ़ा दिए जाएंगे। इसलिए हमारी सरकार इस दिा में काम भी कर रही है। ओर कोर्ािा भी कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सड़कों के बारे में जिकर करना चाहता हूँ। हमारे डांगी साहब की बतौर मंत्री परफोरमैस बहुत अच्छी रही है। इन्होंने बताया कि इतना बजट मांगा था लेकिन मांगे राम गुप्ता जी ने इतना पैसा दिया, इसलिए अब कसूर इनका न रह कर, मांगेराम जी का हर जाता है। इसलिए मेरी मांगे राम जी से प्रार्थना है कि वे जितना पैसा सड़कों की रिपेयर के लिए मांगते हैं, वह दे दिया जाए ताकि सारी सड़कों की मुरम्मत हो सके। इन्होंने बताया है कि इनको हर साल 70 करोड़ रुपये चाहिए जबकि 18 करोड़ से ज्यादा गुप्ता जी नहीं दे रहे हैं। इन 18 करोड़ रुपये में उपाध्यक्ष महोदय, आपके ओर हमारे जिले का नम्बर तो आता नहीं। इनको जितना पैस मिलता है, उससे इनके रोहतक जिले को ही सड़के पूरी हो पाती है। इसलिए मेरी गुप्ता जी से प्रार्थना है कि जितना पैसा डांगी साहब को काम करने के लिए चाहिए, वह पैसा गुप्ता जी इनको दे दें ताकि सारी सड़कों की रिपेयर हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सिचाई के बारे में कहना चाहता हूँ। हरियाणा सरकार को वर्ल्ड बैंक से 800 करोड़ रुपये मिल गए हैं। इनमें से मेरी मांग है कि 65 करोड़ रुपये तो दादूपुर नलवी नही के लिए ओर 100 करोड़ रुपये दादूपुर लाड़वा के लिए दे दिया जाए। यदि हमें 165 करोड़ रुपये मिल जाएं तो ये नहरें पूरी हो सकेगी। इनके पूरा होने पर हमारे इलाके की पानी की जरूरत भी पूरी हो सकेगी और वाटर लैवल जो बहुत नीचे जा

चुका है, वह भी ऊपर आ जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं डांगी साहब का धन्यवादी हूँ क्योंकि हर गांव में जा कर कोर्नर बना कर रहे हैं कि वहां पर सड़क का काम हो जाए। (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं हैल्थ डिपार्टमेंट के बारे में कहना चाहता हूँ। (विधन एवं घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष: लहरी साहब, अब आप वाइंड अप कीजिए।

साथी लहरी सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी थोड़ा समय और दीजिए। बहिन जी अभी बैठी नहीं है। जिस जिस हिसाब से बहन जी काम कर रही है.....(विधन) पिछली सरकार ने और इस सरकार ने जो भी डिस्पेंसरीज और प्राइमरी हैल्थ सेंटरज बनाए हैं, उनकी देख रेख में काफी कमी है। न वहां पर पूरी दवाईयां मिलती है और न पूरी बिल्डिंग ही है। मेरे हल्के में 2 प्राइमरी हैल्थ सेंटरज बनाए हैं, उनकी देख रेख में काफी कमी है। न वहां पर पूरी दवाईयां मिलती है और न पूरी बिल्डिंग ही है। मेरे हल्के में 2 प्राइमरी हैल्थ सेंटरज हैं और वे दोनों ही पंचायतों की बिल्डिंग में चल रहे हैं। सबसिडियरी हैल्थ सेंटरज भी बिना बिल्डिंग के ही चलाए जा रहे हैं। और वहां पर कोई कम्पाउंडर या डाक्टर नहीं मिलता। इसके साथ ही जहां पर एक्स-रे प्लांटस लगे हुए हैं, वहां टैक्नीशियन भी मिलने चाहिए। बहिन जी इस वक्त बैठी नहीं है, मेरा नम्र निवेदन है कि इस ढंग से काम करना चाहिए जिससे सभी को सुविधा मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं शिक्षा के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। जो 13 स्कूल अपग्रेड किया है और न ही मेरे हल्के का कोई स्कूल अपग्रेड किया है उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि 1981-82 के बाद से मेरे हल्के का कोई भी स्कूल अपग्रेड नहीं किया गया है और न ही कोई नई सड़क उस हल्के में बनाई गई है। मैं डांगी साहब से नम्र निवेदन करूंगा कि मेरे हल्के में सड़कों की हालत की तरफ जरूर ध्यान दें। सारे हल्कों में बराबर का काम होना चाहिए, बराबर के स्कूल अपग्रेड होने चाहिए। (घंटी) मेरा हल्का 15-20 साल से पिछड़ा पड़ा है, उसकी तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर एक पुल टूट गया था और दो आदमी भी मर गए थे। उस पुल के टूटने से 100 गांवों का रास्ता बन्द हो गया है। वह पुल धनौरा, डब्ल्यू0 जे0 सी0 पर बनना है और इरिगेशन डिपार्टमेंट न बनाना है। इस पुल के बनने से 100 गांवों के किसानों का फायदा होगा, लेकिन न बनने से बहुत नुकसान हो रहा है। (घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि इससे सबको बराबर सुविधा मिलनी चाहिए। मैंने पिछली बार भी क्वैशन रज किया था, जो भी ग्रान्ट्स है, वे रोहतक, सिरसा, हिसार आदि जिलों में दी जाती है। मेरा फाईनैस मिनिस्टर साहब से नम्र निवेदन है कि ग्रान्ट्स सभी जिलों में बराबर बांटी जानी चाहिए। हमारे इलाके में भी गरीब

लोग रहते हैं, इसलिए उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। (घण्टी) उपाध्यक्ष महोदय, एक क्वै चन के जवाब में मुख्य मंत्री जी ने एनाउंसमेंट कर दी थी कि जरिजन चौपाले है, वे 31 मार्च, 1995 तक कम्पलीट कर दी जाएंगी। यह कोई छोटा फैसला नहीं है, इस पर 100-150 करोड़ रुपये के लगभग खर्च करना पड़ेगा। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने हाउस के बाहर भी 4-5 बार एनाउंस किया है कि इन चौपालों का कार्य कम्पलीट हो जाएगा। 70-75 प्रति शत गांव ऐसे हैं जहां चौपालों की मुरम्मत होनी है। (घण्टी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी ही देर में अपनी बात को समाप्त करूंगा। अब मैं इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के बारे में कहना चाहता हूँ। चौटाला साहब, इस समय हाउस में बैठे नहीं हैं, उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स पलायन कर रहे हैं वे हरियाणा से जा रहे हैं। मैं चौटाला साहब को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अब ये इंडस्ट्रियलिस्ट्स हरियाणा से उद्योग उठाकर बाहर नहीं जा रहे हैं वे तो चौटाला साहब से डर कर चले गए थे। जब इंडस्ट्रियलिस्टर को यह पता चलता था कि चौटाला साहब आ रहे हैं तो जगाधारी और यमुनानगर के उद्योग बन्द हो जाया करते हैं और बहुत से उद्योग हरियाणा से बाहर भी चले गए। इसी तरह से फरीदाबाद में है। अब सरकार की पौलिसी है कि दूसरे देशों से इंडस्ट्रियलिस्ट यहां पर आकर इंडस्ट्रीज लगाएं और अब तक कम से कम 100 इंडस्ट्रियलिस्ट आ चुके हैं और इंडस्ट्री लगा चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष: लहरी सिंह जी, आप वाइन्ड अप कीजिए।

श्री सतबीर सिंह कादयान: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अभी माननीय सदस्य ने श्री ओम प्रकाश चौटाला का नाम लिया है। जब वे सदन में ही नहीं हैं तो उनका नाम नहीं लेना चाहिए। ये तो अभी अभी खरीदे गए हैं। (ओर एवं व्यवधान)

साथी लहरी सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, कादयान साहब, को अपनी वह बात याद आ रही है जिसमें ये पांच करोड़ के घपले में फंस गए हैं

श्री उपाध्यक्ष: लहरी सिंह जी, आप एक मिनट के लिए बैठ जाएं क्योंकि कादयान साहब कुछ कहना चाहते हैं

श्री सतबीर सिंह कादयान: उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो पांच करोड़ वाली बात कही, वह ठीक नहीं है। मैं जब तक इपकों का चेयरमेन रहा हूँ, उसको प्रोफिट ही हुआ है। अगर कोई इपको का एक रूपया भी बचा हुआ था तो वह मेरे टाइम में वापिस आ गया था। एक साल तो 101 करोड़ रूपए का प्रोफिट हुआ था।

श्री राम कुमार कटवाल: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। उपाध्यक्ष महोदय, छाज तो बोले, ये छलनी क्यों बोले है? अभी बंसी ला जी नहीं बैठे है। इन्हे अभी दो साल ही हुए हैं ओर इन्होंने दो साल में पेट्रोल पम्प खोल दिया है।

Mr. Deputy Speaker: This is not a point of order.

साथी लहरी सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, यह पेट्रोल पम्प एक हरिजन को, एक गरीब आदमी को दिया गया है ताकि वह काम करके खा सके। उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिन मुझे पेट्रोल पम्प मिला है, उसी दिन चौधरी बंसी लाल के बेटे को भी पेट्रोल पम्प मिला है। यह मुख्य मंत्री जी के हाथ में नहीं है कि जिसको चाहा पेट्रोल पम्प दे दो ओर न हि किसी ओर के हाथ में है। आज इनको तकलीफ होती है। (घण्टी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में खत्म करता हूँ।

Mr. Deputy Speaker: You are stressing too much.

साथी लहरी सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात ओर कहना चाहता हूँ कि जो बिजली के पावन हाउस इन्होंने अपग्रेड करके 66 के 0 वी 0 के किए है, वे वैसे के वैसे ही पड़े हुए है। जैसे गुडा और पृथला के पावर हाउसिज हे, इनको चालू किया जाए।

Mr. Deputy Speaker: Please windi up.

साथी लहरी सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं खत्म ही कर रहा हूँ। इसी तरह से जो हकसफा का कानून है, वह ठीक हो गया है, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ लेकिन उसमें एक प्रोब्लम रह गई है, उसको भी दूर कर दें। प्रोब्लम यह है कि जो हिस्सेदारी है उस बारे में पुनविचार किया जाए।

इसी तरह से मैं पंचायती राज के बारे में कहना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कारपोरेट्स के चैंबरमैन के बाद में कह दिया, साथ ही यह भी कहा कि चीफ मिनिस्टर का लड़का अपने आपको सी० एम० लिखता है। (विधन) मेरा इस बारे में निवेदन है कि भगवान ऐसी औलाद सबको दें।

श्री जिले सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, ये किस विषय पर बोल रहे हैं।

साथी लहरी सिंह: सर, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव्स पर बोल रहा हूँ। मेरा तो कहना यह है कि परमात्मा ऐसी औलाद सबको दे क्योंकि उसके हाथ में इतनी पावर होते हुए भी घर-घर जाकर लोगों के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि हम आपसे मिलने आये हैं ऐसा नहीं है इनकी तरह कि किसी की बहू का कत्ल करवा दे और किसी और का कत्ल करवा दे। वे ऐसा भी नहीं हैं कि अगर किसी का हाथ उठा गया तो उसका हाथ कटवा दे जैसा कि वे करवाया करते थे। उपाध्यक्ष महोदय, इन भावों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ। (विधन)

श्री सतबीर सिंह कादयान: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का टाईम दें। सर, मुझे तैयारी हो रही है कि मेरा बोलने का नम्बर आएगा या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: कादयान साहब, आप टै ान न रखिए। आपको बोलने का समय दिया जाएगा। पहले जानकी देवी मान को बोल लेने दे।

श्रीमती जानकी देवी मान (इंद्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी के सामने अपने हल्के की कुछ कठिनाईयों के बारे में कहना चाहती हूं लेकिन कहें किससे, मुख्य मंत्री जी तो उठकर चले गए। मैंने उनसे कई बार कहा है कि मेरे हल्के के काम करवाए लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: वित्त मंत्री जी यहां पर बैठे हैं।

श्रीमती जानकी देवी: उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के अन्दर न स्कूल है, न कालेज है। मेरे हल्के के अन्दर लड़कियों के पढ़ने के लिए 10+2 का कोई स्कूल नहीं है, साथ ही लड़कियों को स्कूल ले जाने के लिए कोई बस सविस का भी प्रबन्ध नहीं है। मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि वे मेरे हल्के के अन्दर 10+2 का स्कूल औ कालेज खुलवाएं ताकि लड़किया पढ़ कसे। ये तो खुद कहते हैं कि वे स्त्रियों के लिए बहुत कछ कर रहे हैं पर हो कुछ भी नहीं रहा है। इनकी सब बातें कहने की ही है। उपाध्यक्ष महोदय, जब तक दे और प्रदे ज्ञ के अन्दर लड़कियों की पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, तब तक इनका भविश्य ठीक नहीं हो सकता। अगर मां पढ़ी लिखी होगी, तभी वह घर का काम काज ठीक ढंग से कर सकेगी। इसलिए मुख्यमं त्री जी को मेरे हल्के के अन्दर

स्कूल और कालेज खुलवाने चाहिए। इसके अलावा स्कूल में टीचर्स भी नहीं हैं, कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें जै० बी० टी० टीचर या अन्य टीचर नहीं हैं, इसलिए आपको नेय बच्चों की भर्ती करके टीचर्स लगाने चाहिए। इसके अलावा, मेरे हल्के में स्कूलों की छतें भी टूटी पड़ी हैं सरकार को बरसात से पहले छतें ठीक करवानी चाहिए ताकि मासूम बच्चे करने से बच जाए। मेरे हल्के की सड़कें भी टूटी पड़ी हैं। ओर एक धनौरा जागरी का पुल टूटा पड़ा है जिसकी वजह से किसानों को अपनी फसलें ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए सरकार को जल्दी ही सड़कें और पुलों की मरम्मत करवानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इन्द्री हल्के के साथ साथ बहुत से गांव जमुना से लगते हैं। जब बरसात में पानी आता है तो जमुना के बहाव से गरीब किसानों की जमीन कट जाती है। इसलिए मेरा सरकार से कहना है कि बरसात आने से पहले ही वहां पर ठोकड़ें लगाएं ताकि गरीब किसानों की जमीन बच सके। इसी तरह हरह से बिजली की भी प्रदेश के अन्दर बहुत जरूरत है। इसके साथ ही साथ मैं नेहरा साहब से भी विद्वान करूंगी कि वे लहरों की गाद निकलवाए। पिछले तीन साल से नहरों पर काम नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या बात है? जब इनको सच बात कहते हैं तो ये कहते हैं कि यह बात क्यों कही है। इन्हीं भावों के साथ मैं अपना स्थान लेती हूँ। धन्यवाद।

श्री सतबीर सिंह कादयान (नौलथा): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत

धन्यवाद। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पे 1 किया है.....

.....

श्री उपाध्यक्ष: समय के मामले में जो मिसाल बहिन जी ने कायम की है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी सदस्य उसे कायम रखेंगे।

श्री सतबीर सिंह कादयान: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो डिमांड बढ़ा चढ़ाकर सदन में पे 1 की है, उसमें जो खर्च है, वे वास्तविकता से दूर है, ज्यादा खर्च तो एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर है और फिक्सड ऐक्सपेंडीचर है। विकास के लिए बजट में उतना प्रावधान नहीं किया जितना होना चाहिए। राष्ट्रीय मुद्रा स्फीति के हिसाब से ही बजट में दो तनी साल से वृद्धि हो रही है। ऐक्साइज से ओर सेल्ज टैक्स से जो आमदनी बताई है, वह दस परसेंट होगी। कुछ वृद्धि तो इसलिए कम रहे जाती है कि वित्त मंत्री जी हर महकमें को सही डायरेक्टिव नहीं दे पाते। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रकृति पर निर्भर करती है। फसल अगर ज्यादा हो जाती है तो सेल्ज टैक्स ज्यादा आ जाता है ओर जो टैक्स उगाहे जाते हैं, जिनसे प्रदेश का विकास हो सकता है, उस पर सरकार का पूरा ध्यान नहीं रहता। 1977 में चौधरी देवी जाल जी ने मैचिंग ग्रांट्स स्कीम चलाई थी जिसके तहत स्कूल, कालेज, हरिजन चौपाल और गांव की गलियों के लिए दुगुना पैसा किया करती थी ओर लड़कियों की शिक्षा के लिए तिगुना किया करती थी। मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि 27.03.91 को इन्होंने इसरान में एक

कालेज बनाने का फैसला लिया था। गांव के लोगों ने 5 लाख 40 हजार रूपए जका कर रखे थे लेकिन हमारी सरकार आठ दिन के बाद नहीं रही थी, उसक बाद गुप्ता जी की सरकार आ गई। विकास के नाम से लोगों के पैसे जो बैंकों में जका है, उन संस्थाओं को ने उसका ब्याज मिलता है न मैचिंग ग्रांट देकर दुगुना मिलता है। जब किसानों की जमीन एक्वायर करती है। न तो किसान को उनकी जमीन का पैसा देती है और न ही विकास का काम हो रहा है। ऐसी योजनाएं बनाई जाए कि छह महीने के अन्दर अन्दर एक्वायर जमीनकी पेमेंट किसान को की जाए। सरकार जिन किसानों की जमीन एक्वायर करती है, उनकी नौकरी दी जाए, क्योंकि उनके पास आजीविका के दूसरे साधन नहीं होते।

मै डिमांड नं0 16, 17, 9, 22, 2, 6 और 2 के ऊपर बोलना चाहूंगा। डिमांड नं0 16 इंडस्ट्री के बारे में है। सरकार बलंगबांग दावे करके हरियाणा की जनता को गुमराह करती है कि एक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देगे। कारखाने इतने ज्यादा लगाएंगे कि कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। इन दावों से जनता झांसे में आ गई। हमारी सरकार 50 रूपये और 100 रूपये महीना बेराजगार को बेरोजगारी भत्ता देती थे। इसके अलवा इनको मुक्त बस सात्रा की सुविधा भी देती थी। मै प्रदे 1 के मुख्य मंत्री को यह बताना चाहूंगा कि प्रदे 1 के अन्दर जो आजकल उद्योग लग रहे है, वे चाहे एन0 आर0 आई0 स्कीम के तहत लग रहे है, चाहे प्रदे 1 से बाहर के आदमी लगा रहे है या

हमारे प्रदेश के अन्दर रहने वाले लगा रहे हैं। वह बाहर के आदमी ही रखते हैं हमारे पानीपत में एक नैसले की फैक्ट्री लगी है। इसी तरह से एक पैपसी कोला वालों ने फैक्ट्री लगाई है वहां पर क्लास-थ्री और क्लास-फोर के सभी कर्मचारी बाहर के लिए हैं। प्रदूषण तो हरियाणा में हो, धुआ फैक्ट्रीज को हम खयये, लेकिन हमारे प्रदेश के आदमी भी इनमें नौकरी में ले लिए जाए, यह देखने योग्य बात है। इस तरह की इंडस्ट्रीज हमारे प्रदेश में कार्यान्वित हो रही हैं इसके अलावा, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में उद्योग का सुचारु रूप से चलाने के लिए इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट द्वारा एच० एफ० सी० द्वारा और दूसरे आदयरी द्वारा जो धन दिया जाना है, उसको एक्सीडर्ट करना चाहिए। इसके अलावा, जैसे कि आपके पता ही है किस तरह से खानों की बात हो रही है। हरियाणा का एक माईन्ज एण्ड मिनरल्ज का महकमा है। 1986 में जब चौधरी भजन लाल मुख्य मंत्री थे तब उन्होंने एक निर्णय लिया था कि जो इनके नजदीकी है या करीब है, उनको आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए सरकार की जो चट्टाने हैं या खाने हैं, जैसे स्लेट की खानें हैं या और कोई चीज निकलती है, वह उनको दे दीजिये। इनका यह फैसला था ताकि ये खाने इनके अपने चहेतों को दी जा सकें। उसके बाद चौधरी बंसी लाल 1986 में मुख्य मंत्री बने। उन्होंने इस काम के लिए एक कारपोरेशन बनाई जिसका नाम एच० एम० एल०। यह कारपोरेशन काम करती रही। बाद में जब हमारी पार्टी की सरकार बनी और चौधरी देवी लाल जी आये तो हमने यह किया

कि पहले इस एच0 एम0 एल0 से नो-आब्जैक्टिव इन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तब किसी दूसरे की लीज पर देगे। लेकिन जब 1991 में दोबारा चौधरी भजन लाल जी सता में आये तो इन्होंने अपने चहेतों को और अपने परिवार के लोगों को यह जमीन लीज पर देनी भुरु कद दी।

चौधरी जगदी । नेहरा: आन ए प्यायंट आफ आर्डर सर। डिप्टी स्पीकर सर, इस ढंग से ये जो वेग एलीगे एन्ज लगा रहे है, यह पालियामैंट्री परम्परा के मुताबिक बिल्कुल न लगाए, इनका इन डिमांडज से कोई संबंध नहीं है ययह जो खाने दी जा रही है, उनके लिए बाकायदा एक प्रोसीजर बना हुआ है। उस प्रोसीजर के तहत खाने दी जा रही है ऐसे नहीं कि ऐसे ही मन मर्जी से जिस को चाही दे दी जाए। इसके लिए केन्द्र सरकार की कनकरेंस भी लेनी पड़ती है। इसलिए इस ढंग से ऐसे ही एलीगे एन्ज लगाना कि यह अपनी परिवारों को दी जा रही है, यह ठीक नहीं है इनके राज में जो कार्यवाही इस बारे में इन्होंने की थी, वह भी लोगों को पता है। आप लोगों ने जो खाने दी थी, उनका क्या हाल था, क्या वह ये भूल गये? सारी जगहों पर, इन्होंने भी तो अपने ही रि तेदारों के अलावा, किसी ओर को खाने नहीं दी थी। किस तरीके से कानून की धज्जियों उडाई गयी, यह सब को पता है।

श्री सतबीर सिंह कादयान: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपको लीज के बारे में बता रहा था कि इन्होंने अपने चहेतो को

लीज पर दी है। रोजका-गुजर में, सिलिका-सैंड की लीज, हरियाणा मिनरल्स से सरेंडर करवाकर, विवजीत सिंह व उग्रसैन को दी गयी हैं उग्रसैन मुख्य मंत्री जी के साले का लड़का है। इसके साथ ही अनंगपुर-कटन व सराया ख्वाजा की सिलिका-सैंड की लीज, कैला आहूजा को दे दी गयी हैं

चौधरी जगदी आ नेहरा: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। डिप्टी स्पीकर साहब, ये मिस्टर आहूजा का नाम ले रहे है, क्या यह भी रि तेदार है? (व्यवधान व भाोर) इस ढंग से ऐलीगे ान लगाना और नाम लेना क्या ठीक है?

श्री सतबीर सिंह कादयान: मै यह कह रहा था कि इसी तरह से अनंगपुर कटन व सराय ख्वाजा की सिलिका-सैंड की लीज कैला आहूजा को दी गयी हैं एक पाली, जिला फरीदाबाद की सिलिका सैंड की दो खानें, भी ापाल सिंह सुपुत्र श्री कर्मवरी सिंह वगैरह को दी गयी है। एक गंगानी, जिला गुडगांव की सिलिका-सैंड की लीज एस0 ए0 मिनरल्स, करोलबाग, नई दिल्ली को दी गयी। इसमें कैला आहूजा के अलावा दूसरे व्यक्तियों को सांझेदारी भी हैं एक रविन्द्र कुमार पुत्र श्री अमीर चन्द्र मक्कड, एम0 एल0 ए0 हांस को, खरक-सोहना (गुडगांव) की सिलिका सैंड की लीज दी गयी है।

चौधरी जगदी आ नेहरा: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। इस ढंग से ऐलीगे ान लगनाया जिस तरह से यह कह रहे

है, उचित नहीं हैं एम0 एल0 ए0 का नाम लेकर यह एलीगे इन न लगाए तो ठीक रहेगा। जैसे कर्ण सिंह दलला जी ने धनिक लाल मंडल जी का नाम लेकर एलीगे इन लगया, वह भी ठीक नहीं था। क्या यह सब इनके रि तेदार है या इनके कहने से रि तेदार बन जाते हैं?

श्री उपाध्यक्ष: कादियान साहब, आप बैठ जाइए। आप एक मिनट मेरी बात सुन ले। आप किसी ऐसे आदमी का नाम न ले जो अपने आपको हाउस में डिफेन्ड र कर सकता हो। (गोर एवं व्यवधान) चीफ मिनिस्टर साहब, कुछ कहना चाहते हैं, आप बैठिए।

चौधरी भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, इनका मकसद तो कभी ठीक बात कहने का नहीं है। कोई एम0 एल0 ए0 हो, कोई एम0 पी0 हो और उसका कोई रि तेदार हो काम कर सकता है काम करना कोई गुनाह तो नहीं है? चोरी करना, डकैती करना और हेराफेरी करना तो बुरी बात है लेकिन अगर कोई आदमी कानून के हिसाब से सही काम करता है, मर्यादा में रहकर काम करता है तो इसमें क्या हर्ज है? पहले इन माइन्ज से नौ करोड़ की इन्कम थी ओर आज के दिन सोलह करोड़ की इन्कम हैं बाकायदा ऐप्लीके इनज मांगी जाती है, इंटरव्यू होता है, तब माइन्ज दी जाती है। अगर मक्कड़ के लड़के ने ले ली है तो उसमें गुनाह की क्या बात है? कोई गलत तरीके से ले ली हो ताह यह कह सकते हैं उपाध्यक्ष महोदय, मैं

कहना चाहता हूं कि इनके खिलाफ सी० बाई० आई० ने करण्डान का केस दर्ज किया हुआ है और इंकवायरी भी हुई है अगर मैं आपका चिट्ठा खोलने लगूं तो आपको सारी बातों का पता लग जाएगा।

श्री सतबीर सिंह कादयान: उपाध्यक्ष महोदय, इफको का एक पैसा भी बकाया नहीं है, सारा पैसा वापिस आ गया है। मैं सउन को बताना चाहता हू कि जब आप सेन्टर में कृषि मंत्री थे तो उस वक्त के मेरे पास ऐसे सबूत हैं। एक-एक ट्रक में आठ-आठ, नौ-नौ किलो वजन था और पूरे ट्रक के वजन का क्लेम किया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, मवन्डी (बम्बई) से आंवाला इफको प्लांट बरेली में था और इकोनोमिक ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शन कम्पनी, ट्रांसपोर्टेशन की ठेकेदार थी। इस केस में सी० बी० आई० की इंकवायरी भी चल रही थी। उन ट्रकों में आठ-आठ और नौ-नौ किलो वजन होता था लेकिन पूरे ट्रक का किराया लिया गया था।

चौधरी भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई आदमी कोई प्लांट लगता है और वह प्राइवेट आदमी है तो यह पर इस बात को कहने का क्या ताल्लुक है? उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बाद चौधरी देवी लाल आए, बंसी लाल आए, अगर इनको कोई कमी नजर आई थी तो ये एक ट्रक ले सकते थे और मेरे खिलाफ चौधरी देवी लाल को केस दायर करना चाहिए था। हम कोई फिजूल की बात नहीं कतरे, मर्यादा में रहकर काम करते हैं।
(और एवं व्यधान)

श्री धीरपाल सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथी श्री सतबरी सिंह कादियान ने कहा कि हाउस के नेता जब दिल्ली की सरकार में कृषि मंत्री थे तो उस समय ऐसे ट्रक आए जिनमें नौ किलो वजन डाला गया और पूरे ट्रक का किराया लिया गया। आप उस समय कृषि मंत्री थे और उाकप नाम इसमें आ सकता है उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल ने कहा है कि जब श्री कादियान इफको के चेयरमैन थे, तो उस वक्त काफी गलत काम हुए लेकिन श्री कादियान ने कहा है कि मेर खिलाफ कही कोई लेनदेन का मामला नहीं है। मुख्य मंत्री के ऊपर एक दोशारोपण लगाया जा रहा है। तो आप आपने आपको उस बात से अलग कर सकते है और कह सकते है कि कोई माल नहीं आया और अगर आया है तो आप बात को साफ करें।

श्री धीरपाल सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, बकायदा सी० बी० आई० की इन्क्वायरी हुई थी और इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी जगदी ा नेहरा: स्पीकर साहब, ये तो फिजूल की बात करते है? इनकी बात में कोई सदाकत नहीं है

श्री सतबरी सिंह कादियान: अगर आप चाहे तो मैं आपको ट्रक नम्बर दे सकता हूं जिनमें आठ-नौ किलो वजन आया और पूरे ट्रक का किरयाणा चार्ज किय गया।

चौधरी जगदी ा नेहरा: आप नम्बर दे दीजिए। हमर भागने वाले नही है। ट्रक का नम्बर देने से क्या होता है? हम भी ट्रक के नम्बर दे सकते है। उपाध्यक्ष महोदय, मै प्रार्थना करता हूं कि मैम्बर साहब डिमांड पर बोले, हम बिल्कुल भी दखलअन्दाजी नही करेगे। आप इस तरह से बात करे जिससे हाउस की गरिमा को कोई आंच न आए।

श्री सतबरी सिंह कादयान: उपाध्यक्ष महोदय, मै इंडस्ट्रीज को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। जब तक प्रदे ा के जो साधन है उनको सही ढंग से यूटीलाईज न किया तब तक हमारे प्रदे ा के अन्दर इंडस्ट्रीज नही पनप सकती। मै आपको इस सरकार के कारनामों के बारे में बताना चाहता हूं कि किस तरह से यह सरकार अपना कार्य कर रही है जो बड़ा ही आपत्तिजनक है? इन्होंने अब्दुल रजाक पुत्र गुलाम रसूल गांव पडाणी जिला गुडगांव को सौन्ध की चाईन-क्ले की लीज चौधरी तैयब हुसैन के दामाद को फायदा पहुंचाने के लिए दे दी। (गोर) इसी तरह से सुरेन्द्र पुत्र राम रत्न एम0 एल0 ए0 को सेलेट की लीज कौड़ियों के भाव दे दी। 700 एकड़ भूमि उसको केवल 10 रूपये के प्रति एकड़ के हिसाब से दे दी गई। (गोर एवं व्यवधान) किस तरह से इस सरकार ने लोगों के साथ भेदभाव किया है। (गोर) अच्छा, उपाध्यक्ष महोदय, अब मै ज्यादा इंडस्ट्रीज पर न कहता हुआ, ऐजूके ान पर बोलूंगा क्योंकि अगर मै ओर कुछ बातें इंडस्ट्रीज के बारे में कह दूंगा तो इस सरकार को तकलीफ होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक ऐजूके ान का संबंध है, इसके लिए वित्त मंत्री ने अपने बजट में बहुत कम पैसा रखा है। जब हमारी सरकार थी, उस वक्त सिर्फ एक साल के अन्दर ही 350 स्कूलों को अपग्रेड किया गया था और इस मौजूदा सरकार ने चार सालों में केवल 313 स्कूलों को ही अपग्रेड किया है। (गोर)

श्री अमीर चन्द मक्कड़: उपाध्यक्ष महोदय, इनके जमाने में तो केवल घोशणाएं ही घोशणाएं थी, स्कूल एक भी अपग्रेड नहीं किया गया था। (गोर)

श्री उपाध्यक्ष: कादयान साहब, अब आप समाप्त करे। (गोर)

श्री सतबरी सिंह कादयान: उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही समाप्त करता हूं। अभी मक्कड़ साहब ने बोलते हुए कहा कि केवल घोशणाएं ही घोशणाएं हमारे वक्त में थी, काम कोई नहीं किया। हमारे वक्त में ऐसी बात नहीं थी। जहां पर कोई नार्मज को पूरा करता था तो उस जगह पर स्कूल खोल दिया जाता था। आपकी सरकार की तरह हामर ीसकरार किसी इलाके के साथ भेदभाव की नीति नहीं बरतती थी। आज स्कूलों की क्या हालत है कही बिल्डिंग नहीं, कही बिल्डिंग है तो टीचर्ज नहीं, कोई भी काम आपकी सरकार का नार्मज के अनुसार नहीं हो रहा है। (गोर) आज की यह मौजूदा सरकार नार्मज के लिहाज से स्कूलों की अप ग्रेडे ान नहीं कर रही है, यह कोई अच्छी प्रथा नहीं है। मैं मुख्य

मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे इस ओर ध्यान दे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ और इस सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि राई स्पोर्ट्स स्कूल में नक्ल करवाई गयी। वहां का स्टाफ नकल करवाता रहा और बाद में लड़कों को कह दिया कि अभी नहीं लिए जाएंगे। बाद में दोबारा टैस्ट होगा। (गोर) और जो वहां के प्रिन्सिपल है, वे कहते हैं कि पहले मुझे मुख्य मंत्री महोदय ने नौकरी दे दी और बाद में अर्जी ली। ऐसी ऐसी बातें इस राज में हो रही हैं। (गोर)

चौधरी भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि वैद्य डाक्टर, पढ़ाने वाला जो होता है, वह काबिल आदमियों में से लगाया जाता है लेकिन आपकी तरह * * *

श्री सतबीर कादयान: उपाध्यक्ष महोदय यह भाब्द कार्यवाही में से निकाल दिए जाने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, ये भाब्द कार्यवाही में से निकाल दिए जाए।

श्री सतबीर सिंह कादयान: राई स्पोर्ट्स स्कूल के अन्दर पिछले दिनों कुछ लड़कों ने गुंडागर्दी की। चार लड़कों को स्कूल से निकाला गया, फिर उन्हें दोबारा स्कूल में लिया गया। उन्होंने वहां के वाइस प्रिन्सिपल की पिटाई की थी लेकिन किसी के खिलाफ कोई एफ0 आई0 आर0 या पर्चा दर्ज नहीं हुआ। जब ऐसा

हो तो पढ़ने वाले बच्चों के दिल में क्या भावना पैदा होगी? यह बड़े सोचने की विषय है। इसी तरीके से हमारे प्रदेश के अन्दर लैंड ग्रैबि के तहत एक संस्था बनी है, जिसका नाम 'भजन शिक्षा संस्थान' है। उसने बारह सौ एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है। 415 एकड़ जमीन के तो पंचायतों से प्रस्ताव ले लिए। उसमें बहुत बड़े-बड़े लोग शामिल हैं।

चौधरी भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्यायंट आफ आर्डर हैं मैंने एक पेपर में पढ़ा था कि फरीदाबाद में एक संस्था बनी है। उसे पढ़कर कर मुझे बहुत तकलीफ हुई कि यह पेपर में कैसे आ गई। मैंने उसी वक्त पता किया। उस बारे में किसी पंचायत ने प्रस्ताव नहीं किया ओर यह सब बेसलैस बात है। ये लोग जैसे खुद थे, इनकों वैसा सब को नहीं समझना चाहिए। हमारे पर थोड़ी सी कृपा करों हर एक को अपने जैसा इन्सान नहीं समझाना चाहिए।

श्री सतबरी सिंह कादयान: उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने स्पष्टीकरण देने की कोशिश की परन्तु मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि 'भजन शिक्षा संस्थान' बाकायदा रजिस्टर्ड है। उस शिक्षा संस्थान को उपहार देने के लिए 415 एकड़ जमीन के लिए प्रस्ताव पंचायतों से करवाए गए। जैसे नंगल गुजरान पंचायत से 170 एकड़, कुरै गीपुर से 40 एकड़, गढ़ी गुजरान से 70 एकड़ पाखच से 50 एकड़ मादलपुर से 40 एकड़

नेकपुर से 30 एकड़ और सरूरपुरा पंचायत से 15 एकड़ जमीन का प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष: अगर आपको वास यह प्रस्ताव है, तो आप इनको टेबल आफ दि हाउस पर रख दें।

चौधरी भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूँ कि एक भी पंचायत का प्रस्ताव नहीं है। जब प्रस्ताव ही नहीं है तो ये टेबल पर क्या रखेंगे।

श्री सतबीर सिंह कादयान: चलो, हम इसकी और क्लैरिफिके इन ले लेंगे। वैसे हम कोई झूठ बात यहां पर नहीं कहना चाहते हैं, यह बात सच्ची है इसक बाद मैं कोआप्रे इन विभाग के बारे में दो-चार सुझाव देना चाहता हूँ। (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, यह महकमा ऐसा है जो ज्यादा से ज्यादा आदमियों को रोजगार देने में मदद कर सकता है। परन्तु जिस तरीके से हमारे संस्थान चल रहे हैं, वे प्रदेश के लिए हितकर नहीं हैं सिक्की भी ऐसी संस्था की एनुअल जनरल मीटिंग हर साल होनी चाहिए लेकिन यहां पर कोई मीटिंग नहीं होती। अगर इनकी एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाए तो उसमें चुने प्रतिनिध यानी डायरेक्टर्स आएंगे और जिन लोगों ने उस संस्था में अपनी पूंजी लगाई हुई है, उनको अपने सुझाव उस मीटिंग में देने का मौका मिलेगा। लेकिन उनको वह मौका नहीं दिया जाता। मैं कनफ़ेड के बारे में क्या कहूँ। वहां पर एक ऐसा एम0 डी0 लगा दिया जो एक जेब में

तों टमीनि इन के आर्डर रखता है ओर दूसरी जेब में नौकरी देने के आर्डर रखता है। वारे * * * * * तेरे ठाट क्लर्क दो चड़ासी आठ। (पीर)

श्री उपाध्यक्ष: यह नाम रिकार्ड न किया जाये।

श्री सतबीर सिंह कादयान: उपाध्यक्ष महोदय, वह ऐसा एम० डी० है जिसको सभी जानते है, कोई डिनाई नही कर सकता। उस एम० डी० के 70-70 हजार रूपए के हर महीने के बिल आते है। (पीर)

श्री धीरपाल सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, यदि उसका नाम नही आएगा तो इस तरह से कह देते है कि वाह रे एम० डी० तेरे ठाट क्लर्क दो चपड़ी आठ।

श्री उपाध्यक्ष: कादियान साहब, आप आप बैठ जाएं। श्री पीर चन्द जी बोलेगे।

श्री सतबीर सिंह कादयान: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आप केवल पांच मिनट और बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप बैठ जाए।

श्री पीर चन्द (रतिया): उपाध्यक्ष महोदय, मै डिमांड नं० 8, 9, 10, 11, 21 और 23 पर अपने विचार प्रकट करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय मेरे रतिया हल्के में पिछले 12 साल से कोई भी विकास का काम नही हुआ। जो पिछली सरकार आई थी, उसने

बहुत हिम्मत के साथ रतिया में एक बस-स्टैंड का पत्थर रखा था। आज उस पत्थर का पता नहीं कहां पर है। उसी सकार के आदमी उस पत्थर को वहां से उठा कर ले गए। आज चार साल हो गए, उस समय माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाल मुख्य मंत्री हाते थे। उनहोने बस स्टैंड के लिए पत्थर रखा था और उन्ही के आदमियों ने उस पत्थर का उठा कर पता नहीं कहा पर फैंक दिया, उसका आज तक पता नहीं लगा।

प्रो० सम्पत सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्यावंट आफ आर्डर है। वहां पर बस स्टैंड बनाने के लिए पत्थर जरूर लगाया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन बाद में यह सरकार आ गई और यह सरकार उस पत्थर और पीर चन्द दोनों को ले गई। (हंसी)

श्री पीर चन्द: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सम्पत सिंह जी खुद मिमाज आदमी और वे अपनी गलती को मानते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं हैं इन्होने अपने चार साल के समय में हरियाणा के अन्दर विकास नाम की एक भी ईंट नहीं लगाई, इसमें भी कोई दो राय नहीं हैं उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में इस वक्त न कोई अस्पताल है और न कोई बस स्टैंड है। इसके अलवा मेरे हल्के में स्कूलों की भी बहुत कमी है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने 21 जनवरी को वहां पर एक जलसा रखा था। उस समय हमने इनके सामने हल्के की डिमांड रखी थी और कहा था कि पिछले 12 साल से हमारे यहां कोई विकास नहीं हुआ है। हमारे

माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस समय बड़े सम्मान के साथ वहां पर 30 बैड का अस्पताल मंजूर किया और बस स्टैंड के बारे में यह फरमाया कि जिस सरकार ने उसको बनाने का पत्थर रखा था, उस पत्थर को हम बदलना नहीं चाहते। इन्होंने कहा कि किसी भी सरकार ने पत्थर रखा हो, हम वह बनाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, मेरे हल्के में मुख्य मंत्री महोदय ने रतिया हल्के में एक 33 के 0 वी 0 पावर स्टे अन मंजूर किया है इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूँ। जब ये 1979 के अन्दर मुख्य मंत्री थे, उस समय रतिया को सिर्फ एक थाना और एक ब्लाक के नाते से जाना जाता था। लेकिन जब ये आदरणीय भजन लाल जी, मुख्य मंत्री बने तो 1979-80 में वह पूरा भाहर बन गया। इन्होंने ही उसको तहसील बनया नीं बसें लगाई। इतना ही नहीं बहुत बढ़िया अनाज मंडी भी बनाई। उस समय मैं हेफैड का चेयरमैन होता था। वहां पर 30 करोड़ रूपये की लागत से एक कम्पलैक्स बनया गया है अब फतेहाबार से रतिया की तरफ जाते है तो दूर से ही पता लग जाता है। कि यह रतिया भाहर है। चौधरी भजन लाल जी ने उस समय जितने काम किए, उनके लिए मैं इनको दाद देता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने मुख्य मंत्री काल में सन 1980 में मेरे हल्के रीतिया में एक मिसाल कायम कीथी कि एक प्राईमरी स्कूल को सीधा हाई स्कू अपग्रेड कियाथा। उस समय ये स्कूल के लिए 2 लाख रूपय देकर आए थे। अब जब दोबारा गए थे उसको ये 10+2 का कर आए है। इसी प्राकर से जाखल गांव का स्कूल अब इनकी घोशणा के मुताबिक 10+2 का

हो जाएगा। इस स्कूल के 25 कमरों बहुत बढ़िया बन कर तैयार हैं मेरे हिसाब से तो वह 10 जमा दो का स्कूल आज से चार पांच साल पहले बन जाना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे हल्के में एक रंगोई नाला है। इस नाले की खुदाई चौधरी सम्पत सिंह जी के राज में नहीं हो पाई जिस के कारण बाढ़ से नुकसान होता रहता है। मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहता हू कि इन्होंने अपने समय में इस नाले की खुदाई के लिए 1 करोड़ 20 लाख रूपए खर्च किए लेकिन एक तीन किलोमीटर का टुकड़ा छोड़ दिया। इस टुकड़े के पूरा न होने से जाखल स रतिया और फतेहाबाद से टोहाना के काफी गांव बाढ़ में डूब गए थे। अब गांवों के लोगों ने आपस में मिलकर इस तीन किलोमीटर के टुकड़े के पूरा किया है। अब इस नाले पर सब ने मिलकर एक 3 किलोमीटर लम्बा, 10 फुट चौड़ा और 6 फुट ऊंचा बांध बांध दिया है इस काम को गांवों वालों ने अपने ट्रैक्टर ट्रालियां से पूरा किया। इस काम में वहां के डी० सी० साहब, एस० डी० एम० साहब, तहसीलदार साहब, बी० डी० ओ० साहब ने भी अपना अपना योगदान दिया है। यह बांध 10 फुट और चौड़ा कर दिया जाए तो यह बहुत ही अच्छी बात होगी। (विधन) इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह दिवेदन करतना चाहता हू कि टोहाना रोड और रतनगढ़ तक पुल को अगर बना दिया जाए तो पंजाब को जाने के लिए रास्ता सीधा हो जाएगा और लोगों को सुविधा हो जाएगी। इसके साथ ही मैं यह भी

कहना चाहता हूँ कि वहां के जमींदार बहुत ही मेहनती हैं। और उस जमीन का पानी भी मीठा है लेकिन बिजली की भार्टेंज हैं वहां पर 33 के 0 वी 0 का पावर हाउस बन रहा है। और उम्मीद है कि इसके पूरा हो जाने से बिजली की कमी नहीं रहेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के रतिया में मास्टरों की बहुत कमी है, खासकर पंजाबी टीचरज की ज्यादा कमी है। यह इलाका पंजाब के साथ लगता है इसलिए पंजाबी पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा है। इसलिए मैं एजुकेशन मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि वहां पर ज्यादा पंजाबी मास्टरज भेजने की कोशिश करें। (विधन) उपाध्यक्ष महोदय, मैं और भी कुछ बातें कहना चाहता था लेकिन बोलने वाले और भी बहुत से साथी होंगे, उन्होंने भी अपने विचार रखने हैं। मुख्य मंत्री जी से मेरा नम्र निवेदन है कि जैसे पहले उन्होंने अपने भासनकाल में रतिया का चमकाया था, सारे काम पूरे किये थे, इसी तरह अब भी वे इस हल्के का पूरा ख्याल रखेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इन भावों के साथ मैं अपनी बात को यही समाप्त करते हुए समय देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ तथा अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री राम भजन अग्रवाल (भिवानी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं० 3 5 7 11 और 16 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जहां तक डिमांड नं० 3 का संबंध है, यह होम डिपार्टमेंट से संबंधित है। आज सारी स्टेट के अन्दर कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है कानून का पालन पुलिस करवाती है परन्तु

इस प्रांत के अन्दर पुलिस का ऐसा हाल है कि लोगों की नाजायत पुलिस हिरासत में रखा जाता है, ताड़ना दी जाती है, डर और आतंक का बोलबाला है, यहां पर पुलिस लोगों को मारती-पीटती है और उत्तेजित हो कर लोग पुलिस वालों को पीट डालते हैं। जहां पुलिस और जनता में तालमेल न हो कहीं पुलिस जनता को मारती पीटती है तो कहीं जनता पुलिसको मारती पीटती है, वहां पर कानून और व्यवस्था की क्या हालत होगी? उपाध्यक्ष महोदय, डिमांड नम्बर 5 एक्सार्ज एण्ड टैक्स इन डिपार्टमेंट की है। इस विषय में मैंने पहले भी कहा है कि प्रदेश से व्यापार दिन प्रतिदिन खत्म होता जा रहा है। मार्केट फीस 3 प्रति 100 है लेकिन नजदीक की दूसरी स्टेट्स दिल्ली और राजस्थान में मार्केट फीस कम है इसलिए इस स्टेट का व्यापार दूसरी स्टेट्स में जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सेल्ज टैक्स के सरलीकरण का सवाल है, वह नहीं हुआ है। जो सेल्ज टैक्स सिस्टम है, वह तर्कसंगत नहीं है और टैक्स बहुत ज्यादा है। अगर सेल्ज टैक्स का रेट कम कर दिया जाए तो टैक्स की रिकवरी ज्यादा होगी और स्टेट रैवेन्यू में बढ़ोतरी हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक बात सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूँ। हमारे बाहरों के अन्दर बाजार होते हैं। और इन बाजारों में छोटे दुकानदार होते हैं, वे अपने तख्त लगाते हैं और म्यूनििसिपल कमेटी उनसे टैक्स लेती है। अभी मुझे पता चला है कि 1991-92 में उनसे दस पैसे परस्केयर फुट टैक्स लिया जाता था और 1993-94 में बढ़ाकर 40 पैसे कर स्केयर फुट चार्ज किया

जाने लगा हैं अब इस महीने मार्च के अन्दर म्यूनिसिपल कमेटी ने जो अनाउन्स किया है, वह पिछले साल के टैक्स से 50 गुणा ज्यादा है ओर 1992-93 से दो सौ गुणा ज्यादा टैक्स लेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इसका सुधार किया जाना चाहिए और सरकार की तरफ से म्यूनिसिपल कमेटी को आदे 1 दिए जाने चाहिए कि यह टैक्स 25 प्रति 100 तक बढ़ाया जा सकता है, न कि 50 गुणा बढ़ाया जाए। क्या सरकार इसके लिए म्यूनिसिपल कमेटी को हिदायत जारी करेगी? भिवानी में यह भी कहा गया है कि 25 मार्च तक इस टैक्स की रिकवरी होनी है ओर यह आदे 1 रिकवरी कमेटी के हैं यह भी कहा गया है कि जो व्यापरी इस अवधि तक यह टैक्स नहीं देगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी। यह ठीक नहीं है और न ही यह गरीब आदमी के लिए सहने योग्य हैं

अब मैं डिमांड नं० 9 एजुकेशन के बारे में कहना चाहता हूं। आज स्कूलों को अपग्रेड किया जाता है, उसके क्या नामर्ज है। पिछले साल भी यह बात आई थी कि हिसार में सबसे ज्यादा स्कूल अपग्रेड किए गए थे। ठीक है लेकिन इसके लिए कुछ नियम तो होने चाहिए। जो भी उन नियमों को पूरा करता है, उनको अपग्रेड किया जाए। विशेष तौर पर से जो लड़कियों के स्कूल है, उनको अपग्रेड किया जाना चाहिए ताकि लड़कियों को पढ़ने के लिए दूर न जाना पडत्रे। इस बारे में तो मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था कि वे इसको ध्यान में रखेंगे।

दूसरे उपाध्यक्ष महोदय, कई स्कूलों में अध्यापक न होने की वजह से बच्चों को ठीक से पढ़ाई नहीं होती है। इसलिए यह नकल जो होती है। इसका कारण भी अध्यापकों की व्यवस्था भी करनी चाहिए मेरे हल्के में तीन कालज है। अध्यापक की बात तो छोड़ो वहां पर प्रिंसीपल ही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर प्रिंसीपल भी न हों, वहां पर शिक्षा का विस्तार कैसे हो सकता है। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, डिमांड नं० 11 हुड्डा के बारे में है हाउसिंग कालोनिया हुड्डा डिवैल्प करती है लेकिन वहां पर न तो कालोनिया बनाई गई है ओर न ही सड़के बनाई गई है। ये लोगों से बराबर किस्तें लेते रहते हैं लेकिन अगर कोई व्यक्ति किस्त देने में लेट हो जाए तो उससे भारी इन्ट्रैस्ट चार्ज किया जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो कालोनिया अभी तक नहीं बनाई गई है, उन लोगों से जो किस्तें ली जाती है। वह ठीक हिसाब से नहीं ली जाती है। अगर वहां पर सड़के बनाई जाती है तब तो किस्तें ले, अगर नहीं बनाई जाती है तो किस्तें न लें। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर सड़क नाम की कोई चीज नहीं है सड़कों को पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट देखता है। सड़के बनानी तो दूर रही, उनकी रिपेयर का काम भी नहीं हो रहा है उपाध्यक्ष महोदय, उनकी मुरम्मत होनी चाहिए, साथ ही जो सीवरेज है वह भी ठीक होने चाहिए।

अब सवाल इन्टस्ट्री का है। आज उद्योग लगाने के लिए बिजली की बहुत आवश्यकता है बिजली को टाप प्रायरटी देनी

चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, बिजली पर जमींदारों को सबसीडी दी जाती है लेकिन बिजली मिल ही नहीं रही, इसलिए सबसिडी का क्या फायदा? इसलिए सरकार जमींदारों को बिजली दें। इसके अतिरिक्त लोगों को अपने जेनरेटर सैट लगाने दे ताकि वे अपने उद्योग को ठीक से चला सकें। (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो अभी कुछ भी नहीं कहा है उपाध्यक्ष महोदय, उद्योगों को स्टेट की बहुत जरूरत है लेकिन उद्योगों को बढ़ाया देने के लिए एक तरफ तो बिजली नहीं है और दूसरी तरफ उद्योग विभाग के अधिकारी भी ठीक तरह से एजेकेटिड नहीं है, इसलिए इंडस्ट्री के अधिकारियों को एजेकेटिड किया जाए ताकि जो लोग उद्योग लगाना चाहे, वे अधिकारी उन लोगों को ठीक ढंग से शिक्षा दे सकें ठीक तरह से उनको गाईड लाईन दे सकें। ऐसा करने से उद्योगपतियों को हौसला बढ़ेगा। न केवल बाहर के आदमियों को यहां बुलाकर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए और सरकार की तरफ से सुविधाएं देनी चाहिए ताकि उद्योग को बढ़ावा मिल सकें। आज प्रांत के अन्दर अर्थव्यवस्था खराब हुई पड़ी है, अगर ठीक तरह से इन सब बातों को पालना हो तो अब यही स्टेट का वातावरण ठीक हो सकता है उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं भावों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।

श्री अमर सिंह (गुहला): डिप्टी स्पीकर साहब, आपका बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, बाकी डिमांड पर तो सभी साथी बोले हैं लेकिन डिमांड नं० 13 पर कोई

साथी नहीं बोला। मैं इसी डिमांड पर कहना चाहूंगा कि जो समाज कल्याण विभाग संबंधित है। सर, समाज कल्याण के लिए जो राशि रखी जाती है, उसका बहुत ही मिसयूज हो रहा है। सरकार इस राशि को हरिजनों का नाम दे दिया जाता है कि हम इतना पैसा हरिजनों पर खर्च करने जा रहे हैं लेकिन वास्तव में वह पैसा उन पर खर्च नहीं होता। सरकार कहती है कि वह हरिजनों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं लेकिन हरिजनों की भलाई का कोई काम नहीं होता, हरिजनों को कोई सुविधा नहीं दी जाती, हरिजनों के साथ भेदभाव बरता जाता है उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहता हूँ। सी० एम० साहब ने विधान सभा में चर्चा करते हुए एक बात कही थी कि सरकार 30 एच० सी० एस० नौमिनेट करने जा रही है लेकिन सरकार ने इन तीस एच० सी० एस० की भर्ती में हरिजनों के लिए कोई कोटा नहीं रखा यह बड़े खेद की बात है उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1981 में जुडी ज़यल मैजिस्ट्रेट की पोस्टस एच० पी० एस० सी० के परिव्यू से निकालकर डायरेक्टर जुडी ज़यल मैजिस्ट्रेट लिए गए थे, उस समय भी भजन लाल जी ही मुख्य मंत्री थे। मुझे पता नहीं कि क्यों मुख्य मंत्री जी हरिजनों से नाराज है, क्यों इन्होंने एच सी एस में हरिजनों को कोटा काट दिया? उनमें एक भी हरिजन नहीं लिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल जी के राज्य में अच्छी अच्छी पोस्टों पर हरिजन लगाए जाते चाहे वह डी० जी० पी० को पोस्ट थी। लेकिन इस सरकार में कोई भी हरिजन किसी अच्छी पोस्ट पर नहीं लगाया

जाता। सरकार उनके साथ बड़ा भेदभाव कर रही है। प्रमोशन की जो पॉलिसी है, सरकार उसको भी पूरी तरह से लागू नहीं कर रही, मुझे विधान सभा का एस0 सी0 एवं एस0 टी0 कमेटी का मੈम्बर बनाया गया है। मेम्बर होने के नाते से मैंने देखा है कि सरकार ने किसी भी महकमें में हरिजनों को पूरी रिजर्वेशन नहीं दी। जब कोई टैस्ट होता है तो हरिजनों को छोड़ दिया जाता है। मैंने पिछले सेशन में सवाल भी दिया था कि बी0-1 की पोस्टों में हमारे हरिजन लड़कों को जान-बूझकर क्यों छोड़ दिया गया है, कारण यही है कि सरकार नहीं चाहती कि हरिजनों के लड़के आगे आए उनको कुछ फायदा हो। मैंने यह भी पूछा था कि हमारे हरियाणा के अन्दर जे0 बी0 टी0 अध्यापक कितने हैं और उनमें हरिजन कितने हैं जे0 बी0 टी0 की ट्रेनिंग स्कूल खोलकर दे ताकि जे0 बी0 टी0 की भर्ती में हरिजनों का पिछला बैकलाग पूरा किया जाए। जो हरिजन सरकार को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उनके लिए भी सरकार चिंतित हो, उनके विकास के लिए भी सरकार कुछ न कुछ करे। जो हैड आफ दी डिपार्टमेंट्स रिजर्वेशन के कोटे को पूरी तरह से लागू नहीं करते, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो। ऐसा बिल सरकार विधान सभा में लाए, हम उसका समर्थन करेंगे। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक हरिजनों को न्याय नहीं मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी विधान सभा की एस0 सी0, एस0 टी0 कमेटी के सामने ऐसे मामले भी आए कि अम्बाला में म्यूनिसिपैलिटी में स्पीपर के पांच पदों पर

सामान्य जाति के उम्मीदवारों को लगा दिया गया इससे बढ़कर सरकार हरिजनों के साथ और क्या भेदभाव करेगी?

श्री उपाध्यक्ष: अमर सिंह जी, अम्बाला की जो बात आपने कही है, उससे मेरा भी ताल्लुक है। आप पटिकुलरर्जज बात दें।

श्री अमर सिंह ढांडे: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको पटिकुलर्ज भी दे दूंगा पाचं पोस्टे जो भरी गई है, वह स्वीपर की पोस्टे है ओरउन पर दूसरे लोग लगे हुए है। (विधन)

श्री अमीर चन्द मक्कड़: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्यायंट आफ आर्डर हैं अभी अभी अमर सिंह जी न बोलते हुए कहा कि अम्बाला की म्यूनिसिपैलिटी में स्पीपर की पोस्ट पर दूसरे लोगों को लगाया है, यह अच्छी बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर दूसरे भाई इस काम के में आना चाहते हैं तो यह अच्छी बात है। मध्यम प्रदे ज्ञ सरकार ने भी कहा है क अगर कोई दूसराभाई सफाई का काम करना चाहे तो उसे भी उस काम में लगाया जाना चाहिए।

श्री अमर सिंह ढांडे: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं हरिजनों की प्रोमो इन के बारे में कह रहा था। (व्यवधान एवं भाोर) सर, मैं डिमांड नं0 13, जो समाज कल्याण विभाग के बारे में है, पर बोल रहा हूँ। डिप्टी स्पीकर सर, सरकार कहने को तो कहती है कि हम हरिजनों के लिए बहुत कुछ कर रहे है लेकिन जहां ताक

प्रोमो इन पालिसी की बात है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे चौधरी देवी लाल जी की जब पहली बार सरकार आयी तो 09.02.179 को, इन्होंने हरिजनों के लिए प्रोमो इन पालिसी बनायी थी। कहने को तो यह श्रेय कांग्रेसी नेता है लेकिन आप देखें कि यह पालिसी पहली बार किस सरकार ने बनायी थी? जब दोबारा 1987-88 में चौधरी देवी लाल की सरकार आयी तो उसने सीनियोरिटी-कम-फिटनेस, प्रोमो इन की पालिसी हरिजनों के लिए लागू की। डिप्टी स्पीकर साहब, आप यह देखें कि हरिजनों के लिए किसने काम किया है और किसने नहीं किया है? यह अब आप ही बता दें डिप्टी स्पीकर साहब, अब यह पालिसी लागू है और हरिजननों के लिए प्रोमो इन में भी रिजर्वे इन लागू हैं अभी पिछले दिनों रैवेन्यू डिपार्टमेंट में 104 आदमियों की जो डिप्टी सुप्रिन्टेंडेंट्स की प्रोमो इन हुई है, उसमें केवल 10 या 12 हरिजन व्यक्तियों को यह प्रोमो इन दी गयी है आप खुद अन्दाजा लगाइए, न इसमें बैकवर्ड क्लासिज के लोगों को पूरी रिजर्वे इन दी गयी है और न ही हरिजनों को पूरी रिजर्वे इन दी गयी है। कहने को तो यह बहुत कुछ कहते रहते हैं लेकिन जहां तक रिजर्वे इन दी गयी है। कहने को तो यह बहुत कुछ कहते रहते हैं लेकिन जहां तक रिजर्वे इन-इन-प्रोमो इन का ताल्लुक है, उसको भी पूरी तरह से यह लागू नहीं कर सकते हैं। हरिजनों के साथ कितना भेदभाव यह सरकार कर रही है, यह आप खुद ही अन्दाजा लगा लें?

अब मैं अपने हल्के के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। मेरे साथियों ने अपने अपने हल्कों की दिक्कतों के बारे में बताया है। जो लोग सरकार में बैठे हैं, जब उनके हल्कों में ही बड़ी भारी कमियां हैं तो विपक्ष के आदमियों के हल्कों में तो बिल्कुल ही काम नहीं होते होंगे। मैं तो विपक्ष का अदमी हूँ, इसलिए मेरे हल्के में किसी काम के होने का तो सवाल ही नहीं उठता। इससे कितने दिक्कतें वहां के लोगों को होती होंगी, इसका आप भली भांति अंदाजा लगा सकते हैं? मेरा हल्का गुहला-चीका है। वहां पर पिछली बार जब फल्लु आया था तो सबसे ज्यादा इसको मार पड़ी थी। फसलें तबाह हो गयीं, सड़कें भी काफी टूट-फूट गयीं। लेकिन उन टूटी हुई सड़कों की तरफ कोई ध्यान देना चाहिए था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कैथल जिला के गुहला चीका हल्के के अन्दर एक नया पैसा भी सड़कों की मरम्मत पर खर्च नहीं किया गया और न ही इसके लिए कोई पैसा दिया गया। आज उन सड़कों की इतनी बुरी हालत है कि पैदल चलना भी मुश्किल है मैं, चूंकि अपोजीटिव में हूँ। इसलिए वहां पर कोई काम नहीं हो रहे हैं जबकि बिना भेदभाव के सब जगह पर काम होने चाहिए।

जहां तक शिक्षा की बात है, मेरे हल्के में शिक्षा का बुरा हाल है। वहां पर चीका और भागल में 10 जमादों के स्कूल खोले गए थे जिनकी मंजूरी चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने दी थी। उन दोनों स्कूलों को तोड़ कर, एक छोटे से गांव के

स्कूल को अपग्रेड कर दिया गया। वह गांव चूंकि वहां के पूर्व विधायक का है, जिसका नाम कागथली। उस गांव के स्कूल को 10 जमा 2 तक अपग्रेड कर दिया गया। एजूके इन का इतना बुरा हाल है जिसकी कोई हद नहीं। हमारा हल्का पंजाब के साथ लगता है। उस एरिया में जितनी भी स्कूलज है, उनमें अध्यापक ही नहीं है और जहां है, वहां बहुत ही कम है। सारे स्कूल अध्यापकों ही है और मिडल स्कूल में तो काई एक या दो अध्यापक होते है। आज हमारे हल्के के साथ भेदभाव किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल इस बिना पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए कि वह एक विपक्ष के विधायक का हल्का हैं हम भुरु से ही चोधरी देवी लाल जी के साथ रहे है। मै सरकार से कहना चाहता हूं कि जो ठीक बात है, वह इसे करनी चाहिए। ऐजूके इन के मामले में चीका व भगल में क्या कमी है, उसकसे 10 जमा 2 तक क्यो अपग्रेड नहीं किया जा सकता? वह आपकी हर भात पूरी करताहैं वहां पर बिल्डिंग पूरी है, जमीन पूरी है, फिर सरकार 10 जमा 2 को स्कूल क्यो नहीं खोलती? मेरा कहना यह है कि इसके अन्दर करीब एक महीना पहले गड़बड़ हुई थी, भायद उसकस आप सबों पता होगा। वहां के पूर्व कांग्रेसी विधायक के भतीजे और लड़के ने, कालेज के एक लड़के के साथ इतनी मार-पीट की और पेट में चाकू मारा। वह लड़का आज भी हास्पिटल में पड़ा हैं कालेज के प्रिंसिपल ने उन लड़कों को कालेज से एक्सपैल कर दिया। वहां का पूर्व विधायक आज भी इस इ लू पर कालेज के

प्रिसिपल पर प्रै 11 डाल रहा है कि उन लड़कों को, जिनको एक्सपैल कर दिया गया था, दोबारा एडमिट किया जाए।

जहां तक नहरों ओर माईनजों का संबंध है, मेरे हल्के में दो माईनर्ज पड़ती है। आज तक उनके अन्दर कोई काम नहीं हुआ है। उनकी कभी भी गांद वगैरह नहीं निकाली गई। उपाध्यक्ष महोदय, पानी की हालतय यह है क आज तक टेल पर पानी नहीं पहुंचा है। मेरे एरिया जीरी काएरिया है। अगर वहां पर पूरा पानी न मिले तो जीरी की फसल को काफी नुकसान होता है। मेरे हल्के में बिजली की भी काफी कमी है बिजली की हालत यह है कि दो घंटे बिजली मिलती है। कनक की फसल तैयार है ओर उसे पानी की जरूरत है लेकिन बिजली की कमी की वजह से लोग अपने ट्यूबवैल्ज नहीं चला सकते। आगे जीरी की फसल आने वाली है, उसका सीजन कुछसमय बाद आ रहा है। अगर वहां पर पूरी बिजली नहीं दी गई तो जीरी की फसल की बुआई काफी नुकसान हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं पंचायती के बारे में कहना चाहता हू कि मेरे हल्के में पंचायत की जमीन का एक बहुत बड़ा घपला हुआ था और उसके बारे में आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा। पंचायत की जमीन पर एक पूर्व सरपंच ने कब्जा कर लिया है। यह कब्जा उसने अफसरों की मिलीभगत से किया था। वह चालीस एकड़ जमीन थी लेकिन सरकार ने उसकस कब्जा छुड़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया। जो अब पंचायत बनी, उसने उस

जमीन से उस सरपंच को बेदखल करने का केस तैयार किया लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। जिस अफसरों की मिलीभगत से उस पूर्व सरपंच न पंचायत की जमीन पर कब्जा किया, उन अफसरों के खिलाफ भी सरकार ने कोई ऐक्टान नहीं लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं जंगलात क बारे में कहना चाहता हूँ कि बिलासपुर में जंगलात को नाजायज तौर पर काट लिया गया। आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला के एक प्रश्न के उत्तर में मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वे सरकारी पेड़ नहीं थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि सोलह हजार सरकारी पेड़ नहीं थे। जिनको काटा गया था। एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि वे सरकारी पेड़ नहीं थे। उपाध्यक्ष महोदय, हितने ताज्जुब की बात है कि पच्चीस सौ पेड़ काटने का ठेका दिया गया। लेकिन उस ठेकेदार ने सरकार की मिली भगत से 25 हजार पेड़ काट लिए। उसके खिलाफ कोई ऐक्टान नहीं लिया गया। एक तरफ तो सरकार वन लगा रही है और दूसरी तरफ सरकार के मंत्री घपला कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐक्टान नहीं लिया जा रहा है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपनी बात का दुबारा दोहराना चाहता हूँ कि यह सरकार हरिजनों और बैकवर्ड क्लास के लोगों के सहारे चल रही है लेकिन उनकी भलाई का कोई काम नहीं कर रही है। अगर सरकार उनकी भलाई के लिए कोई पग नहीं उठाएगी तो उन लोगों को कैसे भला हा सकता है?

श्री उपाध्यक्ष: अमर सिंह जी, अब आप खत्म करें।

श्री अमर सिंह ढांडे: सर, सरकार को चाहिए कि हरिजनों को जो हक है, चाहे वह मुलाजमत में है या आम आदमी है, वह उनको मिलना चाहिए। अच्छा जी, अब मैं खत्म करता हूँ। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: अब श्रीमती चन्द्रावती जी बोलेगी।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे न तो गवर्नर ऐड्रेस पर टाईम दिया गया और न ही बजट पर दिया जा रहा है। मैंने एक कट मोशन भी दिया हुआ है। ऐसी क्या बात होगई तजो मुझे टाईम ही नहीं दिया जा रहा है? मुझे टाईम मिलना ही चाहिए। बोलने का मेरा कांस्टीट्यूशनल राईट है यहाँ पर एक एक आदमी को आधा-आधा घंटा टाईम दिया जा रहा है लेकिन मुझे नहीं दिया जा रहा है। ऐसी क्या बात है?

चौधरी जगदीश नेहरा: उपाध्यक्ष महोदय, इन डिमाण्डज पर बोलने के लिए जो टोटल टाईम स्पीकर साहब, ने अलाट किया है, उसके हिसाब से जितना जिसके हिस्से में आता है, आप उतना समय दे दें। ओम प्रकाश जी के हिस्से में अगर एक मिनट आता है तो एक मिनट दे दें और अगर नहीं आता है तो न दें। आप जानते हैं कि हमारे पैसठ मैम्बर हैं और इनमें से केवली दो मैम्बर बोले हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारे मैम्बरज को पूरा समय दिया जाए।

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू): डिप्टी स्पीकर साहब, समय देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं डिमांड पर बोलना चाहती हूँ। इन डिमांड में इरिगे ान की डिमांड तो है लेकिन पावर की डिमांड नहीं है। क्या पावर का अलग से बजट है? मेरे ख्याल से पावर की डिमांड भी होनी चाहिए थी।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं कोआप्रेटिव की डिमांड के बारे में कहना चाहती हूँ। मैं इस बारे में कुछ सुझाव भी देना चाहूंगी। उपाध्यक्ष महोदय, जो कोआप्रेटिव सोसायटीज है, अगर ये डिफाल्टर हो जाते हैं तो कुछ लोग उन पर कब्जा कर लेते हैं। कुछ न उन पर कब्जा कर भी रखा है और वे उसी के हिसाब से रल मिल कर ठीक कर लेते हैं। और दूसरे किसी व्यक्ति को उसमें घुसने नहीं देते। ऐसे लोगों की सोसायटीज में मैम्बरशिप नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, उनको हटाये जाने के लिए सरकार को कोई उचित कदम उठाने चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसके बाद मैं हुड्डा के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। हुड्डा कछेक किसानों की जमीनों को ले ला है लेकिन उनको उसका सही मुआवजा व आल्टरनेटिव नहीं दिया जाता है किसानों के पास उस जमीन के सिवाये खाने पीने का कोई दूसरा साधन नहीं होता और कोई दूसरा काम धन्धा भी उनके पास नहीं होता जिसके सहारे लोग अपना जीवन निर्वाह कर सकें। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से कहूंगी कि जिन लोगों की सरकार जमीन लेती है, उन को सरकार को नौकरिया देनी

चाहिए या कोई दूसरा आल्टरनेटिव सरकार को देना चाहिए ताकि वे लोग, जिनकी जमीन हुड्डा ले लेता है, उसके पास जीवन निर्वाह करने के पक्के साधन हो। पैसा जो सरकार देती है, वह तो एक किस्म का कंपन्सेशन होता है और वह पैसा खत्म भी हो सकता है। अगर सरकार कोई ऐसा साधन ऐसे लोगों को जुटाये जिससे उनका परिवार का गुजारा परमानेंट होता रहे, तो बड़ी अच्छी बात है। उपाध्यक्ष महोदय, अपनी रोजी रोटी कमाना, उनके फण्डामेंटल राइट्स में आता है। इसलिए सरकार इस तरफ ध्यान दें। यह नहीं होना चाहिए कि लोगों को सारी की सारी जमीन ले ली जाए और उनको उसका कोई आल्टरनेटिव न दिया जाए। इसमें कुछ अफसरों का इंटेस्ट भी होता है। इसलिए सरकार ऐसे किसानों को, जिनकी जमीनें ले ली जाती है, उनको आल्टरनेटिव जॉब प्रदान करें।

दूसरी बात मैं सिविल सप्लाइ के बारे में कहना चाहती हूँ। इस बार तो भगवान की कृपा से सभी जगहों पर बारिश के कारण फसल काफी अच्छी हो गई है। पिछली दफा फसल अच्छी नहीं थी। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकारी डिपोज पर राशन का 20 किलो गेहूँ एक परिवार को दिया जाता है। वह सफ़ी ग्रीन्ट नहीं है। इससे एक परिवार का काम नहीं चल सकता। सरकार को ज्यादा मिकदार में गेहूँ मुहैया कराना चाहिए। इसी तरह से दूसरी चीजों की सप्लाइ जैसे चीनी, चावल वगैरह व दूसरे जितनी जरूरी चीजें डिपोज में मिलनी चाहिए, उनकी सप्लाइ में वृद्धि होनी चाहिए

और सभी को सारी चीजें सरकारी डिपोज पर अवेलेबल होनी चाहिए।

इससे आगे मैं पेट्रोल पम्पो क गारे में कहूंगी। मैंने हपले भी एक बार इस बात का जिकर किया था कि पेट्रोल पम्पों के ऊपर डीजल में मिट्टी का तेल मिलाकर बेचा जाता है। जिससे किसानों के ट्रैक्टर, सरकारी जीपों को, व बसों को काफी नुकसान होता है मिट्टी का तेल मिलाअगर अगर तेल बेचा जाएगा तो इंजनो का भट्ठा बैठ जाएगा। डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में काफी फर्क है। जिस कारण से भायद यह हेरा फेरी होती है। या तो सरकार इनकी कीमतों को एक कर दे ताकि अडल्ट्रे इन कम हो सके। नही तो इस ओर सरकार वि ोश ध्यान दे। इससे गरीब किसानों के ट्रैक्टर को काफी नुकसान पहुंच सकता है। जो लोग ऐसे कामों में सलग्न है, उनको अपराधियों श्रेणी में गिना जाना चाहिए। इसका सरकार को जल्दी ही कोठ,न कोई इलाज करना चाहिए। मेरे नोटिस देने के बाद कई जगहों पर छापे भी पड़े है लेकिन यह सफी गीएन्ट नही है। डीजल मे मिलावट करके जो पेट्रोल पम्प वाले बेचते है, उससे जनता को काफी नुकसान होता है। किसान इससे काफी दुखी है। मैं तो यह कहूंगी कि जो विभागीय अधिकारी होते है, उनसे मिलकर ही यह सब कुद होता है। मैं सुझाव दूंगी कि जो ईमादार अफसर हे, उनको ऐसे लोगों को ऊपर चैक होनी चाहिए ताकि वे इस तरह का गलत काम न करे सके।

उपाध्यक्ष महोदय, उससे अपली बात मै बिजली से सम्बन्धित कहना चाहती हूं। मैने पहले भी अर्ज किया था कि लौहारू के अन्दर 33 के० वी० का सब स्टे इन लगा हुआ है, उसकसे 66 के० वी० कर दिया जाना चाहिए। इसी तरह से बहल का, डिकोवा का है। नकी पुर का एक दफा फाउंडे इन स्टोन सरकार की तरफ से रखा गया है। मेरी प्रार्थना है कि सरकार वहां का काम जल्दी करवाये। इसी तरह से भोवड़ा व बादड़ा जो मेरे हल्के में आते है। मेरी कांस्टीचुऐन्सी तीन जिलों से मिली हुई है और भादडत्रा महेन्द्रगढ़ जिला में पड़ता है। मेरी गुजारि 1 है कि इन सभी सब स्टे इन पर जल्दी ही काम पूरा करवा दिया जाए ताकि लोगों को सही मिकदार में बिजली मिल कसे ओर बिजील का सही डिस्ट्रीब्यू इन हो सके। दूसरे डिप्टी स्पीकर साहब, बिजली के मामले में कुछ सुधार जरूर हुआ है, इतना ही सुधार ओर होना चाहिए। यह सुधार तभी हो सकता है जब ज्यादा थर्मल या हाइडल पावर प्लांटस लगाए जाएंगे। आपको पता है कि रोजाना नई नई इंडस्ट्रीज लगती है। बिजली के बिना उनको भी मुश्किल होती है आज मुझ जगाधरी के कुछ लोग मिले थे जगाधरी, फरीदाबाद या सोनीपत जैसे जगहों में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगी हुई है वे लोगों को भी रोजगार देती है ओर अपना रोजगार भी चलाती है। आपको पता है कि जमीन अब इतनी नहीं रही है। कुछ जमीन पर लोग बस जाएंगे, कुछ सड़के वगैरह बनाने में आ गई इसलिए लोगों को काम देने के लिए केवल इंडस्ट्री ही है।, इसके लिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा

मौका देना चाहिए। हमारी लोहारू के लोगों की काफी समय से मांग है कि वहां पर एक पोलेटैकनिक होना चाहिए। इसी तरह से दादरी की एजूके न सोसाइटी ने रिप्रजैटे इन दिया है कि उनको फारमैसी कालेज खोलने की इजाजत मिलनी चाहिए। इसी तरह से हस्पतालों की हालत है। लोहारू और दादरी के हस्पतालों को मुझे पता है, उनकी बहुत अच्छी हालत नहीं हैं वहां पर ज्यादा डाक्टरों की जरूरत है ओर दवाईयों तो न के बराबर है। मेरी आपके द्वारा सरकार से अपील है कि जो जरूरी दवाईया गरीब आदमी के लिए चाहिए, कम से कम वे तो होंनी चाहिए। आपको मालूम है कि गांवा के हस्पतालों में तो गरीब आदमी ही जाते हैं इसलिए वहां पर ज्यादा डाक्टर भी भेजे जाएं और दवाईयों भी दी जाए।। कई डाक्टर ऐसे है जो गांव में नहीं जाना चाहते, इसलिए सरकार को इस बारे में भी ध्यान देना चाहिए। यही हालत स्कूलों की है। जो स्कूल भाहरों में है, वे तो स्टाफ के साथ ओवर क्राउडिड हो जाते हैं और गांवों में पोस्टे खाली पड़ी रहती हैं हमारे यहां बिसलवास में कई सालों से हैडमास्टर नहीं है। यही हाल खरखड़ी ओर मंडोलजी कला का हैं बच्चे स्कूलों में नकल क्यों करते है क्योंकि अध्यापका उनको नहीं पढ़ाते? यह तो वह बात हुई कि लौहा खोटा लोहार भी खोटा। लोहारू में एक डाक्टर है जो ड्रगिस्त है। मैंने विभाग वालों को कहा कि इसको ऐसी जगह लगाओं जहां जिम्मेदारी नह हो, वरना इसका पैन् इन देकर घर भेज दो। ऐसे आदमियों को ऐसी जगह पर लगाया जाए जहां डाक्टरों की तादाद ज्यादा हो। जहां पर डाक्टर की एक ही पोस्ट हो, ऐसी जगह पर

ऐसे लोगों को न लगाया जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी बहुत बहुत भुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे टाईम दिया।

चौधरी औम प्रका 1 (बेरी): उपाध्यक्ष होदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आखिर टाईम दे ही दिया। मैं डिमांड नं0 11, 15 और 17 पर बोलूंगा। मैं सबसे पहले इरीगे 1न के बारे में कहना चाहूंगा। आज हरियाणा प्रदे 3न की 70 प्रति 1त जनता कृशि पर आधारित है ओर कृशि के लिए इरीगे 1न वाटर की जरूरत है नहरी पानी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 17 साल से हरियाणा प्रदे 1 के अन्दर.....

श्री उपाध्यक्ष: बेरी साहब, आप एक मिनट के लिए बैठे। जिन मैंबर साहेबान ने बोलने के लिए अपने नाम दिए हुए हैं, मेहरबानी करके अनीज सीट पर रहे वरना उनका नाम कट जाएगा।

चौधरी ओम प्रका 1 बेरी: उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदे 1 में जहां तक सिचाई के लिए पानी का ताल्लुक है, उसमें बहुत बडा भेदभाव जमुना सिस्टम के एरिया के साथ किया जा रहा है। उस एरिया के साथ ज्यादा भेदभाव हो रहा हैं एस्टिमेंट्स कमेटी का चेयरमैन होने के नतो मैंने पिछले साल 1992-93 में उन कमेटी की 25वी रिपोर्ट हाउस के सामने पे 1की थी। उस रिपोर्ट में यह साफ तौर पर द 1र्या गया था कि हरियाणा प्रदे 3न में रावी ब्यास का 18 लाख एकड फीट पानी आ रहा हैं

गुडगांव और भिवानी जिलों का हक है लेकिन वह पानी उन जिलों को न देते हुए वह पानी हिसार जिले के हांसी उपमण्डल को छोड़ कर, बाकी सभी उपमंडलों को, पूरस सिरसा जिला, कैथल जिला ओर जींद जिले के नरवाना क्षेत्र को अनअथोराइज्ड-वे से दिया जा रहा है यह पानी पिछले 17 साल से भाखड़ा मुख्य नहर में डाल कर हरियाणा प्रदेश में लाया जा रहा है। जब इस बारे में सवाल उठाया गया तो कह दिया गया कि नरवाना ब्रांच की इतनी कैपेसिटी नहीं है जिससे इस पानी को लाया जा सके। इस बारे में मैं सरकार को सुझाव दूंगा जिससे इस पानी को लाया जा सके। इस बारे में मैं सरकार को सुझाव दूंगा जिसके एरिएर जमना सिस्टम में पानी पहुंचाया जाए ताकि जिन इलाकों को वह पानी है, उनको वह पानी दिया जा सके। एक तो नरवाना ब्रांच के किनारों को तीन तीन फुट ऊंचा किया जाए ओर नरधाना ब्रांच की छटाई करवाई जाए। यह काम केवल 50 किलोमीटर पंजाब के क्षेत्र में केवल 3 महीने में किया जा सकता है। नरवाना ब्रांच की आज तक डीसिल्टिंग नहीं करवाई गई, वह बिल्कुल अंटी पडत्री है। नरवाना ब्रांच की 4029 क्यूबिकस की कैपेसिटी थी, वह आज घट गई है। उसकी तरफ आत तक ध्यान नहीं दिया गया। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में पोलिटिकल आधार पर दक्षिणी हरियाणा के साथ पिछले 17 साल से सिंचाई पानी के बारे में भेदभाव होता रहा है। जिस जिले का मुख्य मंत्री बना, उसने उसी जिले के बारे में सोचा, दूसरे जिलों के बारे में नहीं सोचा। (गोर)

सिंचाई मंत्री (चौधरी जगदी 1 नेहरा): डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। डिप्टी स्पीकर साहब, यह बात बार-बार चौधरी ओम प्रका 1 बेरी ने प्रैस में भी कही है। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि दक्षिणी हरियाणा के साथ सिंचाई के पानी के बारे में कतई भेदभाव नहीं है और वह क्यों नहीं है? वह इसलिए नहीं है क्योंकि जो सिस्टम पिछला चला आ रहा है वह इनके जो बड़े भाई श्री भोर सिंह इरीगे 1 न मिनिस्टर थे, के समय से ही चला आ रहा है। वे ज्वायंट पंजाब में भी रहे, उन्होंने जो पानी तकसीम किया, उसे हिसाब से सभी जगहों पर पानी दिया जा रहा है। उस सिस्टम को बनाने में चौधरी रिजक राम और लहरी सिंह भी रहे हैं जो भाखड़ा और जमना नपदी के पानी को सिस्टम है, वह उसी हिसाब से चल रहा है। उस सिस्टम को किसी भी सरकार ने नहीं बदला। मैं उस सिस्टम को चौधरी भजनल लाल की सरकार ने बदला, किसी भी सरकार ने नहीं बदला। इन्होंने तो इस तरह से बात क करके यह मुद्दा उठाना है। डिप्टी स्पीकर साहब, डब्ल्यू0 जे0 सी0 की जो कैपेसिटी है, उसमें पानी कम आत है। उसका रीजन है और वह यह है कि भाखड़ा नहर में जो पानी है, वह स्टोर कर लिया जाता है ओर लीन सीजन में, सदियों के टाईम में वह पानी लिता रहता है। जो भाखड़ा का पानी है वह स्टोर हुआ हुआ है और उसकसे जब पानी की कमी होती है, तब उसकसे छोड़ा जाता है ओर लीन सीजन में यह पानी भाखड़ा के एरिया में सप्लाई हाता है इसलिए यह कहना कि दक्षिणी हरियाणा के साथ भेद भाद होता है, यह गलत बात हैं

इसके अलावा जब तक जमना के बारे में कोई समझौता नहीं हाता, तब तक उसकस पानी स्ओर नहीं होगा। माननीय सदस्य द्वारा ऐसी बातें केवल पोलिटिकल गेन लेने के लिए कही जाती है, और इनका कोई मकसद नहीं है।

चौधरी ओम प्रका । बेरी: उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं हैं ये अपनी बात अपने जवाग में कह सकते हैं। मंत्री जी ने जो बात कही है उससे मैं डिमोरेलाइज होने वाला नहीं हूं। दक्षिणी हरियाणा के सागि जो सिंचाई पानी के बारे में भेदभाव हुआ है, चाहे वह किसी कारण से हुआ, वह दूर होना चाहिए। वह भोर सिंह की वजह से हुआ, चाहे रिजक राम ओर लहरी सिंह की वजह से हुआ, आज आप सत्ता में है आपको यह डिस्क्रिमिने ान दूर करनी चाहिए। मंत्री जी जान बूझकर हाउस को गुमराहकर रहे है। पोलिटिकल आधार पर दक्षिणी हरियाणा सरकार के साथ सिंचाई के पानी के बारे में पिछले 17 साल से भेदभाव किया जा रहा है। ओर इस भेदभाव में चौधरी भोर सिंह, चौधरी लहरी सिंह आदि का कोई हाथ नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय मैं सुझाव दे रहा था थका एक तो नरवाना ब्रांच की छंटाई करवाई जाए। उसके किनारों को तीन तीन फुट ऊंचा किय जाए। दूसरा इनका यह कहना कि इसमें 18 लाख एकड़ फुट पानी नहीं समा सकता तो इस बारे में मरी परपोजलन यह है कि बरवाला लिक कैनल को, जिसमे भाखड़ा का पानी लगता है, उसकसे पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी से अगर जोड़ दे, जिस की लम्बाई 30 कि० मी० है,

इससे सिवायनी कैनल का कमांड एरिया ओर हांसी सब डिवीजन में भाखड़ा का पानी मिल सकता है। और इस तरह से पूरा 18 लाख एकड़ फुट पानी जो हमारा हक है, वह इन इलाकों को दिया जा सकता है इसके अलावा, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि पानी की वजह से इनकी 22 दिन नहरें महीने से चलती है। यानी हिसार सिरसा जो इनके इलाके में तो एक महीने में 22 दिन लहरें चलती हजबकि रोहतक और सोनीपत में ऐ महीने में एक सप्ताह नहरें चलती है ओर भिवानी में एक माह में साढ़े तीन दिन नहरी पानी वहां के लोगों के मिलता है। इसके अलावा, गुडगांव फरीदाबाद में तो इस पानी को ले जाने के लिए नहरों के निर्माण की बात तो छोड़िए नहरों के निर्माण के बारे में सोचा तक नहीं गया। इता ब्रेजन डिसक्रिमिने इन है। इसके अलावा, मैं आंकड़े देकर बताना चाहता हूँ कि हमारे यहां नहरी पानी पहुंचाने के लिए हरियाणा प्रदेश में दो मुख्य सिस्टम हैं एक तो यमुना सिस्टम और दूसरा भाखड़ा सिस्टम है। एक तो यमुना सिस्टम और दूसरा भाखड़ा सिस्टम। यमुना सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूँ कि यमुना का कमांड एरिया 40 लाख एकड़ है, पानी उसके लिए 38 लाख एकड़ फुट, भाखड़ा सिस्टम में 29 लाख एकड़ रकबा ओर 58 लाख एकड़ फुट पानी इतना ब्रेजन डिसक्रिमिने इन है। इसके अलावा यमुना सिस्टम की आबादी 80 परसेंट, एरिया 70 परसेंट और पानी 40 परसेंट। भाखड़ा की 20 परसेंट पापुले इन, 30 परसेंट एरिया और 60 परसेंट हरियाणा का पानी मिलता है। ए योर्ड वाटर एक साल में जो भाखड़ा सिस्टम

से मिलता है, वह है 264 दिन और यमुना सिस्टम को मिलता है। एक साल में 96 दिन चानी 3 गुना पानी इनको अधिक मिलता है। यह हालत उन लोगों ने पानी के बारे में कर रखी है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि.....

चौधरी जगदी । नेहरा: यह हाउस को गुमराह कर रहे हैं यह जो आंकड़े दे रहे हैं वह गलत हैं यह जो भाखड़ा सिस्टम है, वह 1954 का बना हुआ है और डब्ल्यू0 जे0 सी0 सैकड़ों सालों से है। मैं बताना चाहता हूँ कि जब भाखड़ा नहीं बनी थी तो उस समय उस एरिया की क्या हालत थी और जब भाखड़ा बन गया तो उस समय बटेज करने में क्या इनके बड़े भाई भोर सिंह का हाथ नहीं है?

चौधरी ओम प्रका । बेरी: वे तो 1956 में मंत्री बने थे जबकि भाखड़ा 1954 में बनी।

चौधरी जगदी । नेहरा: ये जो आंकड़े दे रहे हैं, वे सही दें। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा आपसे अनुरोध है कि ये आंकड़ें वह दें जो सही हों और सारे हाउस को गुमराह करने के लिए वही बातें दुबारा न कहें कि दक्षिणी हरियाणा के साथ अन्याया हो रहा है। दक्षिण हरियाणा की नहरे कोई नयी नहीं है बल्कि 40-50 साल पहले की बनी हुई है, न कि आज की। ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ पोलिटिकल गेन लेने के लिए बातें कर रहे हैं, इनका और कोई मकसद नहीं है।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में कुल पानी, जिसमें ट्यूबवैल्ज का पानी भी शामिल है, वह है 16 एम0 ए0 एफ0, जबकि हमें इससे कम से कम 2 गुना पानी चाहिए। यह पानी कहां से आयेगा, इस पानी को लाने के लिए क्या रिसोसिज हो इस बारे में हरियाणा सरकार ने सोचने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि इनके इलाके में आज हो हकूमत कर रहे हैं। 17-18 साल से, वही पानी के बारे में गड़बड़ कर रहे हैं। इनके इलाके में पानी बहुतायत में है, इसलिए इस बारे में इन्होंने नहीं सोच कि हमें भी पानी की जरूरत है, चाहे हमारा इलाका पसासा मर जाये, जमीन पसायी मर जाये लेकिन इस बात की इनको कोई चिंता नहीं है इस बारे में सरकार को डिस्क्रीमिनेशन दूर करना चाहिए और पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को बराबर पानी मिलना चाहिए। इसे लिए रिसोसिज कौन से हैं कैसे इनको पानी मिल सकता है? इसके बारे में मैं जो मैं सुझाव दूँ। अगर उन पर सरकार अमल करे तो यह समस्या दूर हो सकती है और सारे इलाकों का पानी मिल सकता है मेरा सुझाव है कि आगरा कैनाल को कंट्रोल हरियाणा सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए और यदि हरियाणा सरकार यह कंट्रोल अपने हाथ में नहीं ले सकती तो बैनिफिटारी स्टेट होने के नाते हरियाणा सरकार को चाहिए कि सैन्ट्रल सरकार के साथ मिलकर इसका कंट्रोल अपने हाथ में ले ले ताकि जितना हिस्सा गुड़गांव और फरीदाबाद जिलों को है, वह पानी उनको मिल सके। दूसरे, दादूरपुर नलवी नहर की

स्कीम काफी दिनों से धूल चाट रही है यह 1985 में मंजूर हुई थी। जैसा कि मंत्री महोदय, ने बताया कि जब यह मंजूर हुई थी तो उस वक्त से इसका खर्च बढ़कर 5 गुना हो गया है मैं चाहता हूँ कि इस नहर को बनाने पर अमल किया जाए ताकि कम से कम 3-4 जिलों को फायदा हो सके और उनको नहीरी पानी सिंचाई के लिए मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं बातना चाहता हूँ कि यमुना पर किसानों के बारे में एक स्कीम थी। सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके जल्दी से जल्दी यह बांध बने, रिजरवायर हो ताकि पानी किसान को मिल सके और खेतों की प्यास बुझ सके। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हम दिल्ली को पीने का पानी दे रहे हैं। क्या दिल्ली को पीने का पानी उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी केवल हरियाणा सरकार की है? यह बात ठीक है कि दिल्ली को पीने का पानी उपलब्ध करवाना सबका फर्ज बनता है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हरियाणा जैसी छोटी सी स्टेट अकेले ही उसको पानी की जरूरत को पूरा करें। यमुना के पानी में दिल्ली का कोई भोयर नहीं है। रावी ब्यास में से 2 लाख एकड़ फुट पानी उसके हिस्से का है। इस बारे में केन्द्र सरकार से बात करके दूसरी स्टेट्स को भी दिल्ली को पानी उपलब्ध करवाने के लिए हिस्सेदार बनाया जाए। यू0 पी0 भी दिल्ली की एडज्वायनिंग स्टेट है और काफी मिकदार में उसके पास पानी अवेलेबर है। इसलिए वह भी दिल्ली को पीने का पानी उपलब्ध करवाने में हिस्सा दें। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूँ ताजेवाला हैड वर्क्स 100 साल से ज्यादा

पुरान हो चुका है हथनी कुण्ड बैराज की स्कीम के बारे केन्द्र सरकार से जल्दी से जल्दी बात करके इस स्कीम को अमली जामा पहनाया जाना चाहिए ताकि सारी स्टेट को हम ठीक ढंग से सिचाई के लिए पानी दे सके ।। हरिके—हैडवर्क्स के बारे में मैं एक कहना चाहता हूँ। फिरोजपुर में सतलुल के बेड़े से पानी यूज करता है। यह पानी पंजाब से हाता हुआ, पाकिस्तान से हाता हुआ समुद्र में जा गिरता है आरे वेस्ट जा रहा है इस बारेमें में मेरी परपोजल है। इस बारे इस स्कीम भी भाायद बनी थी। इस पानी हो हम राजस्थान कैनल में डल दें ओर यह पानी राजस्थान को दे दिया जाए। जितना पानी राजस्थान को दें उतना पानी हम हरियाणा के लिए ले लें तो हरियाणा को उस पानी से लाभ हो सकता है। (विधन)

श्री उपाध्यक्ष: बेरी साहब, आप वाइंड आप करिए। आपको टाईम आप हो चुका है। (विधन) आप अपनी बात सिर्फ 2 मिनट में समाप्त करें। (विधन)

चौधरी ओम प्रका 1 बेरी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा टाईम नहीं लूंगा सिर्फ 5-7 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं तो 5-7 मिनट ही बोला हूँ, ज्यादा टाईम तो इरिगे न मिनिस्टर साहब नपे ही ले लिया। (विधन) उपाध्यक्ष महोदय, नहरों की हालत बहुत बुरी हैं अब तै डी-सिल्टिंग के बारे मैं कहना चाहता हूँ। हमारे इलाके में झज्जर सब-ब्रांच बहुत बड़ी नहीं है, उसकी कैपेसिटी 900 क्यूसिक पानी की है परन्तु इस समय उस

की क्षमता केवल 450 क्यूबिक पानी की रह गयी है वहां पर मंत्री जी भी एग थे ओर देख कर आए थे। मेरा सुझाव है कि भीघ इस नहर की छटाई करवाई जाए ओर लाईनिंग करवाई जाए ताकि पानी टेल तक पहुंच सकें। उपाध्यक्ष महोदय, एक और प्रॉब्लम भी है। जे0एल0एन0 के साथ साथ जे0एस0वी0 भी पैरलल चलती हैं सीपेज की प्रॉब्लम बहुत भारी प्रॉब्लम है। जे0 एल0एन0 के साथ डिच ड्रेन की स्कीम मंजूर की गई थी। उपाध्यक्ष महोदय, केवल स्कीम मंजूर करने का कोई फायदा नहीं है बजट एलोकेशन होनी चाहिए ताकि काम हो सके। जे0 एल0 एन0 के साथ जे0 एस0 वी0 भी पैरलल बहती है। दोनों तरफ से डिच ड्रेम बनेगी, तब जा कर वाटर लैगिंग की प्रॉब्लम हमल हो सकेगी। हमारे अकेले जिले का 40 हजार एकड़ का रकबा सीपेज की वजह से खराब हो चुका है। इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, गजब की बात यह है कि जिन लोगों के खेत 15-16 साल वाटर लैगिंग की वजह से खराब हो गए हैं ओर एक दाना भी पैदा नहीं होता, उनसे आबियाना वसूल किया जा रहा है। अगर यह बात गलत हो तो बेनाक हाउस की कमेटी बना दी जाए जो इस बात का पता करे लें। उन किसानों से आबियाना वसूल नहीं होना चाहिए बल्कि उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इसी ढंग से मैं एक बात एस0 वाई0 एल0 नहर के बारे में कहना चाहता हूँ। पिछले ढाई-तीन साल से जब से मुख्य मंत्री जी प्रदेश के मुख्य मंत्री बने हैं, रोज ब्यान दे देते हैं कि एस0 वाई0 एल0 कैनल एक वर्ष में बन जाएगी। मैं जानना चाहता हूँ कि वह साल किस

तारीख से भुरू होगा ओर कौनसी तारीका को खत्म होगा और उस साल के कितने दिन होंगे? ताकि हरियाणा की जनता इस गुमराही से तो बच जाए। उपाध्यक्ष महोदय, कभी मुख्य मंत्री जी को कुछ ब्यान आ जाता है ओर कभी कुछ और, रोज ये तरह तरह के ब्यान दे देते हैं ओर बेअन्त सिंह का कुछ और ब्यान आ जाता है। (घण्टी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस बारे में हरियाणा भवेत-पत्र जारी करे ताकि हरियाणा की जनता को पता लग जाए कि यह नहर बनाने की हरियाणा सरकार की मं ता भी है या नहीं। एस० वाई० एल० कैनाल की कन्स्ट्रक्शन के बारे में हरियाणा सरकार को इन-डिफरेंट एटीच्यूड हैं अगर यह नहर बन गई तो फिर रावी-व्यास का पानी भाखड़ा कैनाल में डालने की जरूरत नहीं होगी, वहां से सीधे उसमें डाल कर यमुना से जा मिलेगा और उस पानी की ये लोग चोरी नहीं सकेंगे। यह नहर बनाने का हरियाणा सरकार को कोई इन्ट्रैस्ट नहीं है (विधन)

श्री उपाध्यक्ष: बेरी साहब, आपका समय खत्म हो गया है, अब आप बैठे।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं दो मिनिट एग्रीकल्चर के बारे में लेना चाहता हूँ। एग्रीकल्चर के बारे में मेनेजमेंट को भी दिया था वाटर की परीपर मैनेजमेंट के लिए सरकार काफी जोर देती है। है सप्रिकल सैट्स के द्वारा सिंचाई करने से पानी को काफी बचत होती है। हमारे प्रदेश के

अन्दर सप्रिकलर सैट्स पर सेल्ज टैक्स है, जबकि एडज्वायनिग स्टेट्स में कोई सेल्ज टैक्स नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, खासकर दक्षिणी हरियाणा में आबपा फी के लिए यह सबसे बेहतरीन साधन हैं मैं सरकारसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार एग्रीकल्चरल इम्प्लिमेंट्स को सेल्ज टैक्स से एग्जैम्प्ट किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, करनाल के अन्दर एक दुकान सरकार ने खोल रखी है वहां पर अप्रोच द्वारा पांच हजार रूपए सैम्पल ठीक रकने के लिए लिए जाते है। यह बहुत ही घटिया बात है। मैं पूछता हूं कि जिलों में डिप्टी डायरेक्टर कृषि विभाग किस लिए बैठा हुआ है? किसानों को मार्केट में कृषि अधिकारियों को मिली भगत से घटिया इन्सैक्टीसाईडस तथा पैस्टीसाईडज बेचा जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: बेरी साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब अमर सिंह धानक बोलेगे।

श्री अमर सिंह धानक (बवानी खेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं डिमांड नं० 17 एग्रीकल्चर, डिमांड नं० 15 इरीगे टन, डिमांड नं० 16 इंडस्ट्रीज, डिमांड नं० 23 ट्रांसपोर्ट, डिमांड नं० 13 सो टाल वैलफेयर, डिमांड नं० 9 एजुके टन आदि पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने और आररेबल वित्त मंत्री जी ने जो बजट सदन में रखा है, वह टैक्स रहित है। यह किसान को समृद्ध और बैकवर्ड क्लासिज ओर भाडलकास्ट को आगे लाने के लिए हैं उपाध्यक्ष महोदय, हमारा

दे । कृषि प्रध्यान देश है । आज अगर किसान की हालत सुधर जाएगी तो यह बहुत ही अच्छा होगा । अगर किसान सुखी है तो दे । सुखी है । ओर अगर किसान दुखी है तो सारा दे । दुखी है । जब भी किसान की हालत खराब हुई, तो कही पर बाढ़ की वजह से, कही पर सूखे की वजह से । सरकार ने ऐसी हालत में किसानों को कई तरह की सहायता देकर बचाया । उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री मुख्यमंत्री जी ओर वित्त मंत्री से दरखास्त है कि अगर एग्रीकल्चर, इरीगे ान और इलैक्ट्रीसीटी को बजट में ज्यादा पैसा दे दिया जाए तो हमारी स्टेट के हालत ओर अच्छे हो सकते है । वित्तमंत्री जी ने तीनों मदों पर जोर दिया है । एग्रीकल्चरका मतलब मै यह समझता हूं कि अगर किसान को जयश्रत के मुताबिक पानी मिल जाए तो वह काफी तरककी कर सकता है हरियाणा का किसान बहुत मेहनती है । वह कड़ाके की सदी ओर धू की परवह भी नहीं करता । इसलिए उसे पानी जरूरत के मुताबिक मिलना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से बहुत सारी बातें आती हैं इधर के विरोधीर भाई बोलकर नुक्ताचीनी तो करते है लेकिन सही सुझाव देने के लिए तैयार नहीं । ये लोग जब कुर्सी पर होते है तो एस० वाई० एल० का भूल जाते है ओर कुर्सी से हटते ही उसको याद करने लगते है, आलोचना करते हैं यह एस० वाई० एल० का मामला कई सालों से लटका हुआ है । आज तारु मुख्यमंत्री था, तब उसने भी कोई बहुत कोि । । नहीं की । अगर वे कोि । । करते तो बहुत पहले ही हरियाणा के खेतों में एस० वाई० एल० का पानी अया हुआ होता है क्योंकि जब वे उप

प्रधानमंत्री थे ओर उनको बेटा चीफ मिनिस्टर था, उस समय पंजाब में उनका पगड़ी बदल भाई मुख्यमंत्री था। अगर यह प्रयास करते तो बहुत जल्दी ही हरियाणा में इसका पानी आ सकता था। डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस यह कहता हूँ कि मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल ही रावी व्यास का पानी एस0 वाई0 एल0 में ला सकते हैं बाकी सब देख लिए हैं। (विधन)

श्री सतबीर सिंह कादयान: सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। उपाध्यक्ष महोदय, जब चौधरी देवी लाल जी उपप्रधानमंत्री थे, जत तो पंजाब में गवर्नर राज था जबकि ये पगड़ी बदल भाई का राज बता रहे हैं। चौधरी देवी लाल जी ने ही 80 प्रति अंत काम एस0 वाई0 एल0 का कराया था जबकि आज कुछ भी इस नहर का काम नहीं हो रहा है।

श्री अमर सिंह धानक: डिप्टी स्पीकर साहब, 1977 में कौन था? 1977 में तो देवी लाल जी ही थे। मैं 1977 की ही बात कर रहा हूँ ये तो अच्छी बात कहने पर इंटरफियर ही करते हैं। (ओर एवं व्यवधान)

श्री जसविन्द्र सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, अगर ये 1977 की ही बात कर रहे हैं। तो उस समय उनका बेटा सी0 एम0 हां से आ गयात्र? चौटाला साहब तो उस समय सी0 एम0 थे ही नहीं।

श्री अमर सिंह धानक: उपाध्यक्ष महोदय, मैं ताऊ के बारे में कह रहा था कि वे पानी ला सकते थे। लेकिन वे पानी नहीं

लाए। इसके अलावा, पिछली बार हरियाणा में रिकार्ड तोड़ फसल का भाव मिला है जिसकी वजह से किसान खुशहाल हुए हैं किसानों को बहुत अच्छा भाव मिला, जबकि तारु के राज में ऐसे भाव किसानों को नहीं मिले। उपाध्यक्ष महोदय, अगर परमे वर की कृपा हो गयी तो इसबार भी रिकार्ड तोड़ फसल होगी और इसको रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। इस साल हमारी रिकार्ड तोड़ पैदावार होगी। (विधन) मैं इरीगे टन के बारे में बता रहा था कि पिछली बार तारु की सरकार में इरीगे टन एंड पावर मिनिस्टर चौधरी भाम और सिंह सुरजेवाला थे। उस समय 1987 में, ताल्लु सिवाड़ा लिंक मार्डनर का एक फाउंडे टन स्टोन रखा गया था। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) इसके लिए पैसा भी निकाल दिया गया था जो 49.45 लाख रूपया था और काम भी भुग्य हो गया था लेकिन तारु की सरकार अनने के बाद उस पत्थरको तोड़कर नहर में डाल दिया गया। यह मार्डनर नहीं बनायी गयी अगर बनी जाती तो चार गांव सिवाजपुर, मंढावा और लोहासीजाटू का पानी मिल जाता। इसक अलावा तारु के चार सालों के राज में भूरे मार्डनर, खानक मार्डनपर, गंडावास मार्डनर के जो पत्थर रखे गये थे इन पत्थरों को तोड़कर नहर में डाल दिया। ये अगर कोई मोर्डनर बना दते तो किसाना सुखी हो जाते, पैदावार बढ़ती और वे लोग इनका गुणगान करते लकिन इन्होने इनको बनवाने के बजाए उल्टा काम किया। अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार से प्रार्थिन है कि जो पत्थर इन्होने तोड़े है कम से कम अब उन्हें लगाकर उन लहरो का काम भुरू करवा कर पानी चालू करवाया जाए।

श्री अध्यक्ष: गुप्ता साहब, आप बोलने के लिए कितना समय लेंगे।

वित्त मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): सर, मैं बोलने के लिए दस मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष ठीक है। अगर सिंह जी, आप जल्दी ही खत्म करें क्योंकि आपका टाईम भी हो गया है।

श्री अमर सिंह धानक: स्पीकर सर, ऐजूके इन के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मेरे हल्के में कंवारी और जमालपुर में 1986-87 में बारह लाख इकतालसी हजार प्रति बिल्डिंग के हिसाब से 24.82 लाख रुपये खर्च करके सरकार ने यह दोनों बिल्डिंग बनाई थी अगर वह 10 जमा 2 बिल्डिंग बनकर तैयार है तो उनको 10 जमा 2 बनाया जाए। इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट के मामले में बसों के बारे में कहना चाहूंगा कि यह ठीक है कि सहूलियत बढ़ती है लेकिन बसों को पूरी तरह से इंतजाम नहीं है। बसे बढ़ाई जाएं और भिवानी डिपो में और अधिक बसें दी जाएं ताकि लोगों को सहूलियत मिल सकें भिवानी जिले में सभी मार्इनर की टेल है खास तौर पर बवानी खेड़ा टेलों को हल्काहैं मेर सुझाव है कि इरीगे इन मिनिस्टर साहब इसको नोट करें। 121 बुरजी सुन्दर ब्रांच से 179 बुरजी तक हिसार डिवीजन में हैं टेल और हैड एक डिवीजन में रखे जाएं ताकी पानी की डिस्ट्रीच्यू इन ठीक ढंग से होसके। इससे 150 क्यूसिक जो टेलों का पानी है वह हैड वाले ले

जाते हैं वह बवानी खेड़ा के हल्के का पानी है इलैक्ट्रिसिटी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब से पावर मिनिस्टर साहब ने यह महकमा संभाला है। काफी यत्न किया गया है काफी कोर्पोरेशन की है। यदि बारिश नहीं होती तो वे बिल्कुल विफल हो जाते, बारिश ने उनको बचाया। उनकी मेहनत और भगवान की कृपा से किसान को काफी राहत मिली है मेरी गुजारिश है कि गांवों के छीये की तरफ से टिमटिमाते हुई बिजली है थ्री फेज की लाई सब जगह दी जाए जिससे चक्की चल सके। सिंगल फेज की लाईट तो दीये के बाराबर हैं जितनी देर हरियाणा में बिजली रहे तीन फेस की होनी चाहिए। गांव ओर भाहर में एकेई डिसक्रिनेशन नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों मैं सिवानी के गांवों में गया था। खाना खाने के वक्त बिजली चली जाए तो बड़ी परेशानी होती है। मैं पावर मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ढंग से हो ताकि सभी को बिजली मिल सके। इन भावों के साथ मैं इस डिमांडज को अपनी तरफ से समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ (साल्हावास): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, बजट में प्रावधान किए जाते हैं, रूल बनाए जाते हैं फिर बजट को सदन में पेश किया जाता है। मैं जानना चाहूंगा कि जब हम बजट को पास करते हैं, क्या उसको चैक करते हैं कि यहां मिसयूटीलाइजेशन हुआ है, ठीक तरह से

खर्च हुआ या नहीं हुआ? वित्त मंत्री जी ने अपने बजट इकोनोमिक सर्वे आफ हरियाणा में माना है कि टोटल 46.33 लाख मैनडेज होंगे लेकिन 31 दिसम्बर तक केवल 12.05 लाख मैनडेज ही कर पड़े। मैं गुप्ता जी से पूछना चाहूंगा कि 31 दिसम्बर तक 12.05 लाख मैनडेज कवर कर पाए है, बाकी तीन महीनों में 34 लाख मैनडेज कैसे क्रिएट करेंगे? अगर 34 लाख क्रिएट कर भी दिये तो इस तरह से करने का क्या यूज होगा? ट्रैक्टर के द्वारा मैनडेज खोदे जा रहे हैं, उसकसे चैक करना चाहिए। ट्रैक्टर से खोद कर मैनडेज बना देंगे। इसी तरीके से फंड की एलोटमेंट गर क्वार्टरली हो जाते उसका यूटीलाइजेसन हो सकता है। डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिए जाते हैं कि 31 मार्च से पहले-पहले यह पैसा खर्च हो जाना चाहिए। इसका परिणाम यह होता है कि अफरा-तफरी में पैसा खर्च किया जाता है, पैसा फूंक दिया जाता है ताकि किसी तरह से पैसा खत्म हो जाए। इस तरह का प्रोविजन करने का क्या फायदा होगा? क्वार्टरली, फंड डिपार्टमेंट वाइज पैसा दिया जाए ताकि पैसे का दुरुपयोग न हो।

डिमांड नं० 3 होम के बारे में है। पुलिस का जौ रवैया हमारे प्रति है या हमारा पुलिस के प्रति है, वह अच्छा नहीं है पुलिस को गाली न सिखाकर अच्छी बातें सिखानी चाहिए ताकि वे पब्लिक की सुरक्षा करें, समाज में अच्छा वातावरण पैदा करें। आज अगर मंत्री जी के लड़के सेफ नहीं है तो आम आदमी का क्या हाल होगा? पुलिस का आदमी भी सेफ नहीं है तो ऐडमिनिस्ट्रेसन

बरकारर कैसे रखा जा सकता है? पुलिए को जो ट्रेनिग दी जाती है, उस ट्रेनिग के दौरान उनका अच्छा आचरण बनाया जाए ताकि समजा की सुरक्षा मेनटेन्ड रह सकें।

स्पीकर साहब, आगे डिमांड नं0 8 पर कहना चाहता हूँ। यह डिमांड बिल्डिंग्ज एंड रोडज की है। रोडज का यह हाल है कि हमारे यहां पर कोई भी रोड ठीक नहीं हैं सारी सड़कों में गद्दे पड़े हुए हैं सारी सड़के बरबाद हैं और सारी टूटी-फूटी पड़ी है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जितना पैसा ऐजिग के लिए खर्च किया जा रहा है, उस को बजाये सड़कों को चौड़ा करने पर खर्च किया जाये तो ठीक रहेगा। आज यह हो रहा है जो 8, 10 या 12 फुट की सड़कों को थोड़ा वाइडन कर दिया जाये तो ठीक रहेगा। सड़कों के टूटने का एक ही कारण है। हर गांव में, हर टाउन में या हर भाहर में जहां जहां पानी खड़ा रहता है, वहां से रोडज टूट जाती है। हमारे यहां पर कोसली में भी खड़े पानी की दिक्कत हैं हो सकता है दूसरी जगहों पर भी ऐसी ही दिक्कत होगी। रोड के साथ-साथ पानी के लिए चैनलज बननी जरूरी है ताकि पानी रोडज पर जाने की बजाये, उन चैनलज में से गुजर सके। इस समय सिस्टम यह है कि गांव की सड़कें तो पंचायत बनायेगी ताथ भाहर की सड़के म्यूनिसिपल कमेट्टी बनायेगी ओर दूसरा डिपार्टमेंट चैनलज बनायेगा यानी पी डब्ल्यू0 डी0 (पब्लिक हैल्थ) का को चैनलज बनाने का काम दिया हुआ है। मेरा कहना यह है क वह एक ही किस्म का काम हैं रोडज को बनाने ओर उनकों बरबाद

होने से बचाने के लिए इस काम को एक ही डिमाटमेंट को देना चाहिए।

अब डिमांड नं 10 के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। यह डिमांड मैडीकल एंड पब्लिक हैल्थ के बारे में है। आप किसी भी होस्पिटल में चले जाइए, वहां पर दवाईया नहीं है, डाक्टरज नहीं हैं पिछले दिनों मेरे हल्के के गांव जमलपुर में, मुख्य मंत्री, सी० एच० सी० की ओपनिंग सैरेमनी के लिए गये थे। वहां पर केवल एक डाक्टर एक कम्पाउंडर ओर 16 चपड़ासी हैं आप ही देखे, क्लास-फोर के 16 आदमी है और डाक्टर केवल एक है। मेरा कहना यह है कि वहां पर आप डाक्टरज की संख्या को बढ़ाये। इस तरह से से न करें कि चपड़ासी तो 16 लगा दे ओर डाक्टर केवल एक ही हो। वहां पर आप दवाईयों ज्यादा दें और अच्छी क्वालिटी की दवाईया भेजे। इतने ज्यादा चपड़ासी भर्ती करने का कोई फायदा नहीं है। आज भी उस सी० एच० सवी० के अन्दर कोई डाक्टर नहीं हैं तरख्वाह तो उस डाक्टर की जमालपुर के बजट से ली जाती है लेकिन वह काम कही ओर जगह करता है। मेरा सरकार से अनरोध है कि एक तो आप अच्छी दवाईयां दे, और दूसरे जो वहां का डाक्टर आन डैपुटे इन वही दूसरी जगह पर काम कर रहा है, उससे वही पर रखा जाए। किसी दूसरी जगह नहीं जाना चहाए। पब्लिक हैल्थ कि जहां तक ताल्लुक है, मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं। आज सरकार दावा तो करती है कि उसने 6739 गांवों को पीने का पानी दे दिया है, मगर इन

गांवों में से केवल 10 फीसदी लोग ही ऐसे होंगे जहां पर वाटर सपलाई के हैड है और वहां के लोग ही आपका पानी पीते होंगे। 10-20 फीसदी गांवों में ही पानी ठीक जाता होगा, लेकिन सब जगह नहीं। इल्लीगल कुनैव ान्ज बहुत ज्यादा है जिनके कारण पानी टेल तक जाता ही नहीं हैं हमारे यहां पर 1960-1962 से वाटर सपलाई की स्कीम बनी हुई। आज आबादी 15000 के करीब पहुंच चुकी है ओर वाटर पाईप लाइन्ज बड़ी पुरानी पड़ी हुई थी। उन पाईप्स को बदला गया है ओर जो पुरानी पाईप्स निकाली गयी है, वह बेकार पड़ी हुई हैं पानी को कैपेसिटी बढ़ाने के कारण जो पाईप लाइन्ज उखाड़ी गयी है ओर बेकार पड़ी हुई है, उसका किसी दूसरी जगह पर प्रयोग किया जा सकता हैं वह लोहे की पाईप्स है, मेरा विचार यह है कि उनको दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह से जो पाईप्स उखाड़ी गयी है उनको बरबाद न करके कुनै ान देने के लिए या कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमल किया जाये। अगर ओर कुछ नहीं कर सकते तो इन पाईप्स को नीलाम कर दिया जाए। जो पैसा वसूल होगा, उसके उस जगह की बहूबदी के लिए लगाया जाए।

एक आवाज: कहां की पाईप्ज की बात कर रहे हो?

चौधरी जिले सिंह जाखड़ा: मेरे इलाके कोसली में एक नंगल खेड़ा की स्कीम है, वह कम से कम 85 गांव की स्कीम है। उसमें से, कम से कम 20 गांवों की स्कीम में से, लोहे की पाईप उखाड़ी गयी है जो बेकार पडती हुई है। उन लोहे की पाईप्स को

किसी दूसरी जगह प इस्तेमाल किया जा सकता हैं यह मेरा सुझाव है। इसके अलावा, सरकार की एक और स्कीम है जिन गांवों में मीठा पानी नहीं है, उन गांवों के जोहड़ों की खुदाई के लिए सरकार 80000 रूपया देती है ताकि पीने का पानी मिल सके। मेरे हल्के में एक खीरड़ा गांव है। वहां पर 5 एकड़ का जोहड़ है वह तो बरसात के दिनोंमें भरता नहीं है लेकिन तीन जोहड़ और खोदने के लिए 80000 रूपये के हिसाब से दिए गए हैं मातनहेल ब्लॉक में पैसे का बहुत ज्यादा मिसरूटीलाइजे शन हुआ है। अस्सी अस्सी हजार के इतने जोहड़ खोद दिए और वह सारा रूपया बरबाद होगया। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह हाउस की एक कमेटी बनाए और वह केटी वहा जकार देखे कि वे जोहड़ वहां जरूरी भी थे या नहीं थे। अगर उस पैसे को ठीक ढंग से ययूटीलाइज करते तो वह पैसा किसी ओर काम ा सकाता था। जोहड़ खोदने की क्या जयश्रत थीत्र? जब पांच एकड़ का एक जोहड़ बरसात के पानी से नहीं भरता तो तीन और जोहड़ खोदने का क्या फायदा है और वे क्यों खोदे गए? तब पानी का कोई साधन नहीं है बरसात का पानी वहां बढ़ जाएगा और प ुओं को दो महीने पीने का पानी नहीं मिलेगा इसलिए इस तरह की फिजूलखर्ची का रोक जाए।

स्पीकर साहब, इन डिमाण्डज में एजूके शन के लिए पैसा रखा गया है मुख्य मंत्री जी कहते है कि हमारे यहां शिक्षा का बहुत विस्तार हुआ है। हमारे यहां 55.85 परसेन्ट लोग पढ़े

लिखे है ओर पंजाब के अन्दर 58 परसैन्ट समथिंग पढ़े लिखे लोग है। स्पीकर साहब, ऐजूके इन का बजट बढ़ाकर हम टीचर्ज ट्रेनिंग स्कूलों की संख्या बढ़ाई जा सकती है स्पीकर साहब, आज टीचर्ज की जो ट्रांसफर पोलिसी एक समस्या बनी हुई है भाहर के जे0 बी0 टी0 टीचर्ज आज किसी दूसरे जगह नहीं रहना चाहते। उनका कही और ट्रांसफर हो जाता है तो वे वहां नहीं जाते। एक महीने में एक दिन हाजिरी लगा देते है ओर तरख्वाह ले लेते हैं और हजारों लोग सैक्रिटेरिएट में चक्कर काटते रहते है। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए बेहतर तरीका यह है कि हम ट्रांसफर पौलिसी बना लें उसी पौलिसी के तहत हम उनका ट्रांसफर करें हम ट्रांसफर पोलिसी ऐसी बना ले कि पांच साल तक ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसा करने से हमारी सरदर्दी काफी कम हो जाएगी। आज भाहर के आसपास के जो टीचर्ज है वे दूर गांवों से जाना नहीं चाहते। अगर उनका ट्रांसफर हो जाता है तो वे वहां नहीं जाते, इससे बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ता है। सरकार हर टीचर से पूछ ले कि वह कहा रहना चाहता है। ओर उसकी मर्जी के मुताबिक उसका ट्रांसफर कर दिया जाए लेकिन उसके पांच साल क बाद तक कोई ट्रांसफर न किया जाए। शिक्षा स्तर सुधारने का इससे बेहतर ओर कोई तरीका नहीं हो सकता। इससे टीचर्ज भी संतुष्ट रहेगे। स्पीकर साहब, डिमांड नं0 13 सो गल वैलफेयर की है। सो गल वैलफेयर के अन्दर समाज कल्याण आता है। समाज कल्याण का मतलब है कि हम अपने समाज का कल्याण करे। स्पीकर साहब, आज हम अपने समाज का कल्याण नहीं रहे है।

आज आंगनवाड़ी में लाखों बच्चों को खिचड़ी खिलाने के लिए, दलिया खिलाने के लिए छोटे-छोटे बच्चों से अपने-अपने घरों से कटोरे मंगवाए जाते हैं। स्पीकर साहब, उनको खिचड़ी देना, भूगड़े देना, दलिया देना, और गुड देना क्या यह कोई समाज कल्याण की स्कीम है?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव):

स्पीकर साहब, यह कह रहे हैं कि आंगनवाड़ी में खिचड़ी बनती है। हमारे अब आंगनवाड़ियों के लिए नई पौलिसी निकाली है। हमने अुकेर नाम की कि किताब निकाली है। यह किताब नर्सरी ट्रेनिंग के बारे में है बच्चों को हम ट्रेनिंग दे है। यह गलत कह रहे हैं कि आंगनवाड़ी में कोई काम नहीं होता।

चौधरी जिले सिंह जाखड़: मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि हाउस की एक कमेटी बनाकर उनका काम देख लिया जाए। हमारी पी० ए० सी० कमेटीने इनको देखने का प्रोग्राम बनया था लेकिन वह सिर नही चढत्रा। स्पीकर साहब, मेरा कहना यह है कि आप कुछ फैमिलीज फिक्स कर ले, कुछ मैफिलीज आइडैन्टीफाई कर लें, जिल फैमिलीज की ओर जिन बच्चों को अपने देना है, उनको आइडैन्टीफाई करें ओर उनको दे। मैं यह नही कहता कि आप न खिलाओं। सेंद्रल गवर्नमेंअ का न्यूट्री ान का प्रोग्रम है। उसो आप यूटीलाइज करों। लकिन अब हालत यह है कि उस मैटीरयल को कही भैस खा रही है या कोई कट्टी खा रही है। बच्चों को नही मिल रहा हैं कितना आताहै और कितना जाताहै,

इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, आप फिक्स कदो दें कि एक परिवार के बच्चे को पास ग्राम मिलेगा, सौ ग्राम मिलेगा या दो सौ ग्राम मिलेगा या दस ग्राम मिलेगा जिससे कि उनका कुछ भला हो सके।

स्पीकर साहब, अब मैं डिमांड नं 15 जो इरीगे इन की है, के बारे में कहना चाहता हूं। इरीगे इन के लिए मैं गुप्ता जी को कहूंगा कि इस मद में बहुत ज्यादा पैस दिया जाए। यहां पर एस0 वाई0 एल0 के पानी के बारे में झगड़ा है कि 3800 लाख एकड़ फीट पानी नहीं मिल या 3500 लाख एकड़ फीट पानी नहीं मिला। मैं तो यह कहूंगा कि 3800 की बजाए अगर 3600 मिल जाए तक भी ले लो। पचास साल हो गए ओर हम पानी की वजह से बर्बाद हो रहे हैं। अगर अगले बीस साल भी पानी नहीं मिला तो वह भी सारा चला जाएगा। झगड़ा करने के क्या फायदा है? फिजूल में लटठम लट्ठा हो रहा है। हमारे पास डब्ल्यू जे0 सी0 क जमुना का दो तिहाई पानी हैं हम उसको यूटीलाइज नहीं कर रहे हैं। और एस0 वाई0 एल0 पर लट्ठ बजा रहे हैं। उसका क्या फायदा है? हथनी कुंउ बैराज बनाओं ताकि ताजेवाला हैड का पानी मिल सके। दक्षिणी हरियाणा में बरसात में एक लाख एकड़ फीट पानी होता है ओर उससे से पचास हजार या अस्सी हजार एकड़ फीट पानी बेस्ट चला जाता है। यह बात मंत्री जी ने मानी है। उस पानी का यूज करने के लिए नहरों को डिसिलिटिंग कराकर दक्षिणी हरियाणा के जिलों को भेज दिया जाए ता कम से

कम वाटर रिचार्ज होकर पानी तो आ जाएगा। हमारे ट्यूबवैल्ज तो चल पड़ेगे। अगर सरकार इन स्कीमों में भी पैसा नहीं लगाएगी तो कहां लगाएगी? जब बरसात के दिनों में आपके पास पानी स्पेयर होगा तो जरूरत के दिनों में आप उस पानी को दे सकते हैं। स्पीकर सहाब, एस0 आई0 टी0 सी0 और काढ़ा के अन्दर जो आप वाटर कोसिज बनाते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज हमारे वाटर कोसिज जितने भी हैं वे बकार पडत्रे हैं उनके बनने के बाद से आत के एक घूंट भी पानी उसमें नहीं चला है। बीस-बीस किलोमीटर लम्बे वाटर कोसिज बने पड़े हैं जिनसे एक घूंट भी नहीं चल रहा है। आप सर्वे करकार देख ले कि इन वाटर कोसिज में पानी पहुंच है या नहीं पहुंचा है अगर कोई वाटर कोर्स पांच किलोमीटर लम्बा है तथा वह टूट गया और सरकार के पास उस पर लगाने के लिए पैसा नहीं है तो उसका क्या फायदा है? इसलिए रिपेयर के लिए भी सरकार पैसा दे। रिपेयर के लिए कौन बैनीफि गायरी पैसा देगा और कौन पैसा इक्ठठा करेगा और कौन उसको बनाएगा। कौन उसकी रिपेयर करेगा? इसलिए बजट में इसकी रिपेयर के लिए पैसे का प्रावधान किया जाना चाहिए।

इससे आगे मैं इरीगे गन विभाग का भी कुछ जिकर करना चाहूंगा, इस में ड्रेनेज डिवीजन भी आता है। उसमें डीजर ट्रेक्टर क्रेनज वगैरह और दूसरी तरह की बहुत सारी मं गिनरी होती है जो यों ही पड़ी बरबाद हो रही है। 10-15 साल पहले हमारी साहलावास की ड्रेन बनी थी, पता नहीं वहां पर कितना

लोहा यंही बेकार पड़ा हुआ है। कोई उसकी सुध बुध नहीं लेता। मैं सरकार से कहूंगा कि अगर वह वेस्ट मैटीरिय, उससे कोई यूटीलाईजे इन नहीं है, उनको अगर कंडमंड कराब दे दिया गया है तो उसकी जल्दी से जल्दी नीलामी करवा दी जाए। और इन से जो पैसा सरकार को मिले, उसको दूसरे कामों पर लगाये। पी0 ए0 सी0 कमेटी का मैम्बर होते हुए हमने इस मुद्दे को एग्जामिन किया था लेकिन यह बात नहीं बनी। हमें बताया गया कि इसके लिए काफी समय लगा जाता है। हमें समझ नहीं आता कि कोई चीज जो किसी काम की काम नहीं है, उसकी डिवोजल में दो-दो, तीन-तीन महीने का समय कैसे लग जाता है?

श्री अध्यक्ष: आपका समय समाप्त हो गया है। जिले सिंह जी। अब आप बैठें।

चौधरी जिले सिंह जांखड़: सर, मैं एक दो मिनट में अपनी बातें कह कर समाप्त करूंगा। मैं कह रहा था कि जो सामान वेस्ट हाता है, यूटीलाईज नहीं हो पाता, कंडम होता है, चाहे जीपे हो, ट्रैक्टर हो, उनकी जल्दी ही आव इन करवा दी जानी चाहिए ताकि उन से जो पैसा आए, उसका कहीं ओर सदुपयोग किया जा सकते। अगर उन चीजों को समय पर कंडम करके आव इन कर देगे तो सही कीमत मिलेगी और अगर देर से आव इन की जाएगी तो पैसा कम मिलेगा। इसलिए सरकार इस ओर विशेष ध्यान देवे।

इससे आगे में डिमांड नं० 17 के बारे में बोलना चाहूंगा। इरीगे 1न में जो हमारी जमीन खराब हो रही है, उसकसी ओर सरकार ध्यान दे। जैसे जेहलम, डब्ल्यू० जे० सी० और जे० एस० पी० के साथ जो पैरेलल जमीन पड़ी है, वह बर्बाद हो हरी है ऐसी जमीन लगभग 50-60 हजार एकड़ के करीब होगी, सरकार को ऐी जमीन को जल्दी ही ठीक करवाना चाहिए। इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। और सरकारका भी हो रहा है। रोहतक, रिवाड़ी और महेन्द्रगढ़ की जो जमीन है, टीले पडत्रे हुए है, उनकी सरकार को लैवलिंग करनी चाहिए जहां पर न बरसात का पानी है और न ही ट्यूबवैल्ज का पानी है, उसकी लैवलिंग करवायी जाए ताकि किसानों को और ज्यादा जमीन जोतने के लिए मिल सकें।

इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात ओ कहूंगा जहां तक स्टाफ का संबंध है। जैसे एस० डी० ओज० है, सर्किल आफिसर्ज हे, इंस्पैक्टर्ज है उनको साल के 265 दिनों में एक घण्टा भी काम नहीं है ये सारे कोई कहीं बैठता है, कोई गांव में बैठता है, कोई हैड क्वार्टर में बैठता है अगर ये कोई काम करते है हो, किसी किसान के खेत में कभी गयी हो, उनको कुछ बताय हो, या किसी को कुछ नालिज हो तो सरकार बताए ऐसी बात नहीं हैं बस महीन में एक दिन आए, टिकट लगाई और तनख्वाह ले गये। इनकी कुछ चैकिंग सरकार द्वारा होनी चाहिए। अगर ये किसानों के पास जात हो तो उनको पता हो सकता है

कि खेती क्या होती है इनको किसानों को पूरी तरह से मदद देनी चाहिए कि फला खेती किस तरह से हो सकती है अगर फलां खेत में बीमारी पड़ जाए तो इसके लिए क्या करना होगा लेकिन जब स्वयं को ही कुछ पनता नह हो तो ये किसानों को क्या बतायंगा। इसलिए सरकार कारे इस ओर पूरा ध्यान देना चाहिए।

सरकार को इस तरफ का स्टाफ यूंही बैठक तनख्वाह ले रहा है इसलिए मेरी सरकार से गुजारि है कि इस सरप्लस स्टाफ को कही ओर जगह पर इस्तेमाल करें।

इससे आगे में माकिटींग बोर्ड का जिक्र करूंगा। इसमें मंडिया भी आत हैं सरकार नई मंडियों बनाने जा रही है मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे नई मंडिया बनाने की बजाए जो पहले ही पुरानी मंडिया अधूरी पडती हुई है, पहले उनका काम खत्म किया जाए, उनको पूरा किया जाए, फिर नई मंडियों को ओर धयन दिया जाए। इस तरह नई मंडियों की घोशणाए करने को कोई लाभ नहीं होगा, जब तक पुरानी मंडियों इंकपलीट पड़ी हो। मेरे कोसली हल्के में एक मंडी पिछले 10-15 सालों से अधूरी पड़ी है ओर उसके नजदीक आस पास कोई दूसरी मंडी भी नहीं है, वह बिल्कुल बेकार पड़ा है इसलिए सरकार जो नई मंडिया बना रही है उनकी तरफ ध्यान न देकर पहले पुरानी मंडियों को पूरा करने पर ध्यान दें।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कम्यूनिटी डिवैल्पमेंट विभाग का भी जिकर आया। मैं यकह कहूंगा कि सामूहिक विकास का जो पैसा सरकार लगा रही है, उसकस ठीक ढंग से यूटीलाईजे न नही हो रहा है। उस पैसे का फिजूल में बरबाद नही किया जाना चाहिए।

पहले मैंने यह जिकर किया था यूंही फिजूल में जोहड़ खोदे जा रहे है ओर वे ट्रैक्टर के द्वारा खोदे जा रहे है, फिर उनके मेनडोज बना दिए जाएंगे। सब से पहली उस इलाके की यह डिमांड है कि वहां पर हमारी बहन, बहू-बेटियों के लिएबुजुगों के लिए लैट्रीन बनाई जाएं इसलिए सरकार को मेरा सुझाव है कि सरकार इसके लिए एक या आधा एकड भूमि अर्जित करके, चार दीवारी बना दे, यहां सफी गिरेन्ट रहेगा ताकि लोगों को लैट्रीन वगैरह जाने के लिए कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। यूंही फिजूल कम्यूनिटी डिवैल्पमेंट के लिए पैसा लगाया जाए, यह कोई अच्छी बात नही है इसमें हम कामयाब नही है वाटर सप्लाई भी कोई नही है जिससे इन लैट्रीनज को पानी के साथ कनेक्ट कर दें। इसलिए सरकार गांव में रहने वाली हामरी बहन, बहू-बेटियों व बुजुगों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए चारदीवारी करवा दे ताकि लोगों को सुख-सुविधा हो सके। ऐसा काम सरकार को तुरन्त ही करना चाहिए। (धन्यवाद)

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल): स्पीकर साहब, मैं डिमांड नं0 2, 3, 8, 15, 17 और 22 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

स्पीकर साहब, सदन में इरीगे टन की डिमांड पर चर्चा की गई। मैं उस जगह से संबंध रखता हूँ, कई बार सदन में चर्चा हुई कि जिला फरीदाबाद को नहीर पानी देने के बारे में सरकार को बिल्कुल इरादा नहीं है। बार-बार हमारे उस जिले के दूसरे माननी सदस्यों ने भी सदन में चर्चा की है। जिला फरीदाबाद में जो आगरा नहर है, उसमें से हरियाणा को अपने हिस्से के तौर पर पानी मिलता है। आज उस नहर में पहले से ज्यादा पानी आता है। अगर हरियाणा सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से उसका कंट्रोल लेने के बारे में फिलहाज बात नहीं कर सकती है तो उस पानी का हिस्सा बढ़ाने की बात तो कर सकती है। अगर ऐसा हो जाए तो जो पानी बढ़ेगा, उसको गुडगांव कैनाल में डाल कर हमने सिर्फ फरीदाबाद जिले को बल्कि गुडगांव के मेवात के इलाके में भी पानी दे सकते हैं। जिला फरीदाबाद के जितने उद्योग और दिल्ली के उद्योग हैं तथा दिल्ली का जितना सीवरेज का गंद है, वह सारा आगरा और गुडगांव नहरों में चला जाता है। उस पानी से बहुत ज्यादा बदबू आती है। जहां जां से ये नहरे गुजरती हैं वहां पर बदबू के मारे लोगों को जीना दूभर हो जगया है। उस गन्दे पानी की वजह से लोगों का जीना दूभर हो गया है। उस गन्दे पानी की वजह से लोगों की सेहत पर असर पड़ा है। मैं चाहता हूँ कि इनका पर्यावरण महकमा उस गन्दे पानी को रोके। आज पर्यावरण के नाम पर सब से बड़ा मजाक है फरीदाबाद को केवल हरियाणा कह नहीं बल्कि नौथे इंडिया का उद्योग सैन्टर कहा जाता है। हरियाणा सरकार ने पर्यावरण अदालत बनाने का जिक्र किया यह

आदालाते एक हिसार मे, एक अम्बालजा में तथा एक और किसी जगह बनेगी। जबकि उस अदालत का हकदार फरीदाबाद जिले था क्योंकि उद्योगों की सब से ज्यादा गन्दगी फरीदाबाद में है। इसके अलावा हमारे पलवल के इलाके में सड़कों की बहुति बुरी हालत है। हम जहां भी बोलते हैं तो हमारे मंत्री ओर आदरणीय मुख्य मंत्री हमारे साथ इस तरह से पैदा आते हैं जैसे हरियाणा प्रदेश में इनका ही हक है, सदन में भी केवल इन्हीं का हक है, हमारा कोई हक नहीं है। हमें झूठा साबित करने की कोशिश की जाती है। चौधरी भजन लाल ने फरीदाबाद से एम0 पी0 इलैक्ट्रिकल लड़ा था। इन्होंने लोगों को कहा था कि अगर मैं सांसद बन गया तो मैं जिला फरीदाबाद को इंग्लैंड बना दूंगा। (विधन) आज हालत यह है कि प्रदेश में 110 ए0 एस0 आईज0 की भर्ती हुई। स्पीकर साहब, हमारे फरीदाबाद जिले के भायद ही किसी बच्चे का नाम उस लिस्ट में हो। प्रदेश में कोई भी नौकरी निकलती है तो उसके लिए या तो हिसार के लडत्रके लिए जाते हैं या कालका के लिए जाते हैं स्पीकर साहब, कोई भी स्कीम या तो कालका के लिए बनती है या हिसार के लिए बनती है। फरीदाबाद के लिए कुछ नहीं होता। हमारे मुख्य मंत्री जी को फरीदाबाद से 50 लाख रूपए महीने की कमाई है.....

चौधरी भजन लाल: क्या कहा अपने यह दोबारा बता दें।

श्री कर्ण सिंह दलाल: फरीदाबार में जो ट्रक यूनियन है, उसको मुख्य मंत्री ने अपनी कमाई का जरिया बनाया हुआ है। वहां के डी० सी० और एस० पी० को इन्होंने आदे 1 दे रखे हैं। कि चाहे जिला प्र पासन चले य न चले, मुख्य मंत्री को उस यूनियन से 50 लाख रुपये पहुंच जाने चाहिए। (गोर)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो बात कही है उससे धटिया बात कोई आदमी कह नहीं सकता सदन के मैम्बर को ठीक बात करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अगर ये इस बात को साबित कर देगे, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा या फिर ये अस्तिफा दे दे। जैसा इन्सान होता है वह वैसी ही बात करेगा। इनको इस तरह के बेहूदा एलीगे 1न लगाने का कोई लाईसैस नहीं मिला हुआ **

* * * यह कोई तरीका है। ऐसी गलत बात कहने को इनको कोई लाईसैस नहीं मिला हुआ है। (गोर)

चौधरी बंसी लाल: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने जो भाब्द कहे हैं वे रिकार्ड पर नहीं आने चाहिए। (गोर)

श्री अध्यक्ष: ठीक है वे भाब्द रिकार्ड पर न आएंगे। (गोर)

प्र० छतर सिंह चौहान: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने जिन भाब्दों का इस्तेमाल किया है, वे भाब्द मुख्य मंत्री जी को वापिस लेने चाहिए। (गोर)

श्री अध्यक्ष: उन भाब्डों को रिकार्ड से निकाल दिया गया है।

चौधरी जगदी ँ नेहरा: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। विधान सभा के माननीय सदस्यों को सदन में प्रवे ँ करते ही मसाने खम्बे पर बात लिखी हुई है उसकसे पढ़ लेना चाहिए। माननीय सदस्य दलाल साहिब बार-बार सदन में गलत बात कहते है। इनका यह कोई तरीका नही है। (ँोर)

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, आप बैठ जाए। (ँोर)

चौधरी जगदी ँ नेहरा: स्पीकर साहब, माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल ने जो राज्यपाल महोदय के बारे में कोई बात हुई थी, उस के बारे में आल सुबह मुख्य मंत्री जी से खिलाफ आपको एक प्रिविलेज मो ँन दिया था जबकि गवर्नर साहब के कंडक्ट के बारे में असैम्बली के अन्दर कोई डिस्क ँन नही हो सकती। जब उसब रे में दलाल साहब से एफेडेविट देने के लिए कहा गयातो मुकर गए। अगर ये सच्चे होते तो एफेडेविट देते। आप समझदार आदमी हो, विधायक हो और जिम्मेदार आदमी हो आप एफेडेविट देते। अगर आप सच्चे है तो एफेडेविट देते। आप अब भी एफेडेविट दे हम अब भी तैयार है। इसतरह से गलत बोलने से क्या फायदा। यह आपका कोई तरीका नही है कि हर टाईम गलत एलीगे ँन लगा दों। (ँोर)

श्री अध्यक्ष: आपको भी बोलने के लिए पांच मिनट का टाईम दिया जाएगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, हमारे जिले के लोगों के हाथ हर मामले में यह सरकार भद्दा मजाक कर रही है। हमारे वहां पलवल, बल्लभगढ़, होडल के लिए जो पहले आई० एस० बी० टी० से बसें चलती थी, वे अब बन्द कर दी गई हैं अब कोई कालेखा अड्डा बनाया गया है वहां से ये बसें चलती है, जो आई० एस० बी० टी० से 12 कि० मी० दूरी पर पड़ता है। जो सवारियों चण्डीगढ़, रोहतक या प्रदेश के दूसरे हिस्सों में जाना चाहती है, उनको आई० एस० बी० टी० से बसें पकड़ने के लिए काफी परेशानी होती है। मेरी सरकार से मांग है कि हमारे एरिया में जो बसें पहले आई० एस० बी० टी० के लिए चीती थी, अब भी वही से चलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मेरी दूसरी मांग है कि हमारे एरिया में बिजली के खम्भों की काफी कमी है। खम्भे न होने की वजह से बांस के डण्डों पर तारे नंगी लगी हुई है, उनके गिरने से कईबार जानवर और इन्सान के जीवन को खतरा बना रहता है। मेरा मांग है कि सरकार जल्दी से जल्दी बिजली के खम्भों को भिजवाने का प्रबन्ध करें।

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, अब आप बैठे। आपको पहले ही काफी समय मिल गया है। अब श्री राम रतन जी बोलेंगे।

श्री राम रतन (हसनपुर एस0सी0): स्पीकर सहाब, मैं आपके ध्यान में औरसदन के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि दलाल साहब इस्तीफ़े की बात कर रहे हैं मैं कहना चाहूँ कि पिछले सैंतान मैं। भी मैंने इस्तीफा दिया था। ये दलाल साहब जी हैं, ये पहले इस्तीफा दें। (गोर)

श्री अध्यक्ष: आप डिमांड पर बोलें।

श्री राम रतन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सेवा में अर्ज करना चाहता हूँ कि जब मैं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, तब से हरियाणा में काफी विकास का काम हुआ है। (विधन) अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं0 1 से 7 पर बोलना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जब से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी है, तबसे हरियाणा में विकास के काम हुए हैं। मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूँ कि हमारे जिला काफी पिछड़ा हुआ है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का टाइम 10 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: हाउस का समय 10 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1994-95 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान
(पुररारम्भ)

श्री राम रतन: अध्यक्ष महोदय दलाल साहब की दुकान मार्किट कमेटी, पलवल में हैं इनकी दुकान के बाहर दो पेड़ भी आम के खड़े थे जिनकी कीमत कम से कम 20 हजार रुपये होगी। उन दोनों पेड़ों को यह लोग काट कर ले गए थे और अब वहां भी आम के पेड़ नहीं है। (भाोर एवं विधन) स्पीकर साहब, अगर यह बात झूठी होती मैं सदन से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। चौधरी कर्ण सिंह जी भी इस्तीफा दे दें और मैं भी अपना इस्तीफा लिख कर आपको दे देता हूं। अगर मेरी बात झूठ हो तो मेरा इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए। (विधन एवं भाोर) अगर मेरी बात सच साबित हो जाए तो इनका इस्तीफा मंजूर कर लेना चाहिए। (विधन एवं भाोर)

श्री अध्यक्ष: भी आम के ये पेड़ कितना टाईम पहले काटे गए हैं? (विधन एवं भाोर)

श्री राम रतन: ये पेड़ करीब 2 महीने पहले ही कोट्ट एक है। पलवल में कालोनी के अन्दर इनकी कोठी बन रही है उन भी आम के पेड़ों को कोट कर ले गए हैं और उनसे वहां पर किवाड़ बनाए जा रहे हैं। (विधन एवं भाोर) अगर यह बात हो तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। (विधन एवं भाोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मेरी प्वायंट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राम रतन जी, आप बैठिए। कर्ण सिंह जी, आपका प्वायंट आफ आर्डर क्या है?

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, जो बात श्री रात रतन जी ने सदन में कही है, वह बिल्कुल बेबुनियाद ओर गलत है, मेरी कोई दुकान पलवल मार्किट कमेटी में मेरे नाम से नहीं है और न ही मैंने भी राम या कीकर का कोई पेड़ काटा है ये बेबुनियाद बात यहा पर कह रहे हे। (विधन) अध्यक्ष महोदय, मैं आपक माध्यम से श्रीमान जी से कहना चाहूंगा कि इस प्राकर का व्यवहार सदन की मर्यादा के खिलाफ है ये श्रीमान जी सदन मे किसी मिनिस्टर के माध्यम से या राम रतन जी के माध्यम से चाहे जाजे भी कहलवा ले, लेकिन ये मुझे बोलने से नहीं रोक सकते है। मैं अपनी बात कहूंगा और इनके इस प्रकार रोकने से नहीं रूकूंगा। (विधन एवं भाोर)

श्री राम रतन: स्पीकर साहब, मैंने भी राम के पेड़ का जिकर किया है, कीकर के पेड़ का मैंने नाम नहीं लिया। हो सकता है इन्होने कोई कीकर का पेड़ भी काटा हो लेकिन मैंने सिर्फ भी राम के पेड़ की ही बात कही है। (विधन एवं भाोर) भी राम के पेड़ इनके भाई ने काटे है, मार्किट कमेटी, पलवल के लोगों को

इस का पता है। स्पीकर साहब, आप हाउस की कमेटी बना कर सर्वे करवा लें। (विधन)

चौधरी बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, आनर्बल मैम्बर ने पर्सनल एक्सप्लेन इन के लिए काफी टाईम ले लिया है और टाईम काफी ज्यादा हो गया है हमने कट मो इन दिया है (गोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि कट मो इन पर बोलने के लिए में समय मिलेगा या नहीं?

श्री अध्यक्ष: डिमांड फार ग्रांट्स के लिए जितना टाईम ऐलोट होगा आपकी पार्टी के सदस्यों के हिसाब से आपको टाईम जरूर देगे। (विधन) जितना टाईम रूलिंग पार्टी को मिलना उतना उनको मिलेगा ओर पार्टी की रे गों के मुताबिक आपकी पार्टी को टाईम मिलेगा। (गोर एवं व्यवधान)

श्री राम रतन: अध्यक्ष महोदय, मैं तो डेढ़ लाख वोटो से चुन कर हाउस में आया हूँ ओर मुझे अपने बात कहने का अधिकार है, क्या आप मेरी बात नहीं सुनेगे? (गोर)

श्री अध्यक्ष: आप अपनी बात कहिए परन्तु अपनी बात मो बार—बार रिपोर्ट न करे।

श्री राम रतन: अध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूँ आज की सरकार ने शिक्षा में नवल रोकने के लिए काफी प्रयास किए है। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में दस जमा

दो के स्कूल नहीं है और जो है भी वह 15 किलोमीटर दूर है.....
.....

श्री अध्यक्ष: राम रतन जी, आपका टाईम हो गया है ,
अब आप बैठ जाए। बंसी लाल जी क्या आप बोलना चाहेंगे?

चौधरी बंसी लाल: जी हां।

वित्त मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, ये तो
बोल चुके हैं।

श्री अध्यक्ष: इन्होंने थोड़ा सा बोलना है आप पहले
इनको बोलने दें।

चौधरी बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं0 2, 3,
15, 17 और 24 पर बोलना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं
कहना चाहूंगा कि किसानों के लिए खेतों में जो दवाईया छिड़कने
के लिए मिलती है उन का कीड़ा पर कोई असर नहीं होता।
पिछले दिनों मैं सिरसा गयाथा, वहां पर मुझे लोगों ने बताया कि
कपास पर छिड़कने के लिए जो दवाई दी गई है वह बेकार है,
उसका कीड़ों पर कोई असर नहीं पड़ता। लोगों ने ककोरे में
दवाई डाल कर उसमें कीडने डाल दिया लेकिन वे कीड़े मरे नहीं,
बल्कि ऊपर तैरने लग पड़े। यह दवाई पानी की तरह है।

अध्यक्ष महोदय, जो सड़के अलग से माफिटिक बोर्ड
बनाता है, वह डुपलीकेट काम हो जात है। अध्यक्ष महोदय, पहले

भी यह होता था कि मार्किटिंग बोर्ड, पी० डब्ल्यू० डी० डिपार्टमेंट को काम दे देता था। मार्किटिंग बोर्ड वाले जो सड़के बनाते हैं, उनकी क्वालिटी ठीक नहीं होती, उनके पास टैक्नीकल नौ-हाऊ नहीं होते। मेरी सरकार को सुझाव है कि मार्किटिंग बोर्ड का पैसा पी० डब्ल्यू० डी० को दे दिया जाए जाकि अच्छी सड़के बने।

अध्यक्ष महोदय, अब गर्मी आ रही है। खासकर मेरे जिले में पानी की किल्लत होगी। इस तरह से रोहतक, सोनीपत, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, फरीदाबाद और गुड़गांव में पीने के भी पानी की किल्लत आएगी। क्या सरकार इसके लिए पहले से ही प्रबन्ध करेगी क्योंकि एक महीने के अन्दर अन्दर गर्मी आ रही है?

अध्यक्ष महोदय, जिला हिसार में फर्जी खाद सप्लाई हो रही है। यह खुद मुख्य मंत्री जी का जिला है। यह गोरखपुर गांव और भूना के इलाके मोजी, गैमउनपुर, और चौबारा में कई जगह पर खाद के नमूने किए गए थे लेकिन वह खाद गलत निकली थी और ठीक नहीं थी अगर ऐसी खाद किसानों को दी जाएगी तो किसानों का बहुत नुकसान होगा अध्यक्ष महोदय, मेरी इत्लाह के मुताबिक एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने अखबार में ब्यान दिया था कि दौ सौ से ज्यादा नमूने फेल हुए हैं

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं जे० एल० एन० के बारे में कहना चाहूंगा। जे० एल० एन० कैनल पर डिच ड्रेन जल्दी से जल्दी बनाए जाए। अगर यह नहीं बनाई गई तो सोनीपत और रोहतक

जिे के गांवों की हात बहुत खराब हो जाएगी क्योंकि इनके दोनों तरफ 4-5 एकडय जमीन में पटेरा खड़ा हो गया हैं ओर वह जमीन कल्लर बन गई है। इसलिए सरकार को डिच ड्रेन जल्दी से जल्दी बनानी चाहिए। जहां तक सिंचाई का ताल्लुक है, उइसके लिए किना पैसा खर्च करते है, इस बारे में कुछ पता नही है ओर न ही कुछ कहा जा सकता है। मै जगह जगह पर जाता हूं और पूछता हूं कि क्या नहरों की डी-सिल्टिंग हुई है तो किसी न भी यह नही कहा कि हां डी-सिल्टिंग हुई है। अध्यक्ष महोदय, नहरों की डीसिल्टिंग होनी चाहिए। आज पहले ही पानी की दिक्कत है। अगर टेल पर पानी नही पहुंचेगा तो बहुत नुक्सान हो जाएगा।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: अगर सदन की सहमति हो तो सदन का समस दस मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: सदन का समय दस मिनट और बढ़ाया जाता है।

**वर्ष 1994-95 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान
(पुररारम्भ)**

चौधरी बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मै यह भ कहना चाहूंगा कि जो राई के कम्पलैक्स के लिए पैसा रखा

गया है, वह बहुत ही कम है, ज्यादा पैसा रखना चाहिए ताकि इस कम्प्लैक्स को जल्दी से जल्दी डिवैल्प किया जा सकते। इसके साथ ही रोहतक के पास तो तलवार लेक है, वहां पर हर संडे को दिल्ली से लोग घूमने के लिए आते हैं, इसलिए इसको ऐक्सटैन्ड करना चाहिए। वहां पर मोटल भी बनाया जाए ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। ऐसा करने से सरकार को आमदनी भी होगी और स्टेट का नाम भी ऊंचा होगा। इसके अलावा, धारूहेड़ा कम्प्लेक्स में भी अकमोडे शज़न की कमी आ गयी है क्योंकि जयपुर आने जाने वालों का ट्रैफिक बहुत है इसलिए इस कम्प्लैक्स को भी बढ़ाना चाहिए इसके अलावा डैपेचिक जो होडल के पास है, बहुत अच्छा नहीं है, वहां भी अकमोडे शज़न की कमी है, इसलिए अकमोडे शज़न बढ़ायी जाए। रैस्टोरेन्ट की जगह पर पीने के पानी का प्रबन्ध बढ़िया किया जाए। आजकल लोग यू0 पी0 में चार पांच किलोमीटर की दूरी पर, कोसी में ठहर जाते हैं लेकिन हमारे यहां नहीं ठहरकरते, इसलिए सरकार को वहां पर भी अच्छा प्रबन्ध करना चाहिए। रिवाड़ी के टूरिस्ट कम्प्लेक्स में भी पीने के पानी का अच्छा प्रबन्ध होना चाहिए और ठकहरन के लिए ज्यादा से ज्यादा अकमोडे शज़न होनी चाहिए। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज यह है कि वहां पर जो तकिये मैटरसिज बैड भीट्स, बैड कवर्ज है, वे पुराने हो गये हैं अगर उनको हटाकर देखते हैं तो वे बिखरने लगते हैं, इसलिए सरकार उनको रिप्लेस करें। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि टूरिज्म के लिए 32000000 रूपया रखा है, यह

बहुत कम है। सरकार को कम से कम 15 करोड रूपये रखने चाहिए थे।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक बात जनरल ऐडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में कहना चाहूंगा। पुलिस को मोरल बहुत ही नीचा है क्योंकि डी० जी० पी० नीचे वाले स्टाफ की तकलीफों को ध्यान नहीं करता। पुलिस का ढांचा अच्छी तरह नहीं चल रहा है ला एण्ड आर्डर में गड़बड़ है। ला एण्ड आर्डर में गड़बड़ क्या है यह तो बिल्कुल है ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए कहूंगा कि जो डी० जी० पुलिस लगा हुआ है, वह कभी कभी पंचकुल रैस्ट हाउस में रहता है। लेकिन परमानेंटली दिल्ली में रहता है। कभी यह चण्डीगढ़ में या पंचकुला में रहता है, कभी दिल्ली में। उससे कहे कि या तो वह यहां का काम कर ले या दिल्ली का काम कर ले। इनको उसकी जगह पर किसी और अफसर को लगा देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट के व्हीकल्ज का भी बहुत मिसयूज होता है। चाहे सब्जी लानी हो चाहे कहीं और ले जाना हो, चाहे मुख्य मंत्री जी को कहीं जाना हो तो काफी गाड़िया उनके साथ चलती है तो मैं सरकार को इसके बारे में सलाह दूंगा कि ऐसी जगहों पर एक ही गाड़ी तीन चार अफसरों का लेकर जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक गाड़ी एक ही अफसर को लेकर जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, जो गुडगांव जिले में 80—90 एकड़ जमीन की चर्चा आज सुबह हुई है, अगर उस जमीन पर टूरिज्म कम्प्लैक्स बना दिया जाए, रेसकोर्स बना दिया जाए,

गोल्फ क्लब बना दिया जाए या टूरिज्म की कोई दूसरी चीज बना दी जाए तो मैं समझता हूँ यह बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि यह जगह दिल्ली के दरवाजे पर इन्दिरा गांधी ऐयरपोर्ट के साथ ही है। इससे सरकार को कम से कम बीस सा तीस करोड़ रुपये की कमाई हो सकती है। सरकार इस जमीन को चाहे ऐक्वायर करे या कुछ भी करे, लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट से वापस न ले। अगर वह जमीन वापस ले ली है तो उनको वापस देकर वहां पर टूरिज्म का कम्प्लैक्स डिवैल्प करें जिससे की स्टेट को फायदा हो सके ओर स्टेट का नाम ऊंचा हो सके। अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट की मीनिंग को मिसयूज तो बेहद ही है। एक एफ0 आई0 आर0 नं0 307, दिनांक 11.11.93 संगरिया मंडी में दर्ज हुई है वहां पर इसके लोग बूथ कैंपरिग करने गए थे लेकिन वे खुद ही कैप्चर हो गये। अध्यक्ष महोदय, यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो फरीदाबाद की खान है, अगर उन सबों ने एनेलाईज कर दें तो सरकार को ज्यादा फायदा होगा। आज उन खानों से नाजायज तौर पर पत्थर निकलाकर बेचा जाता है। जिसकी वजह से सरकार की आमदनी कम हुई है। और यह तो गुडगांव ओर फरीदाबाद जिले में, पंचायतों की, गांवों की जितनी जमीन नीलाम हुई है। उन सबकी सुप्रीम कोर्ट के सिटिब जज से इंकवायरी कराई जाए ताकि पता लग सके कि वह सारी जमीने नीलाम हुई है, उन सबकी सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जज से इंकवायरी कराई जाए ताकि पता लग सके कि वह सारी जमीनें ठीक नीलाम हुई है या नहीं? नीलामी की खबर अखबार में महीने सा दो महीने

में एकबात छपती है, लेकिन इसकी आवाज नहीं होती, किसी आफिसर के घर के ऊपर नीलामी हो जाती है इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इंकवायरी कराई जाए। आजकल बडत्री तेजी से एक धारा चल रही है, मुख्य मंत्री जी ने एक नयी प्रथा चलाई है कि मंत्रियों की कोरे भेज हो, एम0 एल0 ए0 को कारे भेज हो, तोहफे भेद हो। यह तो इस तरह का धन्धा चल रहा है यह ठीक नहीं है धक्के से चंदा वसूल होता है। 15-15 लाख, 20-20 लाख रूपए इकट्ठे किए जाते हैं। मैं उनके नाम नलेकर बदमगजी पैदा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि चंदा वसूल करने में सरकारी मीनरी का सिसयूज न किया जाए लेकिन मिसयूट होता है। अध्यक्ष महोदय, एक कमिशनर इन्होंने रोहतक में लगा रखा है वह चार सौ या पौने चार सौ रूपये में वी0 डी0 ओ0 के थू कैसिट और कितने बेचा तहै उसकी आप कनाट प्लैस में कोई दुकान खुलवा दो। वहां बेच लेगा। अध्यक्ष महोदय, ऐसी चीजों पर प्रतिबन्ध होना चाहिए। सरकारी मीनरी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा था ओरअब भी खुलासा तौर से कह देता हूँ कि मुख्य मंत्री जी के अपने भाहर में, 2 अक्टूबर, 93 को, महात्मा गांधी जी, की स्टैच्यू पर माला डालने गए भाराब बंदी आंदोलन के कार्यकर्ता भांति से अपना आंदोलन चला रहे थे। मुख्य मंत्री जी ने हिसार तो दरकिनारा, रोहतक तक गिरफ्तारियों करवा दी। इससे उनकी हिसार की फैक्टरी को तो कोई खतरा नहीं था। भाराब के खिलाफ आंदोलन का तो आपको भी समर्थन करना चाहिए था

अध्यक्ष महोदय बातें तो औरभ बहुत सारी कहनी लेकिन समय काध्यान रखते हुए मैं यही अपनी बात समाप्त करता हूँ। (धन्यवाद)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी ला ने डी० जी० पी० के बारे में कहा कि डी० जी० पी० रहते रैस्ट हाउस में है और घर दिल्ली में है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में उनके बच्चे पढ़ते हैं, आफिसर को दिक्कत हो सकती है जितन काबिल, जिना भानदार डी० जी० हरियाणा को है, उतना दे ा में किसी भी प्रदे ा का नहीं हैं ला एण्ड आर्डर जितना भानदार हरियाणा में है, उतना किस भी प्रदे ा में नहीं मिलेगा। (गोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, आप बैठ जाइए। कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं।

चौधरी भजन लाल: क्या आपके बारे में कुछ कहा है? डी० जी० पी० के बारे में कहा है अध्यक्ष महोदय, डी० जी० पी० के बारे में पिछली बार भी इन्होन कहलवाया, यह ठीक बात नहीं है अच्छे आफिसर की तारीफ करनी चाहिए। कोई गलत काम करते हो, बेईमान हो तो कहें, फिर हम भी मानेगे। (विधन)।

चौधरी बंसी लाल: मैं तो कहूंगा कि वह इनकंपिटेंट है।

चौधरी भजन लाल: आप के कहने न कहने से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आप चीफ मिनिस्टर थे तो आपका ओर मेरा एक ही जिला था आपने छांटकर बढ़िया एस० पी० हिसार में लगाया हुआ था। ये वही डी० जी० पी० हैं

चौधरी बंसी लाल: ये जरूरी तो नहीं कि जो आदमी आज से 15 साल पहले अच्छा था वह आज भी अच्छा हो?

चौधरी भजन लाल: एक अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कमिशनर का नाम लेकर यह कह दिया कि वह कैसेट बेचता हैं यह बिल्कुल सच्ची बात नहीं है वह कमिशनर इनके जिले का श्रीके० सी० भार्मा हैं वह बहुत ही बढ़िया गानदार और ईमानदार अफसर है। कोई इन्होंने उसको गलत काम कह दिया होगा, उसने किया नहीं होगा। चौधरी बंसी लाल का एक सुख है कि भोर एक मिनट लगता है लड़ने में। एक मिनट की भी टाल नहीं करता। यह इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। यह क्वालिटी भी किसी किसी आदमी में ही मिलेगी (हंसी) दूसरीबात अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह कह दी कि गवर्नमेंट में गिनरी का संगरिया में बहुत मिससूज किया गया। यह बात इन्होंने पहले भी कही है पता नहीं, इनको क्या फोबिया हो जाता है। ऐसी बात कहने का गवर्नमेंट में गिनरी मिससूज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: अभी फाईनैस मिनिस्टर साहब ने बोलना है इसलिए यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 10 मिनट के लिए ओर बढ़ा दिया जाए।

आवाजे: जी हां

श्री अध्यक्ष: बैठक का समय 10 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

**वर्ष 1994-95 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान
(पुनरारम्भ)**

मुख्यमन्त्री (चौधरी भजन लाल): मैं तो अध्यक्ष महोदय, केवल दो मिनट में ही खत्म कर दूंगा। बाकी तो गुप्ता जी ने 10 मिनट के बोलना है, वे आपसे बात करेंगे। आप जानते हैं, कोई भी अधिकारी इलैव इन के दौरान छुट्टी ले कर जा सकता है। राजस्थान ओर हरियाणा के लोगों का आपस में मेल जोल है रि तदारिया है। हम उनकी मदद के लिए जाते हैं ओर वह हमारी मदद के लिए आते हैं। लेकिन सरकारी मीनिरी का मिसयूज कहना कोई मुनासिब बात नहीं है एक बात इन्होंने फरीदाबाद की खानों के बारे में कही है। पहले वहां से इन्कम 9 करोड़ रुपये की थी लेकिन अब इन्कम 16 करोड़ से भी ऊपर हो रही है इसलिए कोई गड़बड़ का सवाल ही पैदा नहीं होता।

चौधरी बंसी लाल: इनको नैनेलाईज कर दो।
नैनेलाईज कर दोगे तो इन्कम 50 करोड़ होगी।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हमने नैनेलाईज करके भी देख लिया हैं एक बात इन्होंने पंचायत की जमीन के बारे में कही है कि नीलामी ठीक नहीं हुई या उसमें कुछ कमी रही है। पंचायत प्रस्ताव पास करने के बाद ही बाकायदा ओपन आक्टिन से जमीन को नीलाम करती हैं जब भूखी कोई आक्टिन पंचायत की जमीन की होती है तो सारी पंचायत से प्रस्ताव पास होता है तब वह नीलामी होती है। जब वह नीलामी छूटती है तो अगर अच्छा भाव होता है तो उस जमीन को पंचायत बेच सकती है, वरना वह टाल भी कर सकती है वरना वह टाल भी कर सकती है। कोई प्राइवैअ आदमी जब अपनी जमीन बेचता है ओर अगर उसका कोई दूसरा आमदी लेना चाहते ता सरकार उसमें क्या दखल दे सकती है? इसी तरह से पंचायत अगर कोई जमीन बेचनाचाहे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं त्र इसी तरह से पंचायत अगर कोई जमीन बेचना चाहे तो इसमें हम क्या कर सकते है। अगर ओपन आक्टिन मे पंचायती जमीन आक्टिन न हुई हो ता बातये। हां, अगर कोई िाकायत हो तो ये लिख कर भेज दें, हम उसकी जांच करवा सकते है। एक बात इन्होंने यह कही कि मत्रियों को एम0 एल0 एज0 को कारें दी जाती है। अगर किसी हल्के के लोग उनके भले काम के लिए ऐसा करते है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? यह प्रथा तो चौधरी बंसी लाल न ही डाली हुई है। इनके खुद के जमाने में स्टेज पर एम0 एल0एज0 को कारें भेट की जाती थी इसके लिए सरकारी मीनरी चन्दा

इक्ठठा करती थी (व्यवधान भाोर) मैने यह कहा है कि आपके जमाने में तो एम0 एल0 ए0 को कार स्टेज पर भेंट होती थी।

चौधरी बसी लाल: कब हुई है, यह भी जारा बात दो?

चौधरी भजन लाल: वह भी हम आपका बता देंगे। एक बात ओर होती थी सरकारी म गिनरी की बाकयदा डियूटी लगती थी। जो जलसे होते थे, उनमें पटवारी से लेकर डिप्टी कमि गनर तक ओर एक सिपाही से लेकर एम0 पी0 तक की डियूटी लगती थी। लकिन हमने किसी भी आदमी हो डियूटी नहीं लगायी है। हमारे जलसों में तो आदमी अपने आप ट्रैक्टरों में, बसों में या पैदल चल कर आते हैं। इसलिए किसी भी सरकारी म गिनरी का दुरुपयोग करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।

चौधरी बंसी लाल: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। मुख्य मंत्री जी मेरे ऊपर एक इल्माज यह लगाया थी कि यू0 पी0 में सरकारी म गिनरी लगाकर मैने जलसे किए थें यह आरोप निराधार और बेबुनियाद है।

चौधरी भजन लाल: मेने तो यू0 पी का नाम नहीं लिया है, मैने तो हरियाणा का नाम लिया है। हरियाणा ही आपको लिए फालतू पड़ता है।

चौधरी बंसी लाल: मैने कभी हरियाणा में भी सरकारी म गिनरी का दुरुपयोग नहीं किया। यह तो अध्यक्ष महोदय, पिछले दो तीन दिनों से आप भी देख रहे होंगे ओर आप ने अखबारों में

पढ़ा होगा कि बसों में काली पैंट पहनकर जो जाते थे या काली चुन्निया ओड़ कर जाती थी या काली जुराबें पहन कर नहीं जाते थे, उनको बसों से उतरवा देते थे। कोई भी आदमी काला कपड़ा पहन कर नहीं चल सकता इनके जलसों में काला कपड़ा पहन कर कोई आज सकता है

चौधरी भजन लाल: ये तो हम को ऐसा ही समझते है। ये आप करते थे, वैसा ही सोचते है कि भजन लाल भी करता होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मै आपकी तरह से नहीं करता। डाक्टर मंग सैन जी की पार्टी का मैम्बर सहां पर बैठा नहीं है। वे बड़े ही सीनियर लीडर थे। लेकिन उस आदमी को इन्होंने बोरी में बन्द करके पिटवाया था चौधरी बंसी लाल जी आप अपने पर्चे उखडवाना क्यो चाहते हो।

चौधरी बंसी लाल: आन ए प्वायंट आफ पर्सनल एक्सीप्लेने इन सर। यह बेबुनियाद इल्जाम हैं मुख्य मंत्री को सच बोलना तो आता ही नहीं है। इनकी मजबूरी भी है, इनको सच बोलाना तो आता ही नहीं हैं

चौधरी भजन लाल: चलो स्पीकर साहब, मै बात को यही खत्म करता हूं।

वैयक्तिक स्पटीकरण

श्री धर्मपाल द्वारा—

श्री धर्मपाल सिंह: आन ए प्वायंट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन। अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी श्री छतर सिंह चौहान ने कहा कि दादरी में अधिकारियों ने जलसे के लिए चन्दा इकट्ठा करके दिया ओर गाड़ी दी, यह बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं और गलत बातें हैं किसी भी अधिकारी को मैंने चन्दे के लिए लिए नहीं कहा और न ही किसी व्यापारी को कहा। यहां तक की मैंने किसी को टेलीफोन पर भी किसी तरह के चन्दे के लिए नहीं कहा। मैंने इस बारे में कोई बात तक नहीं की है। अगर कोई इस बात को साबित कर दे तो मैं बड़ी से बड़ी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। अगर यह बात साहित हो जाए तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं माननीय सदस्य ने जो इस तरह का ऐलीगेशन लगाया है। यह बिल्कुल बेबुनियाद ओर निराधार है। इनका यह कहना कि दादरी के जलसे में पुलिस ले लोगों को पीटा या काले कपड़े उतरवस। यह बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये लोगे वह भी कहते थे कि विधायक धर्मपाल को गांव के लोग घुसने नहीं देते ओर जलसे में एक भी आदमी नहीं आएगा जबकि छः तारीख को जलसे में ये हालत थी कि मुख्य मंत्री के सम्मान में जनसभा में इने लोग आए। उस दिन इतने लोग जलसे में आए कि इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई मैं इनके बारे में सारी बातें कहना नहीं चाहता क्योंकि लोग कहेगे कि तक इनका गुणगान करता था और आज इनके खिलाफ बोलता है। स्पीकर साहब, हमने खुद चन्दा इकट्ठा करके इनको कारें भेंट की थी। करण सिंह ने चन्द्रा इकट्ठा करके इनको कार भेंट की थी लेकिन

आज से यारी बातों के लिए इन्कार कहे रहे है। स्पीकर साहब, इन्होंने जो आरोप लगाए है वे बेबुनियाद और गलत है।

वर्ष 1994 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

वित्त मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से हमने आज हाउस में वर्ष 1994-95 की अनुदान मांगों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लेते हुए अपने अपने हल्के की दिक्कतों ओर िकायतों के बारे में विस्तार से चर्चा की। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बनते ही मुख्य मंत्री जी ने सबसे से पहले फैसला लिया कि प्रदेश के भ्रान्ति के साथ विकास होगा। स्पीकर साहब, हमने यह सारा केवल कागज पर ही बुलन्द नहीं किया बल्कि इमकों वास्तविक रूप दिया। हमने हमें ही मुख्यमंत्री जी के इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बजट बनाते समय, इन बातों का ध्यान रखा है अध्यक्ष महोदय, आज आप देख रहे है कि जहां तक हरियाणा में भ्रान्ति का संबंध है, कानून और व्यवस्था का जो माहौल है वह बहुत ही अच्छा है। हरियाणा के हर एक आदमी का हमने पूरा ध्यान रखा है, चाहे वह भाहर का रहने वाला हो चाहे गांव का रहने वाला है किसी भी जाति है चाहे किसी भी धर्म का है, हमने सब की सेपटी के लिए और ला एण्ड आर्डर को मैनेटेन रखने के लिए बजट पैसा रखा है यही कारण है कि आज हरियाणा में गुण्डागर्दी नहीं कर सकता। हमने ला एण्ड आर्डर को

पूरी तरह से और अच्छी तरह से मैनटेन करने के लिए आपनी पुलिस की जो साधन उपलब्ध कराए है। उसके कारण आज कोई भी बदमाश आदमी बच नहीं सकता उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही हो सकती है आज लोग हरियाणा के अन्दर अमन से रहते है। स्पीकर साहब, जहां तक विकास का ताल्लुक है। कि जिस प्रदेश में कितना विकास होगा, उतने ही लोग विकास के लिए ओर ज्यादा इच्छुक हो जाते है। यह एक स्वाभाविक बात है हमारे माननीय सदस्यों ने अपने हल्कों के लिए हरियाणा प्रदेश के लिए मांगों पर चर्चा की। अध्यक्ष महोदय, यहां पर स्कूलों के बारे में चर्चा की गई कि कि गांवों में स्कूलों की कमी है शिक्षा की तरफ सरकार ध्यान नहीं देती। स्कूलों में टीचर्स की कमी है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने स्कूल हमारी सरकार के आने के बाद अपग्रेड हुए है, इनकी सरकार चार साल रही, इनके चार साल में ही नहीं बल्कि मैं तो यहां तक कह सकता हूं, कि पिछले दस साल में भी इनके स्कूल अपग्रेड नहीं हुए। स्पीकर सर, यहां पर मेरे भाईयों ने बोलते हुए टीचर्स की बात भी कही कि टीचर्स की कमी है वाकई गांव के अन्दर टीचर्स की कमी रही थी। (ओर)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: मांगे राम जी मेरे विचार से 10 मिनट का समय सदन का ओर बढ़ा दे।

वित्त मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): ठीक है जी बढ़ा दे।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, सदन का समय 10 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

**वर्ष 1994-45 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान
(पुनरारम्भ)**

वित्त मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि स्कूलों में वाकई टीचर्स की कमी रही थी नफरी कम रही थी जिससे बच्चों की पढ़ाई में काफी नुकसान होता था। मैं इन भाईयों से पूछता हूँ कि जब इन भाईयों की सरकार थी तो इन्होंने अपने चार साल के कार्यकाल में कितने टीचर्स लगाये थे? चार साल के अर्से में इन्होंने स्कूल व कालेजों में ऐ भी पोस्ट नहीं दी थी। लेकिन हमने एक एक गांव की जरूरत को ध्यान में रखते हुए जितने पोस्टे खाली पडती थी, उनको भरा था और कालेजों में अब चार साल के बाद पहली बार हमने पोस्टें दी हैं

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ। कि जब स्कूल अपग्रेड होंगे तसे उसके साथ साथ टीचर्स की डिमांड बढ़ती ही जाएगी। इसलिए सरकार यह प्रयास करती रहती है ताकि स्कूलों में बच्चों की शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए बजट में ज्यादा से ज्यादा पैसे का प्रावधान किया जाए और बच्चों की पढ़ाई खराब न हो। सरकार पूरी तरह से जागरूक है कि हरियाणा का कोई भी बच्चा अनपढ़ न रहे जो व्यक्ति पहले अनपढ़ रह गया था साक्षरता

अभियान के तहत उसके लिए सरकार यह कोशिश कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा फण्डज की ऐलोकेशन करके अनपढ़ता को समाप्त किया जाए (तालिया)

इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, यहां पर हस्पतालों का जिकर भी आया। डाक्टरों का जिकर भी किया गया कि हस्पतालों में डाक्टर नहीं है। (गोर)

श्री अध्यक्ष: मांगे राम जी, आप यह बताएं कि देहातो में जो गर्ल्स कालेज खोले हुए हैं, उनको भी आप ग्रांट देगे या नहीं।

श्री मांगे राम गुप्ता: स्पीकर सर, भायर कहीं स्कूल खुलवाने का आपकी भी इच्छा है। इसके लिए आप बड़े ही भुभचिन्तक हैं। (गोर)

श्री अध्यक्ष: खुलवाने की इच्छा नहीं है, खुलवा लिए है।

श्री मांगे राम: अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि शिक्षा के लिए बजट में हम पैसे का पूरा प्रावधान करते हैं लेकिन जब हम बच्चों की शिक्षा देने की कोशिश करते हैं तो स्टूडेंट्स की नफरी बढ़ती ही रहती है हमारे शिक्षा मंत्री बता रहे थे कि हिन्दुस्तान में हरियाणा ही एक ऐसा प्रदेश है। जहां प्राइवेट स्कूल की शिक्षा के लिए अपने गांव से एक किलोमीटर तक, मिडिल स्कूल की शिक्षा के लिए दो ढाई किलोमीटर तक तथा हाई स्कूल की शिक्षा के लिए पांच

किलोमीटर तक बच्चों का जानापड़ता है। सभी माननीय सदस्यों को पता होगा कि जब हम लोग पही क्लास में अपने गांव से पढ़ने के लिए जाया करते थे तो हमें कम से कम दो किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता था। इस तरह इन हालात में स्कूलों और कालेजों के टीचर्स की मांग तो रहेगी ही। जब तक प्राइवेट लोग स्कूल और कालेज खोलने के प्रयास करते रहेगे और शिक्षा को बढ़ावा देने में सरकार को योगदान देते रहेगे तक तक शिक्षा को बढ़ावा मिलता ही रहेगा। यह अकेले सरकार के बस काम नहीं हैं जो प्राइवेट संस्थाएँ हैं, अगर वे अच्छा कालेज चलते हैं, अच्छा स्कूल चलाते हैं अच्छी ऐजक्यूटिव देते हैं, अच्छी मैनेजमेंट है तो उनको सरकार अपनी तरफ से पूरा-पूरा सहयोग देगी, प्रोत्साहन देगी, जितनी भी सरकार की तरह से सुविधाएं दी जा सकती होगी, वह सरकार उनको प्रोवाइड करेगी ताकि बच्चों की शिक्षा में किसी प्रकार का विधान न पड़ने पाये। अध्यक्ष महोदय, कालेजों में आज भी सरकार 95 प्रतिशत ग्रांट देती है। आप ही बताएँ कि इससे ज्यादा सरकार और क्या कर सकती है? इससे ज्यादा सरकार और क्या मदद कर सकती है।

श्री अध्यक्ष: मतलब क्या दोगे?

श्री मांगे राम गुप्ता: दे रखी है पुण्डरी से स्पीकर सर।

(गोर)

आवाजे: पुण्डरी के भी दोगे या नहीं। (गोर)

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, एक पुण्डरी के लिए ही नहीं सरकार तो सारे हरियाणा के लिए चिन्तित हैं सरकार की नीति के अनुसार पुण्डरी उसमें आता है, तो अब यह देगे। जो नीति में अगर पुण्डरी आएगा तो प्रायोरिटी हम देगे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।

इसके साथ साथ स्पीकर सर, मैं कहना चाहता हूँ कि आज जरूरत है सब से ज्यादा किसानों को पानी देने की और बिजली देने की। सरकार हमें 11 ही एग्रीकलचर सैक्टर को ज्यादा पैसा देने की कोशिश करती है लेकिन साधन सीमित होने के कारण सारा पैसा एक ही तरफ नहीं लगाया जा सकता, दूसरे कामों पर भी सरकार को नजर रखनी पड़ती है। इसलिए सरकार ने यह प्रयास किया है कि खेत क्यारी और किसानों के टेल तक पानी पहुंचाया जाए। इसके लिए सरकार ने पूरा पूरा प्रयास किया है। अभी बोलते हुए बंसी लाल जी ने कहा कि नहरों की, माईनर्ज की सिल्ट वगैरह, निकलवाने के लिए सरकार के पास कोई साधन है ही नहीं और न ही नहरों और माईनर्ज की सफाई का सरकार प्रयास ही कर रही है। मैं उनको यह बताना चाहता हूँ कि साधन न होते हुए भी सरकार ने वल्ड बैंक से इस काम के लिए 800 करोड़ रुपया मंजूर करवाए है। ताकि किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जा सके। अब नहरों में सिल्ट ही रहेगी और न ही माईनर्ज के कच्चे पक्के होने की शिकायत ही रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर भाहरों के बारे में भी चर्च हुई ओर कुछ टैक्स के बारे में भी चर्चा हुई। मैं बताना चाहता हूं कि भाहरों और गांवों को अलग नजर से देखने का पहली सरकार का ध्यान था, हमारा नहीं हैं पहली सरकार भाहर को एक नजर से देखती थी ओर गांव दूसरी नजर से देखती थीं हमारी सरकार इसमें फर्क नहीं रखती है। हम गरीब, किसान और हरिजन सभी का ध्यान रखते हैं हम हर वर्ग को सहूलियत देने की बात करते हैं। यहां पर सीवरेज के पानी का जिक्र अया कि पीने के पानी में मिलने की वजह से लोगों को पीलिएया हो गया। अध्यक्ष महोदय, आज जानते हैं कि म्यूनिसिपलट कमेटियों इतने साधन ही नहीं जुटा सकती थी इसलिए सरकार ने यह काम अपने हाथ में ले लिया। अब हरियाणा के किसी भाहर और गांव में, जहां सीवरेज सिस्टम है, इस तरह की कोई िाकायत नहीं आएगी। अब अगर कहीं भी पाईप लीक हो जाएगा तो उसका पूरा इन्तजाम करने के लिए हमने बजट में पैसा रखा है।

यहां पर सड़कों के बारे में भी िाकायत आई। अध्यक्ष महोदय, आप तो बहुत से प्रदेशों में घूमते हैं। आपको तो पता ही है ओर हम यह कह सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश की सड़कें आज देश में नम्बर एक पर हैं। हमें जो आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिए थे ओर अब दिए हैं, उसके अनुसार आप देख लें। आप सारे हरियाणा में देख लें कि कोई भी सड़क चाहे वह किसी देहात के कोने में लगती हो, वह टूटी हुई नहीं रहेगी। हमने तो एक मिसाल

आपके सामने पे 1 की हैं पहले किसी सरकार ने फोर लोन की तरफ ध्यान नहीं दिया था। अब दो महीने के अन्दर करनाल से दिल्ली तक फोर लेनिंग पूरी तैयार हो जाएगी। इन्होंने पता नहीं उस सड़क को क्यों रोक रखा था? इस बारे में पीछे मुख्य मंत्री जी ने बताया था। अध्यक्ष महोदय और कई बातों पर यहां चर्चा हुई। मैं किसी बात को रिपीट नहीं करूंगा। बहुत सी बातों का जवाब मुख्य मंत्री जी ने दे दिया है ओर कंसर्ड मिनिस्टर्ज ने भी दिया हैं जो बजट हमने पे 1 किया है, वह वक्त की मांग को देखते हुए पूरी बातों को कंसिडर करके पे 1 किया है। हम यह भी को 1 1 1 करेगे कि इसकासही प्रयोग हो। कही कोई मीनरी गलत चलेगी तो उसको रोकने की भी हम पूरी को 1 1 1 करेगे। अध्यक्ष महोदय, चूंकि आम पब्लिक ने इस बजट की सरहना की है इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको सर्वसम्मति से पास किया जाए। (धन्यवाद)

Mr. Speaker: Hon'ble Members now voting on demands on the Budget for the year 1994-95 will take place.

First, I will put the cut motion on the demands to the vote of the House and then I will put the demand to the vote of the House.

Demand No. 1

Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs. 27907000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that

will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 1-Vidhan Sabha.

The motion was carried.

Demand No. 2

Mr. Speaker: Now I put the cut motion on demand No. 2 given by Sarvshri Bansi La, Karan Singh Dalal, Chhattar Singh Chauhan and Smt. Janki Devi Mann to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 2 of Rs. 568399000 on account of General Administration be reduced by Rs. 1/-

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is —

That a sum not exceeding Rs. 555298000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 2-General Administration.

The motion was carried.

Demand No. 3

Mr. Speaker: Now I put the cut motion on Demand No. 3, given by Sarvshri Bansi Lal, Ram Bhajan , Karan Singh Dalal and Attar Singh, M.L.As. to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 3 of Rs. 2039319000 on account of Home be reduced by Rs. 1/-

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs. 1961064000 revenue expenditure and Rs. 45000000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No 3-Home.

The motion was carried.

Demand No. 4

Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs. 348568000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No 4-Revenue.

The motion was carried.

Demand No. 5

Mr. Speaker: Now I put cut motion on Demand No. 5 given by Sh. Ram Bhajan, M.L.A. to the vote of the House.

Question is—

That demand No. 5 of Rs. 145796000 on account of Excise & Taxation be reduced by Rs. 1/-

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs. 145786000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 5-Excise & Taxation.

The motion was carried.

Demand No. 6

Mr. Speaker: Now I put cut motion on Demand No. 6 given by Sh. Chhattar Singh Chauhan, , M.L.A. to the vote of the House.

Question is—

That demand No. 6 of Rs. 6748984000 on account of Finance be reduced by Rs. 1/-

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs. 1397909000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 6-Finacen.

The motion was carried.

Demand No. 7

Mr. Speaker: Now I put cut motion on Demand No. 7 given by Sh. Chhattar Singh Chauhan, , M.L.A. to the vote of the House.

Question is—

That demand No. 7 of Rs. 10615476000 on account of Other Administrative Services be reduced by Rs. 1/-

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs. 13612546000 revenue expenditure and Rs. 1050000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 7-Other Administrative Services.

The motion was carried.

Demand No. 8

Mr. Speaker: Now I put cut motion on Demand No. 8 given by Sh. Chhattar Singh Chauhan, Smt. Janki Dev and Karna Singh Dalal, M.L.A. to the vote of the House.

Question is—

That demand No. 8 of Rs. 10615476000 on account of Building & Roads be reduced by Rs. 1/-

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs. 861452000 revenue expenditure and Rs. 817760000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 8-Buildings & Roads.

The motion was carried.

Demand No. 9

Mr. Speaker: Now I put cut motion on Demand No. 9 given by Sh. Rsm Bhan, Smt. Janaki Devi, Chhattar Singh Chauhan and Sh. Attar Singh, M.L.A. to the vote of the House.

Question is—

That demand No. 9 of Rs. 5059663000 on account of Education be reduced by Rs. 1/-

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs. 5059658000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 9-Education.

The motion was carried.

Demand No. 10

Mr. Speaker: Now I put cut motion on Demand No. 10 given by Sh. Sh. Om Parkash Beri, M.L.A. to the vote of the House.

Question is—

That demand No. 10 of Rs. 3754769000 on account of Medical & Public Health be reduced by Rs. 1/-

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs. 3289457000 revenue expenditure and Rs.463800000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 10-Medical and Public Health

The motion was carried.

बैठक का समय बढ़ाना।

श्री अध्यक्ष: यदि सहमति हो तो हाउस को समय ओर 10 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजे: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: हाउस का समय 10 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

**वर्ष 1994-95 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान
(पुररारम्भ)**

Demand No. 11

Mr. Speaker: Now I put the cut motion on demand No. 11 given by Ram Bhajan, M.L.A., to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 11 of Rs. 138618000 on account of Urban Development be reduced by Rs. 1/-

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is —

That a sum not exceeding Rs. 138618000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 11-Urban Development

The motion was carried.

Demand No. 12 to 14

Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs. 299694000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 12-Labour & Employment.

That a sum not exceeding Rs. 1933426000 revenue expenditure and Rs. 35431000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 13-Social Welfare & Rehabilitation.

That a sum not exceeding Rs. 7.933600 revenue expenditure and Rs. 3444725000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 14-Food and Supplies.

The motion was carried.

Demand No. 15

Mr. Speaker: Now I put cut motion on Demand No. 15 given by Sh. Sarvshir Bansi Lal, Karan Singh Dalal and Chhattar Singh Chauhan, M.L.As. to the vote of the House.

Question is—

That demand No. 15 of Rs. 11305850000 on account of Irrigation be reduced by Rs. 1/-

The motion was lost.

Mr. Speaker: I also put cut motion given by Sh. Om Parkash Beri, M.L.A. to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 15 of Rs. 9961550000 on account of Irrigation Department be reduced by Rs. 1/-

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs. 9961550000 revenue expenditure and Rs. 1340700000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the

course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 15-Irrigation.

The motion was carried.

Demand No. 16

Mr. Speaker: Now I put cut motion on Demand No. 16 given by Sh. Bhajan Aggarwal, M.L.As. to the vote of the House.

Question is—

That demand No. 16 of Rs. 11305850000 on account of Irrigation be reduced by Rs. 1/-

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs. 301028000 revenue expenditure and Rs. 109711000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 16 Industries.

The motion was carried.

Demand No. 17

Mr. Speaker: Now I put the cut motion on demand No. 17 given by Sarvshri Bansilal, Karan Singh Dalal, and Om Parkash Beri, M.L.A., to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 17 of Rs. 1217897000 on account of Agriculture Department be reduced by Rs. 1/-

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is —

That a sum not exceeding Rs. 1216747000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 17-Agriculture.

The motion was carried.

Demand No. 18 to 21

Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs. 374000000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 18-Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 44911000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 19-Fisheries.

That a sum not exceeding Rs. 488070000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 20-Forest.

That a sum not exceeding Rs. 173290000 revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 21-Community Development.

The motion was carried.

Demand No. 22

Mr. Speaker: Now I put cut motion on Demand No. 22 given by Sh. Chhattar Singh Chauhan and Karan Singh Dalal, M.L.As. to the vote of the House.

Question is—

That demand No. 22 of Rs. 225573000 on account of Cooperation Department be reduced by Rs. 1/-

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs. 139454000 revenue expenditure and Rs. 86109000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 22-Cooperation.

The motion was carried.

Demand No. 23

Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs. 2548392000 revenue expenditure and Rs. 379300000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 23-Transport.

The motion was carried.

Demand No. 24

Mr. Speaker: Now I put cut motion on Demand No. 24 given by Sh. Bansi Lal, M.L.As. to the vote of the House.

Question is—

That demand No. 24 of Rs. 8136686000 on account of Tourism be reduced by Rs. 1/-

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs. 8502000 revenue expenditure and Rs. 26000000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 24-Tourism.

The motion was carried.

Demand No. 25

Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs. 3233897000 revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that

will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 25-Lowans & Advances by State Govt.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House stands adjourned till 9-30 A.M. tomorrow, the 16th March, 1994.

19:17 Hrs.

(The Sabah then adjourned for Wednesday, the 16th March, 1994).